भारत में आतंकवाद की चुनौतियाँ
:
समाधान का गांधीय परिप्रेक्ष्य

The Challenges of Terrorism in India : Gandhian Context to its Solution

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से पीएच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
2014

शोध निदेशक

डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी
असोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सवाईमाधोपुर (राजस्थान)

शोध छात्रा

संगीता जैन

APPENDIX - IX

CERTIFICATE BY SUPERVISOR

It is certified that the

1. Thesis entitled "भारत में आतंकवाद की चुनौतियाँ : समाधान का गांधीय परिप्रेक्ष्य" "The challenges of Terrorism in India : Gandhian Context to its Solution" submitted by SANGEETA JAIN is an original piece of research work carried out by the candidate under my supervision.

2. Literary presentation is satisfactory and the thesis is in a form of suitable for publication work.

3. Work evinces the capacity of the candidate for critical examination and independent judgement.

4. Candidate has put in atleast 200 days of attendance every year.

Signature of the Supervisor
With date

प्राक्कथन

भय व शोषण, युद्ध व आतंक के इस वर्तमान युग में जहां एक ओर आतंकवाद का विश्वव्यापी रूप में तब्दील हो जाना चिंताजनक पहलू है वहीं दूसरी ओर इस पर वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण एक प्रमुख चुनौती है। प्रस्तुत शोध प्रबंध ''भारत में आतंकवाद की चुनौतियाँ : समाधान का गांधीय परिप्रेक्ष्य'' के माध्यम से इसके विविध आयामों पर प्रकाश डालने का छोटा–सा प्रयास इसमें किया गया है।

प्रथम अध्याय 'परिचयात्मक' है जिसमें अध्ययन की प्रकृति, इसका उद्देश्य, उपलब्ध साहित्य की समीक्षा, अध्ययन की पद्धति आदि का समावेश किया गया है।

द्वितीय अध्याय 'आतंकवाद का निहितार्थ, विस्तार, इसके प्रमुख कारण व विश्व की प्रमुख आतंकवादी घटनायें, में आतंकवाद का अर्थ, इसकी परिभाषायें, विस्तार, इसके उदय के कारणों के साथ विश्व की प्रमुख आतंकवादी घटनाओं का आकलन किया गया है।

तृतीय अध्याय 'भारतीय संदर्भ में आतंकवाद के कारण, विभिन्न राज्यों में उत्पन्न आतंकवाद, नक्सलवादी आतंकवाद व इसके भारत पर पड़ने वाले

प्रभाव' में आतंकवाद के कारणों का विवेचन, विभिन्न राज्यों में उत्पन्न आतंकवाद व नक्सलवादी आतंकवाद का विश्लेषण, साथ ही इसके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय 'आतंकवाद के नियंत्रण व समाप्ति एवं देश की आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने हेतु सुझाव' में इसके नियंत्रण व सुरक्षा के प्रयत्नों पर प्रकाश डाला गया है।

पंचम अध्याय 'आतंकवाद की समाप्ति हेतु गांधीय विकल्पों का आकलन' में गांधीय विकल्पों पर प्रकाश डाला गया है।

शोधकर्ता के शोध विषय के पूर्ण होने में उसके अतिरिक्त उन सभी व्यक्तियों का जो तथ्यों से अवगत कराते हैं, का सहयोग होता है। अतः मैं उन सभी व्यक्तियों का आभार प्रकट करती हूँ। इस शोध कार्य में मुझे मेरे गुरू व निदेशक डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी से निरंतर प्रेरणा व प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा है। उनके कुशल निर्देशन व स्नेहपूर्ण प्रोत्साहन से ही यह कार्य संभव हुआ है। इस शोध कार्य में जिस तत्परता से उन्होंने सहायता की है, उसके लिये मैं उनकी आभारी हूँ। मैं शोध केंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई

माधोपुर के प्राचार्य महोदय के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती हूँ।

मेरे श्रद्धेय पिताजी एवं माताजी मेरे द्वारा किये गये शोध कार्य के प्रेरणा स्रोत रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं कुमारप्पा गांधी ग्राम स्वराज्य निधि, जयपुर, राधाकृष्णन पुस्तकालय, जयपुर के उन सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मुझे प्रस्तुत शोध प्रबंध हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई।

(संगीता जैन)
शोध छात्रा

अनुक्रमणिका

क्र सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	**प्रथम अध्याय** परिचयात्मक :– अध्ययन की प्रकृति, उद्देश्य, उपलब्ध साहित्य की समीक्षा, अध्ययन की पद्धति	1–33
2.	**द्वितीय अध्याय** आतंकवाद का निहितार्थ, विस्तार, प्रमुख कारण, विश्व की प्रमुख आतंकवादी घटनायें	34–73
3.	**तृतीय अध्याय** भारतीय संदर्भ में आतंकवाद के कारण, विभिन्न राज्यों में उत्पन्न आतंकवाद, नक्सलवादी आतंकवाद व भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभाव	74–101
4.	**चतुर्थ अध्याय** आतंकवाद के नियंत्रण व समाप्ति एवं देश की आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने हेतु सुझाव	102–120
5.	**पंचम अध्याय** आतंकवाद की समाप्ति हेतु गांधीय विकल्पों का आकलन	121–137
6.	**षष्टम अध्याय** निष्कर्ष एवं आत्मकथन	138–144
	संदर्भ ग्रंथ सूची	

प्रथम

अध्याय

परिचयात्मक

आज हम वैश्विक गतिशीलता के युग में रह रहे हैं। भौगोलिक सीमाओं का कोई अर्थ नहीं रह गया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने संपूर्ण विश्व को एक विश्वग्राम के रूप में बदल दिया है। यही वजह है कि आतंकवाद द्वारा सृजित नाटकीयतापूर्ण कृत्यों को आसानी से वैश्विक दर्शक मिल जाते हैं। आतंकवाद के इस विश्वव्यापी दैत्य से राष्ट्रों, अर्थव्यवस्थाओं, लोकतंत्रों की रक्षा करना अब चुनौतीपूर्ण हो गया है।

भारतीय उपमहाद्वीप पर दृष्टिपात करें तो भले ही यहाँ भी आतंकवादी परिदृश्य की कहानी अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी परिदृश्य से भिन्न नहीं है। भौगोलिक अवस्थिती के कारण जहां एक ओर स्थित हिन्द महासागर इसे विभिन्न देशों की जलीय सीमा से जोड़ता है वहीं दूसरी ओर इसकी स्थलीय सीमा अनेक देशों से जुड़ी हुयी है। उत्तर पूर्व राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अवैध आव्रजन से पड़ौसी देशों में प्रशिक्षित आतंकवादी संगठनों या फिर जिहादी समूहों के अन्तराष्ट्रीय स्वरूप के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद ने भारत में दस्तक दी है। क्योंकि साम्प्रदायिकता का मुद्दा तो हमारे विभाजन की त्रासदी से ही

जुड़ा हुआ है। इसके अलावा नक्सलवाद, भाषावाद, जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिक दंगों का हमारा इतिहास रहा है। यदि विभिन्न अन्तराष्ट्रीय आतंकी संगठनों या फिर सीमापार के आतंकी संगठनों द्वारा भारत में ही आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो हो सकता है कि हमारे खुफिया तंत्र, हमारी सुरक्षा व्यवस्था में ही खामियां हों। हमारे यहां आतंक रोधी प्रभावी कानूनों का अभाव हो या फिर हमारी ढीली, लचर कानून व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार हो, यदि ऐसा नहीं होता तो प्रश्न उठता है कि क्यों सितंबर 2001 के बाद अमरीका में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ?

प्रस्तुत शोध में आतंकवाद की चुनौतियों के सभी पहलुओं को समझाया गया है कि कैसे ये हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है। कैसे इन चुनौतियों से निपटा जाये। एक बहुआयामी, बहुसांस्कृतिक, बहुसमुदाय वाले देश के लिये इस दैत्य से निपटना एक आवश्यकता एवं अपरिहार्यता है। निःसंदेह अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान होने का हौसला हमारे अन्दर मौजूद है।

अध्ययन की प्रकृति

आतंकवाद शब्द अपनी प्रकृति से ही नकारात्मक कूटनीति का अस्त्र मात्र है। यही कूटनीति हमारे पौराणिक साहित्य में भी दृश्यमान होती रही है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में भले ही इसने जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के नाम पर अपने आपको पेश किया हो किंतु उद्देश्य सदा ही इसका एक ही रहा – स्वार्थपूर्ति।

भारत में आतंकवाद की चुनौतियां समसामयिक व्यवस्था की उपज नहीं है। किंतु तकनीकी विकास, संचार क्रांति, परिवहन विकास, मादक द्रव्यों की तस्करी, नवउपनिवेशवाद, बेरोजगारी तथा विभ्रान्त आदर्शवाद ने इसके स्वरूप को प्रभावित किया है। जिसके कारण आज इसने क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्वरूप से ऊपर उठकर अन्तराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। इस चुनौती ने हमारी विदेश नीति को प्रभावित किया है। मीडिया आतंकवाद का जन्म हुआ है। आतंकवाद के प्रचार प्रसार के लिए राजनीतिक, आर्थिक सामरिक महत्व के केंद्रों पर हमले होने लगे हैं। संसद व जम्मी कश्मीर विधानसभा पर हमला इसी तथ्य का परिचायक है। मानव बम, आत्मघाती

हमले, फिदायीनी हमले, आतंकवादी संगठनों का मुख्य हथियार बन गये हैं। साइबर आतंकवाद के रूप में कम्प्यूटर, इंटरनेट द्वारा नेटवर्क स्थापित कर विनाश का संवहन किया जा रहा है। सीमा पार के आतंकवाद के नवीन स्वरूप का आविष्कार हुआ है। धन, आधुनिक हथियार, आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर, विदेशी राष्ट्रों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं। भारत में चाहे इसके लिए केंद्र की अविवेकपूर्ण नीतियों ने अलगाव के विचार को जन्म दिया हो या बुनियादी ढाँचे का अभाव रहा हो या फिर धर्म मजहब के नाम पर इसका प्रयोग होता रहा हो इसकी प्रकृति से ही यह हिंसात्मक बन खौफ फैलाता रहा है। इसका लक्ष्य है सिर्फ अपनी मांगें मनवाना, जो आज इस कदर सुरसा की भांति मुंह फैलाये खड़ी है कि राष्ट्रीय सीमाओं को ही पार कर गयी है।

अध्ययन का उद्देश्य

स्वतंत्रता के पश्चात् आज भारत आधी शताब्दी का सफर तय कर 21वीं सदी की चौखट पार कर चुका है। देश आज एक जीवन्त, उन्नति की ओर अग्रसर राष्ट्र के रूप में गतिमान है। पिछले पांच दशकों के कालखण्ड में भारत की राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष अनेक संकट

उत्पन्न हुये हैं। तमाम अन्तर्विरोधों, तनावों, विविधताओं के बावजूद भारत का लोकतांत्रिक ढांचा अविचल रहा किंतु आज सर्वतोप्रमुख आतंकवाद ऐसा नासूर है जिसने हमारे देश की अखण्डता पर आघात किया है।

इस विषय पर अध्ययन का उद्देश्य भारतीय संदर्भ में आतंकवाद के कारणों का पता लगाना है कि कैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणों के अलावा आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रभाव ने व वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारत में आतंकवाद की नवीन पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। विभिन्न राज्यों में उत्पन्न आतंकवाद व नक्सली आतंकवाद का विश्लेषण करना साथ ही भारत पर पड़ने वाले प्रभाव व परिणामों का आकलन करना है। किस प्रकार हम यह तय करें कि हमारा गन्तव्य क्या हो? भविष्य क्या हो? भारत में आतंकी गतिविधियों को रोकने हेतु वैधानिक उपायों, प्रभावी रणनीति के लिये सुझाव देना साथ ही यह भी विचार मंथन करना कि आंतरिक सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावी तरीके से कायम रखा जा सकता है। चूंकि अब तक किये गये प्रयास पूर्णतः हिंसा पर अवधारित रहे हैं, इसलिए इसके समाधान के रूप में

गांधीवादी मूल्यों का सहयोग लेना प्रमुख है। क्योंकि हिंसा के साथ–साथ व्यक्ति के अंदर अहिंसा का अस्तित्व भी विद्यमान रहता है या यों कहें कि दोनों साथ–साथ चलती हैं। जब आचरण में पशुता उतरती है तो भी भीतरी हलचल से अन्तःकरण में एक भाव जागता है। दया, सेवा, दान, त्याग, उदारता, विवेक एक बार शरीर के रग–रग में बहता जरूर है। भीतर की सत्ता से जुड़े रहकर हम बाहर की सत्ता द्वारा करवाये जा रहे गलत कामों को जब पहचानने लगेंगे तो इससे न केवल अन्तःकरण की शुद्धि बनी रहेगी बल्कि समाज के पुनर्निर्माण में भी गांधीवादी तरीकों की महिमा बढ़ेगी।

इस प्रकार इस शोध का उद्देश्य आतंकवाद के समाधान के एक तरीके के रूप में गांधीय उपायों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण विश्व के मूल्य को समझाने में सहायता करना है।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

वी.टी. पाटिल, न्यू फेस ऑफ टेर्ररिज्म, लांसर पब्लिकेशन, दिल्ली, 2008 – इस पुस्तक में नवीन आतंकवाद का चेहरा दिखाया गया है कि

किस प्रकार आज के वर्तमान युग में आतंकवाद सभी क्षेत्रों में उपस्थित है। इसके अलावा पुस्तक में आतंकवाद के प्रकार तथा उसकी परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के संकट का वर्णन किया गया है तथा वहां सक्रिय प्रमुख आतंककारी संगठनों का भी उल्लेख किया गया है साथ ही भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की प्रमुख आतंककारी घटनाओं, धार्मिक आतंकवाद, लोकतंत्र और आतंककारियों की मनोवैज्ञानिक सोच का वर्णन है कि क्यों वो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं?

वाल्डर लॉकर, दि न्यू टेर्ररिज्म : फेनेटीसिज्म एंड दि आर्म्स ऑफ मास डेस्ट्रक्शन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000 – इस पुस्तक के माध्यम से आतंकवाद का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अलावा आतंकवादियों के व्यवहार को समझने का तर्कसंगत आधार भी उपलब्ध कराया गया है। लॉकर इसके माध्यम से रासायनिक व जैविक हथियारों की उपलब्धता व भविष्य में होने वाली हानियों की तरफ ध्यान दिलाते हुए उस विनाशकारी ताण्डव से हमें सचेत करते प्रतीत होते हैं। इस पुस्तक में मार्क्स, मोहम्मद की विचारधारा, धर्म व राज्य के अर्न्तसंबंधों, आतंकवादियों

के प्रेरणास्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसकी रचना का उद्देश्य भविष्य में हथियारों से बढ़ने वाली परेशानियों के प्रति हमारे भीतर दूरदृष्टि से युक्त विचारों की सृष्टि करना है। इसमें भाषा शैली को आशावादी दृष्टिकोण से युक्त किया गया है।

रेंडी बोरम, साइकोलोजी ऑफ टेर्ररिज्म, साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004 इस पुस्तक में आतंकवादी हिंसा को मनोवैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास किया गया है कि आखिर क्यों लोग इन आतंकवादी समूहों की ओर आकृष्ट होते हैं। इसमें उन सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया गया है जो आतंकवाद को रोकने में सहायक हो सकते हैं। साथ ही विचारधारा का आतंकवादियों के व्यवहार पर प्रभाव को समझाया गया है। रेंडी बोरम का उद्देश्य जहां एक ओर यह समझाना रहा कि कैसे यह संगठन पनपते हैं, काम करते हैं और अन्त में नष्ट हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी रहा कि इनके दुःख में हमें भागीदारी निभानी होगी ताकि इन्हें सुमार्ग पर लाया जा सके। इस पुस्तक में लेखक का प्रयास भावनात्मक लगाव पैदा करके लोगों को सद्जीवन की ओर उन्मुख करना है। भाषा

शैली की दृष्टि से यह मार्मिकता का प्रतिनिधित्व करती है।

ब्रुस होफ्मन, इन्साइड टेर्ररिज्म, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 2006 – यह रचना न केवल आतंकवाद के ऐतिहासिक विस्तार बल्कि आतंकवादियों की दिमागी मानसिकता को समझने का एक प्रयास है। इसमें नयी प्रेरणाओं, उन नई रणनीतियों पर चर्चा करते हैं जो हाल ही के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद में दिखायी पड़ती है। साथ ही आतंकवाद के आज व कल के बारे में, धार्मिक व राजनीतिक आतंकवाद के मध्य स्पष्टतापूर्वक भेद करते हुए धार्मिक आतंकवाद की उत्पत्ति पर भी विस्तार से प्रकाश डालते हैं।

टोरे बीजोरगो, रूट कॉजेज ऑफ टेर्ररिज्म ' मिथ्स रियलिटी एंड वेज, रूटलज प्रकाशन, 2005 – यह पुस्तक आतंकवाद की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों, उन स्थितियों का वर्णन करती है जो इसे बढ़ाने में सहायक है। इसमें प्रजातांत्रिक असंतुलन, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, आतंकवाद व मीडिया संबंधों, आतंकवाद के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पहलुओं, फिलीस्तीन, मध्यपूर्व, लेटीन अमरीकी, यूरोप में क्रांतिकारी आतंकवाद के समाप्ति हेतु

ठोस उपायों पर भी दृष्टिपात करती है। साथ ही राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर विस्तार से चर्चा करती है। इसका उद्देश्य आतंकवाद की उत्पत्ति के सभी कारणों पर विचार विमर्श करना है। इसमें शैली व्यंग्यात्मक है।

जगमोहन, माइ फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2006 – इस पुस्तक में आतंकवाद के बर्बर चेहरे, इसके क्षति पहुंचाने के तरीकों व इसकी प्रकृति को विविधता से चित्रित किया गया है। आशावादी सोच के धनी लेखक का मंतव्य है कि कश्मीर में परिवर्तन केवल नयी दृष्टि, यथार्थताओं के प्रति गहरी अंर्तदृष्टि के साथ केवल भारत द्वारा ही लाया जा सकता है। इसमें अनुच्छेद 370, भारत–पाक वार्ता, भारतीय संसद पर हमला आदि घटनाओं के बावजूद नये संकल्पों को सजाया गया है। वेद व्यास, टेर्ररिज्म इन नर्दन इंडिया : जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, 2008 – यह पुस्तक जम्मू कश्मीर व पंजाब के विप्लवों का तथ्यपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करती है। इसमें कश्मीर सरीखे सीमावर्ती राज्य में फैलाये गये विद्रोहों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर में कार्यरत आतंकी समूहों का वर्णन व

जम्मू–कश्मीर की वर्तमान स्थिति का वर्णन भी इसमें है। पंजाब व कश्मीर के सिख व इस्लामी समूहों के प्रति भारत के समझौतावादी रूख को समझते हुए भी प्रेरणा यही दी गयी कि समय कुछ कठोर फैसलों को क्रियान्वित करने का है।

एस.के. घोष, टेर्ररिस्ट वर्ल्ड अण्डर सीज, आशीष पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, 1995 यह पुस्तक आतंकवाद के निकृष्टतम कृत्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है और यह भी बताती है कि इसको बढ़ाने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें वैश्विक आतंकवाद पर प्रकाश डालते हुये विश्व के सभी देशों में बढ़ते अपहरणों, बम विस्फोटों, विमान अधिग्रहणों, सांस्कृतिक विरासतों को क्षति आदि की घटनाओं व इनके रोकने के उपायों, इस संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की भूमिका आदि पर प्रकाश डाला गया है। भारत में स्वतंत्रतापूर्व व पश्चातवर्ती आतंकवादी घटनाओं, इसमें महिलाओं की भूमिका, मानवाधिकारों का हनन आदि के संबंध में चित्रण किया गया है। इस पुस्तक की रचना का उद्देश्य यह बताना है कि किस तरह आतंकवाद हमारे जीवन पर कुप्रभाव छोड़ता है।

जतिन देसाई, इंडिया एंड यू.एस. ऑन टेर्ररिज्म, कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000 – यह पुस्तक भारत–अमरीका संबंधों का चित्रण करती है और यह बताती है कि किस प्रकार ये दोनों मिलकर आतंकवाद का सामना करें। आतंकवाद का वैश्विक परिदृश्य समझाने के साथ ही भारत किस प्रकार आतंकवाद का सामना कर सकता है, किन–किन आतंकवादी संगठनों ने भारत को अपना मुख्य निशाना बनाया है, इसके साथ ही आतंकवाद के राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप का भी वर्णन इसमें है। अमरीका द्वारा द्विपक्षीय मुद्दों में की गयी भागीदारी या यों कहें कि हस्तक्षेप किया, को वैश्विक शांति के विरूद्ध मानते हुए अमरीका द्वारा जो मुख्य हस्तक्षेप किये गये उनका वर्णन भी इस पुस्तक में देखने को मिला है जो हमारे अध्ययन के लिए कारगर साबित हुये हैं। लेखक द्वारा व्यंग्यात्मक शैली में अमरीकी हठधर्मिता को उजागर किया गया है।

अजीत सिंह, वर्ल्ड टेर्ररिज्म टूडे, बुक एन्कलेव जयपुर, 2002 – इस पुस्तक में आतंकवाद की परिभाषाओं, इसकी नीतियों तथा राजनीति में आतंकवाद की व्याप्ति पर प्रकाश डाला गया है। आतंकवाद में प्रयुक्त हो

रही उच्च तकनीकों, इसमें महिलाओं की भागीदारी का वर्णन भी बखूबी किया गया है। आतंकवाद को जंगली आग बताते हुए यह बताने का प्रयास किया गया है कि यह लोगों में मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर देता है। साथ ही 11 सितंबर 2001 को न्यूयार्क में आक्रमण, सांस्कृतिक विरासतों, आतंकवाद के मीडिया से संबंधों भूतकाल व वर्तमान में इसके परिवर्तित स्वरूपों, इसके विभिन्न प्रकारों आदि का उल्लेख किया गया है।

सुरीनेनी इन्द्रा, गांधीयन डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रस्टीशिप, साउथ एशिया बुक्स, नई दिल्ली, 1991 – यह पुस्तक समाज में असमानता को कम करने, इस विषमता को दूर करने हेतु गांधीजी के सिद्धान्तों, विशेषकर ट्रष्टीशिप के सिद्धान्त पर अधिक बल देती है। इसमें ट्रस्टीशिप के आधार व स्रोतों का वर्णन समाज में धन का समान वितरण कर समाज को हिंसक प्रवृत्तियों से बचाने हेतु किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक की रचना का उद्देश्य आर्थिक न्याय की दिशा में गांधीय उपायों का मूल्य समझाना है।

प्रो. आर.पी. मिश्रा व के.डी. कनग्रोड, गांधीयन अल्टरनेटिव, कनसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 2005 – यह पुस्तक गांधी के सिद्धान्तों को

किन–किन क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जा सकता है, का वर्णन करती है। जैसे गांधी का अध्ययन उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में करना इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर इसका अध्ययन करवाना, गांधीजी पर शोध करवाना, उनके विचारों को जन–जन में फैलाना आदि प्रमुख विषयों पर इस पुस्तक में लिखा गया है, जो कि हमारे शोध के लिये महत्वपूर्ण साबित होगी। गांधीजी के विचारों में उनका सत्याग्रह और ट्रष्टीशिप के सिद्धान्त का वर्णन प्रमुख रूप से इसमें किया गया है।

मंजरिका सिवाक, कांफ्लिक्ट्स एंड पीस प्रोसेस, मनोहर प्रकाशन, 2006 – यह पुस्तक भारत व पाकिस्तान के मध्य चलने वाली शांति प्रक्रिया के प्रयासों पर प्रकाश डालती है साथ ही यह भी बताती है कि कैसे इन दोनों नाभिकीय प्रतिद्वन्द्वियों के बीच धर्म एक अहम् मुद्दा है। इसमें बढ़ते संघर्ष को रोकने हेतु आर्थिक सहयोग को विकल्प के रूप में प्रमुखता से दर्शाया है।

अदलूरी सुब्रह्मण्यम राजू व एस.आई. कीथा पोंकलन, मेरीटाइम कोपरेशन बिटविन इंडिया एंड श्रीलंका, मनोहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स,

2008 – यह पुस्तक भारत श्रीलंका संबंधों के विविध पहलुओं को उजागर करती है। इसमें 1974, 1976 के समझौतों, कच्चातीबू विवाद के बावजूद जलवायु, प्रदूषण नियंत्रण, समुद्र शास्त्रीय अध्ययन, अवैध व्यापार पर आदि पर सहयोग के बिंदू दर्शाये गये हैं। भारत श्रीलंका समुद्री मुद्दों पर समझ बढ़ाने के लिये लेखकद्वय का यह अनूठा प्रयास है।

ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित, इंडियाज फोरेन पालिसी एंड इट्स नेबर्स, ज्ञान बुक्स, 2001 – इसमें भारत के विदेश संबंधों से संबद्ध लेखों का संकलन है। साथ ही भारत की विदेश नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। 1994 से 2001 तक की घटनाओं का वर्णन, राष्ट्रीय हितों का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक शोधार्थियों के लिये अत्यंत उपयोगी है।

अदलूरी सुब्रह्मण्यम् राजू, टेर्ररिज्म इन साउथ एशिया : व्यूज फ्रॉम इंडिया, इंडिया रिसर्च प्रेस, 2004 – आतंकवाद पर विविधतापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने का लेखक का यह सराहनीय प्रयास है। इसमें आतंकवाद से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या, आतंकवादियों की गतिविधियों, कश्मीरी आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके

एक खंड में महत्वपूर्ण दस्तावेजों, समझौतों, संधियों के वर्णन ने इसको अति महत्वपूर्ण बना दिया है। दक्षिणी एशिया से आतंकवाद का भारतीय संदर्भ में प्रस्तुतिकरण तक का इसका विश्लेषण महत्वपूर्ण है।

स्टेनली वाल्पर्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान : कंटीन्यूड कांफ्लिक्ट एण्ड कोपरेशन, केलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2010 – इस पुस्तक में लेखक तिरेसठ वर्षों के इतिहास का वर्णन करते हुये भारत पाकिस्तान के मध्य संबंधों में संघर्ष की मूल जड़ को तलाशते हैं। उनके संघर्ष निवारण हेतु विभिन्न प्रयासों, दृढ़ निश्चयी उपायों का जिक्र किया गया है।

जे.एन. दीक्षित, इंडिया पाकिस्तान इन वार एंड पीस, रूटलज प्रकाशन 2003 – यह पुस्तक दक्षिणी एशिया के दो प्रतिद्वन्द्वियों, कश्मीर संघर्ष की तुलना इजरायल फिलीस्तीन संघर्ष से करते हुए इनके संघर्ष को इतिहास की विरासत मानती है। इन दोनों के स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रारंभ से ही युद्धरत रहने, इनके मध्य हुए तीन युद्धों, संयुक्त राष्ट्र संघ में इनके टकराव का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्ध उकसाये गये आतंकवारियों द्वारा किये गये हिंसक कृत्यों

का तथ्यों से पूर्ण चित्रण है।

जॉन वी. बान्ड्यूरेन्ट, कन्क्वेस्ट ऑफ वायलेंस : दि गांधीयन फिलोसॉफी ऑफ कान्फिलिक्ट, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1988 – इस पुस्तक में गांधीजी के राजनीतिक दर्शन को क्रमबद्ध रूप से चित्रित किया गया है। यह गांधीजी के जीवन, उनके सत्याग्रह का तरीका, भारत में उनके सत्याग्रह अभियानों पर क्रमबद्ध अध्ययन, साथ ही सत्याग्रह की अवधारणा पर हमें प्रेरित भी करती है।

डायना मिलर, टेर्ररिज्म : आर वी रेडी, नोवा साइंस पब्लिशर्स, 2002 – इसमें लेखिका आतंकवाद की भयावहता के प्रति हमें सचेत करते हुए जैविक आतंकवाद, नाभिकीय आतंकवाद, विनाश के हथियारों, आतंकवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय नियमों, संधियों, आतंकवाद से राष्ट्रों की सीमा सुरक्षा के मुद्दों आदि घटनाओं का विश्लेषण, आतंकवाद की ओलंपिक खेलों के दौरान भयावहता का जिक्र किया है।

डेविड अरनोल्ड, गांधी, लांगमन, 2001 – इसमें लेखक गांधीजी के जीवन का विविधता से परिपूर्ण परिचय करवाते हैं। 20वीं सदी के इस

प्रशंसनीय व्यक्ति को एक हिंदू संत की संज्ञा देते हुए उनके दृष्टिकोणों, अनुभवों पर व्यापक दृष्टिकोण पेश करते हुए उनकी पश्चिम तक प्रसिद्धि, पश्चिम पर उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं।

सुमंत्रा बोस, कश्मीर : रूट्स ऑफ कांफ्लिक्ट पाथज टू पीस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2003 – बोस प्रस्तुत पुस्तक में गहराई से यह बताती है कि कैसे कश्मीर के प्रश्न ने दक्षिणी एशिया में विनाश की आशंका रूपी अग्नि को निरन्तर प्रज्वलित किए रखा है। इस ओर शांति बहाली हेतु सुझाव, संघर्ष के जन्म के कारण, कश्मीर में हुए युद्ध, संप्रभूता संबंधी संघर्ष के बारे में विस्तार से प्रकाश डालती है।

डेविड हार्डीमेन, गांधी इन हिज टाइम एंड अवर्स : दि ग्लोबल लीगेसी ऑफ हिज आईडियाज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2003 – यह पुस्तक गांधी के विचारों की पृष्ठभूमि बयां करती है कि उनको यह विचार कहां से प्राप्त हुए। लेखक ने बताया है कि उनका यह दृष्टिकोण तत्कालीन समाज व्यवस्था पर केंद्रित था। उनके विरोधी समूहों के साथ संघर्ष के तरीकों, दलितों के प्रतिनिधियों व उनके आलोचकों के साथ संबंधों का हार्डीमेन परीक्षण करते हैं। इसमें गांधीजी के स्त्रियों के प्रति

नजरिए का भी उल्लेख किया गया है। मनोज जोशी, दि लोस्ट रिबेलियन, इसमें कश्मीर में हुए विप्लवों का वर्णन है। लेखक विद्रोहियों के आतंकी बनने तक के सफर को बड़ी सफाई से चित्रित करता है कि कैसे असंतुष्ट युवा वर्ग एक ही वर्ष में उन समूहों में शामिल हो जाते हैं जो भारत विरोधी हैं। इसमें भारत के खिलाफ पाकिस्तान के छद्म युद्ध का भी वर्णन है।

डेनिस डाल्टन, महात्मा गांधी : नॉनवायलेंट पावर इन एक्शन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012 – इस पुस्तक में गांधीजी को दो असाधारण सफलताओं सविनय अवज्ञा आंदोलन, कलकत्ता उपवास का वर्णन करते हुए डाल्टन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक रहने के दौरान गांधीजी को अनेक अवसर मिले जिन पर उन्होंने अपने आदर्शों को न केवल विकसित किया बल्कि पुनर्जीवित किया। उनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग, माल्कोम × से की गयी है। इस पुस्तक की रचना का उद्देश्य गांधी के जीवन की घटनाओं को विशिष्ट दृष्टि से संजोना रहा है।

प्रतीप के. लाहिरी, भारत में सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद – इस पुस्तक में इस ज्वलंत विषय पर देश–विदेश की तमाम घटनाओं, मजहबी,

परंपराओं, इतिहास का ब्यौरा दिया गया है। इसमें दंगों के लिए जिम्मेदार तत्वों का भी विश्लेषण है। वैचारिक दलीलों के आधार पर हिंसक प्रवृत्तियों के मूल में जाने की कोशिश लेखक ने की है। अंतिम खंड में जबलपुर, इंदौर, भागलपुर, मुंबई, गुजरात के दंगों का वर्णन है। यह भारत में हुए दंगों के साथ ही दुनियाभर में हो रही आतंकवादी घटनाओं, इनमें लिप्त आतंकवादियों, उनके संगठनों की मानसिक बुनावट पर रोशनी डालती है। इसमें यह टिप्पणी आशाजनक है, ''यदि सिर्फ समुदाय के नेता, राज्य के अधिकारी और मीडिया तालमेल के साथ कार्य करें तो एक ऐसे सामंजस्यपूर्ण समाज के विकास की ओर ले जाने वाले आंदोलन की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें अलग–अलग धार्मिक पहचान के प्रति बढ़ी हुयी जागरूकता के फलस्वरूप होने वाले संघर्ष कम से कम हो।''

एंथनी परेल, गांधी, फ्रीडम एण्ड सेल्फ रूल, लेक्विंजगटन बुक्स, 2000 – यह पुस्तक गांधीजी के स्वतंत्रता के संदर्भ में दिये गये चार अर्थों को विस्तार से बताती है। संप्रभू राष्ट्र की स्वतंत्रता, व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, गरीबी से स्वतंत्रता, आत्म नियंत्रण की सामर्थ्यता के आधार पर स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता आदि। गांधीजी के पूर्वी व पश्चिमी विचार

स्रोतों का वर्णन, साथ ही विरासत में प्राप्त हिंदुत्व की विचारधारा के खतरों के प्रति आगाह किया गया है।

वजहत हबीबुल्लाह, माह कश्मीर : कांफ्लिक्ट एंड दि प्रोसपेक्ट्स ऑफ एन्ड्यूरिंग पीस, वंगार्ड बुक्स, 2009 – इस पुस्तक में जातिवाद, धर्म, राष्ट्रीय पहचार, राष्ट्रीय व स्थानीय शासन संबंधी अव्यवस्थाओं को आतंकी गतिविधियों का मूल कारण माना गया है। भारत सरकार द्वारा की गयी भूलों, कश्मीरी मध्यमवर्गीय अभिजन समूहों की लालची प्रवृत्तियों, धर्म की राजनीति का भी इसमें समावेश है। लेखक विश्वासघात के लंबे इतिहास के बावजूद शांति तलाशने की संभावना को महानतम मानते हैं।

एंथनी परेल, गांधीज फिलोसॉफी एण्ड दि क्वेस्ट फोर हारमनी, केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006 – इसमें गांधी दर्शन को प्रस्तुत किया गया है। लेखक यह खोजते हैं कि कैसे गांधीजी एक साथ आध्यात्मिक भी थे और सांसारिक भी। उनके इसी सामंजस्य को इस पुस्तक में बताया गया है। साथ ही पुरूषार्थ और जीवन के उद्देश्य को गांधीजी ने कैसे धर्म व राजनीति के साथ जोड़े रखा। गांधीजी के व्यावहारिक दर्शन का भारतीय

विचारकों पर प्रभाव, इस दर्शन की वर्तमान में महत्ता आदि को इसमें समावेशित किया गया है।

बेंजामिन नेतान्याहु, फाइटिंग टेर्ररिज्म, फेनर स्ट्रॉज एण्ड जेरोक्स पब्लिशर्स, 2001 – इस पुस्तक में घरेलू आतंकवाद को प्लेग जैसी महामारी की संज्ञा दी गयी है। नागरिक स्वतंत्रताओं, 1980 के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, 1990 के दशक में अमरीका व अन्य देशों में इस्लामी आतंकवाद का उदय, नाभिकीय आतंकवाद आदि के वर्णन के साथ लेखक इस विषय पर चिंता जाहिर करता है कि आखिर क्या किया जाये? कैसे लोकतंत्रीय व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी जाल को खत्म कर सकती है? इन समस्त विषयों पर समझ बढ़ाने का लेखक का प्रयास है।

राम पूनियानि, टेर्ररिज्म : फेक्ट्स वर्सेस मिथ्स, फेरोज मीडिया पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2007 – पुस्तक में आतंकवाद रूपी प्रक्रिया के विविध आयाम बताते हुए इसे वर्तमान की मुख्य समस्या बताया गया है। लेखक द्वारा इसे मुस्लिम समुदाय, धर्म, सभ्यता के पतन आदि से जोड़ते हुए इसकी समाप्ति हेतु आवश्यक उपाय बताए गए हैं।

रिचर्ड ए. क्लार्क, अगेंस्ट ऑल एनीमीज – इन्साइड अमेरिकाज वार ऑन टेरर, फ्री प्रेस पब्लिशर्स – यह पुस्तक राष्ट्रपति बुश के प्रशासन की प्रतिकारियों को दबाने में किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालती है। न केवल बुश बल्कि इस ओर रीगन, क्लिंटन के प्रशासन की भी बारीकी से पड़ताल करती है। बुश प्रशासन के प्रति इसमें कड़ी आलोचना की गयी है।

अहमद परवेज, अलकायदाज मिशन कश्मीर, 2009 – यह पुस्तक अलकायदा की कश्मीर में मौजूदगी, कश्मीर घाटी में हुयी सैनिक मुठभेड़ों अलकायदा के इराक, दक्षिणी अफ्रीका, सऊदी अरब आदि देशों में की गयी हिंसक घटनाओं, इसके नेताओं व अलकायदा के भविष्य आदि सभी बिंदुओं पर व्यापक दृष्टिपात करती है।

सुधीर कुमार सिंह, टेर्ररिज्म ए ग्लोबल फिनोमिना, आर्थर प्रेस, 2000 – इस पुस्तक में आतंकवाद को युद्ध का ही दूसरा चेहरा बताया गया है, साथ ही आतंकवाद की प्रकृति पर भी विस्तार से वर्णन किया गया है। अर्थव्यवस्था, अपराध व आतंक के संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी है।

जोगिंदर सिंह, ट्रायस्ट विद टेरर : टेर्ररिज्म इन इंडिया – यह

पुस्तक लेखों पर आधारित है जिसमें 2005 से लेकर 2008 तक के मुंबई हमले तक का वर्णन है। इसमें लेखक हमें भारत के नक्सलवादी, माओवादी विद्रोहियों, इस्लामी आतंकवादियों व अन्य समूहों चाहे वे घरेलू हो या बाहरी आदि के बारे में व्यापक रूप से बताती है।

डी.पी. शर्मा, दि न्यू टेर्ररिज्म ' इस्लामिस्ट इंटरनेशनल, एपीएच पब्लिशिंग, 2005 – नवीन आतंकवाद, परंपरागत आतंकवाद, जिहाद, आत्मघाती दस्तों, अलकायदा के नेतृत्व विहीन आतंकवाद, सभ्यताओं के पतन, राज्य प्रायोजित आतंकवाद साथ ही भविष्य के आतंकवाद आदि पर एक साथ रोशनी डालती है।

आर. जोनाथन, टेर्ररिज्म एंड होमलेण्ड सिक्योरिटी, 2011 – इस पुस्तक में आतंकवाद के विभिन्न विषयों का समावेश किया है, जैसे : आतंकवाद की सामजिक पृष्ठभूमि, आतंकवादी संगठन व इसके वित्तीय संसाधनों का वर्णन, आधुनिक आतंकवाद के कारणों आदि पर लेखक द्वारा किया गया वर्णन अद्वितीय है।

लारेंस होवर्ड, टेर्ररिज्म – रूट्ज, इंपेक्ट, रेस्पोंसेज – इसमें लेखक आतंकवाद को हिंसा के सभी प्रकार के प्रयुक्त अविवेकपूर्ण कार्यों पर

आधारित मानते हुए इसकी प्रकृति के बारे में न केवल चर्चा करता है बल्कि इसके लक्ष्यों का भी वर्णन इसमें है। इसमें लेखक का उद्देश्य हिंसा के प्रति अपने उद्गार प्रकट करते हुए जनता को जाग्रत करना है।

लोा ए.एम.सी. नमारा व रॉबर्ट ए.रूबिन्स, डेंजर्स लियाइसंस – प्रस्तुत पुस्तक आतंकवाद जैसे कठिन विषय पर हमें एक प्रभावी संवाद प्रस्तुत करती है। यही संवाद इसे अद्भुत बना देता है। इसका प्रमुख ध्यान देने योग्य पहलू यह है कि आतंकवाद जैसे विषय पर यहाँ अनेक उपागमों का वर्णन सम्मानपूर्ण तरीके से किया गया है। राज्यीय हिंसा व मानव शास्त्र, युद्ध, शांति, आदि के अर्न्तसंबंधों पर भी यह व्यापक दृष्टिपात करती है।

डॉ. कृष्णदेव झारी, कश्मीर समस्या और भारत पाक युद्ध, नालंदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001 – प्रस्तुत पुस्तक में भारत पाक संबंधों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इनके मध्य मूल समस्या कश्मीर की नहीं बल्कि अलगाववादी धर्मान्धता है। साथ ही यह कश्मीर समस्या के सभी पहलुओं, भारत पाक के मध्य तनावों, संघर्षों, कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों, हिन्दू

पंडितों की दुर्दशा आदि को विवेचित करते हुये भी दोनों देशों को कश्मीर के स्थान पर आर्थिक अवनति दूर करने के उपायों को लागू करने पर बल देता है किंतु मित्रतापूर्ण संबंधों का हिमायती होने के बावजूद लेखक पाकिस्तान के आक्रामक रूख को सहन करने का पक्षधर नहीं है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखन का उद्देश्य इस्लामी धर्मान्ध आतंकवाद को भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खत्म करने की आवश्यकता ताकि भारतीय उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो। इसमें भाषा शैली की दृष्टि से लेखक ने तीखे शब्दों में बात की है।

मनोहर लाल बाथम व शिव चरण विश्वकर्मा, आतंकवाद चुनौती और संघर्ष, मेघा बुक्स, दिल्ली, 2003 – प्रस्तुत पुस्तक आतंकवाद से संबंधित सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने का लेखकद्वय का अनूठा प्रयास है। इसमें आतंकवाद की आधारशिला हिंसा को मानते हुए भी इसे केवल अल्पावधि के लिये आया हुआ विकार बतलाकर, मनुष्य का मूल स्वभाव उसकी सद्वृत्तियों को बताते हुये हिंसा पर अहिंसा की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी है साथ ही आतंक फैलाने की कार्यप्रणाली, आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने के कारण, इसके बदलते स्वरूप, मानवाधिकारों की आड़ लेकर अपने

दुष्कर्मों को छिपाने की आतंकवादियों की मनोवैज्ञानिक सोच का वर्णन है। मीडिया व आतंकवाद अर्न्तसंबंधों पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखन का उद्देश्य आतंकवाद के इतिहास व वर्तमान से अवगत कराना ही नहीं बल्कि इसके विरूद्ध मानसिक तैयारी के लिये प्रेरित करना है। इसमें भाषा का प्रयोग व्यावहारिक साथ ही शैली व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक, सुझावात्मक है।

पीटर आर. न्यूमन, ओल्ड एंड न्यू टेर्ररिज्म, पोलिटी प्रेस, 2009 – प्रस्तुत पुस्तक में प्रमुख विषय यह है कि आतंकवादियों के संगठनात्मक ढांचे क्यों व कैसे पनपते हैं। इसमें आधुनिक सूचना क्रांति व भूमण्डलीकरण के कारण राजनीतिक कार्यक्रमों, युद्ध के प्रकारों, हुये परिवर्तनों का भी वर्णन किया गया है। इसमें लेखक का उद्देश्य आतंकवाद के नये स्वरूप की इस चुनौती से संघर्ष हेतु सरकार व समाज को तैयार रहने की सलाह देना है। लेखक ने सरल भाषा में अपनी बात कही है।

एडरीयन गुअलके, दि न्यू ऐज ऑफ टेर्ररिज्म एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, आई.बी. टोरिस, लंदन व न्यूयार्क, 2009 – प्रस्तुत पुस्तक में लेखक की आतंकवाद विषय से संबंधित गहन दृष्टि उजागर हुई है।

इसमें लेखक 9/11 के बाद आतंकवाद के विश्वपरक स्वरूप पर प्रकाश डालता है। व्यंग्यपूर्ण शब्दों में सरकार पर भी व्यंग्य करता है कि कैसे इसकी मौजूदगी में आतंकवादी समूह हिंसा उपजाते रहते हैं। लेखक की यह व्यंग्य प्रधान रचना है।

माइकल बर्लिह, ब्लड एंड रेज : ए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ टेर्ररिज्म, हार्पर कोलिंस पब्लिशर्स, 2009 – प्रस्तुत पुस्तक में आतंकवाद की आधुनिक प्रवृत्ति पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण के धनी लेखक ने 19वीं सदी के पश्चिमी यूरोप पर प्रकाश डाला है। इसमें आतंकवादी समूहों, रेड आर्मी, अलकायदा व अन्य जिहादी समूहों के कार्यों पर प्रकाश डाला है। लेखक की भाषा सरल है।

ब्रिगीटे एल.नाकोस, टेर्ररिज्म एंड काउंटर टेर्ररिज्म, लोंगमन, बोस्टन, 2011 – यह आतंकवाद विषय पर लिखी गयी एक व्यवस्थित रचना है। यह आतंकवाद की परिभाषा, वैश्विक आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, राज्य प्रायोजित आतंकवादी समूहों, उनके लक्ष्यों, नागरिक स्वतंत्रताओं व सुरक्षा, मीडिया का दोहन आदि विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

रिचर्ड जेक्सन, ली जारविश, जीरोन गनिंग व मेरी ब्रीन स्मिथ, टेर्ररिज्म ए क्रिटिकल इंट्रोडक्शन, मेकमिलन, न्यूयार्क, 2011 – इसमें लेखक वार्तालाप की शैली में एक आलोचक के रूप में आतंकवाद पर विचार रखता है। इसकी प्रकृति, इसकी घटनाओं कि कैसे इन्हें भययुक्त बनाया जाये आदि पर एक आलोचक की दृष्टि से अपने विचार व्यक्त करता है।

गुश मार्टिन, एसेंशियल ऑफ टेर्ररिज्म : कंसेप्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज, सेज, लॉस एंजिल्स, 2011 – यह पुस्तक आतंकवाद की आधुनिकतम प्रवृत्तियों की प्रस्तुति का शानदार नमूना है। इसमें लेखक आतंकवाद पर गहरी अर्न्तदृष्टि के साथ उसकी परिभाषा, ऐतिहासिक व विचारधारात्मक वर्णन, लक्ष्यों, भविष्य के बारे में नजर डालता है। यहां लेखक की मनोवैज्ञानिक सोच का वर्णन है।

वालर एंडर्स व टूड सेंडलर, दि पॉलिटिकल इकोनोमी ऑफ टेर्ररिज्म, केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 2006 – प्रस्तुत पुस्तक में घरेलू व बाहरी आतंकवादी घटनाओं का गुणात्मक व मात्रात्मक आधार पर राजनीतिक विश्लेषण किया गया है। इसमें यह भी वर्णन है कि कैसे नागरिक

स्वतंत्रताओं व सुरक्षा व्यवस्था को उदार प्रजातंत्रीय समाज में सरकार अपनी प्रभावशीलता बनायी रखे। शैली व्यावहारिक, सुझावात्मक है।

ब्रुस बोंजर, साइकोलोजी ऑफ टेर्ररिज्म, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007 – प्रस्तुत पुस्तक आतंकवादी घटनाओं के उत्तरदायी कारकों का वर्णन करती है साथ ही उन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को भी बताती है जो इसके खात्मक के लिये उपयोगी हो सकते हैं।

लोरेंस राईट, दि लूमिंग टावर : अलकायदा एंड दि रोड टू 9/11, विंटेज, न्यूयार्क, 2009 – इसमें 9/11 की घटनाओं का वर्णन है। साथ ही इस्लामिक अस्तित्ववादियों के उदय का भी वर्णन है। अमरीकी खुफिया एजेंसियों की 9/11 के आक्रमण को रोकने में असफलता को व्यंग्यात्मक शैली में दर्शाया गया है। जेसन प्रेंकस, रिथिंकिंग दि रूट्स ऑफ टेर्ररिज्म, मेकमिलन, न्यूयार्क, 2006 – यह पुस्तक विशेषतः मध्यपूर्व के संदर्भ में आतंकवाद के उद्देश्यों व कारकों को विस्तृत रूप में हमें बताती है। सामाजिक, राजनीतिक कारकों पर भी व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है।

जॉन हारगन, दि साइकोलोजी ऑफ टेर्ररिज्म, रूटलज, 2005 – यह पुस्तक मनोविज्ञान का शानदार प्रस्तुतिकरण है कि कैसे एक व्यक्ति को आतंकवादी बना दिया जाता है, कैसे वह बदली हुई स्थितियों में काम करता है। आतंकवादियों के आचरण व आतंकवाद को कैसे परिभाषित किया जाये। इस विषय पर यह पुस्तक सरल शैली में पठनीय सामग्री प्रस्तुत करती है।

जेम्स जे.एफ. फोरेस्ट, दि मेकिंग ऑफ ए टेर्ररिस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड रूट कोजेज, प्रेगर सिक्योरिटी इंटरनेशनल, 2006 – प्रस्तुत पुस्तक में यह चर्चा की गयी है कि एक व्यक्ति कैसे आतंकवादी के रूप में बदल जाता है। इसमें आतंकवादियों की भर्ती, उनको शामिल करने के मनोवैज्ञानिक तरीकों व धर्म के आधार पर दबाव बनाने आदि का इसमें वर्णन है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन सभी कारकों का वर्णन है जो आतंकवाद को बढ़ाने में सहायक होते हैं। सरल भाषा में लेखक का यह अनूठा प्रयास है।

अध्ययन की पद्धति

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु विभिन्न पुस्तकों, लेखों, विभिन्न लेखकों के पत्र प्रकाशनों का अध्ययन किया गया है जिसमें कार्य की मूल अवधारणा व इसके मुख्य उपागम स्पष्ट होते हैं तथा दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत शोध में तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक स्रोतों के अन्तर्गत दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों के माध्यम से तथ्य संकलित किये हैं। द्वैतीयक स्रोतों में व्यक्तिगत प्रलेखों के अन्तर्गत संकलन कर्ताओं का संदर्भ देते हुये जीवन वृत्तों के माध्यम से समाज से संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी ली गयी है। सार्वजनिक प्रलेखों के अन्तर्गत सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाओं के द्वारा तैयार प्रकाशित लेखों जैसे – व्यक्तिगत शोध कर्ताओं के प्रकाशन, शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन आदि का अध्ययन करते हुये तथा अप्रकाशित लेखों के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों जैसे विदेश, गृह मंत्रालय आदि द्वारा तैयार आंकड़ों, सूचनाओं तथा दस्तावेजों का भी अध्ययन किया गया है। शोध अध्ययन के लिये विभिन्न पुस्तकालयों जैसे राधाकृष्णन पुस्तकालय जयपुर, कुमारप्पा गांधी ग्राम स्वराज्य निधि जयपुर, गांधी अध्ययन केंद्र, राजस्थान

विश्वविद्यालय जयपुर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा आदि की सहायता ली गयी है। प्रस्तुत शोध कार्य तुलनात्मक व विश्लेषणात्मक होने के साथ–साथ समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। समस्त घटनाओं का उल्लेख तथ्यों पर आधारित है जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति एवं जनाक्रोश को बढ़ावा न मिले। इसमें राजनीतिक व सामाजिक तथ्यों का विशिष्ट विश्लेषण किया गया है जिसमें वैचारिक पूर्व धारणा के विषय भी शामिल है। पूर्णतः विश्लेषणात्मक होने के कारण शोध के परिणामस्वरूप ऐसे तथ्यगत निष्कर्ष निकले हें जो समरूप समाजों के लिये उपयोगी हो सकते हैं।

द्वितीय

अध्याय

आतंकवाद का निहितार्थ, विस्तार, प्रमुख कारण व विश्व की प्रमुख आतंकवादी घटनायें

आतंकवाद वर्तमान विश्व की सबसे प्रमुख समस्या के रूप में उभरा है। आज इसके विश्वव्यापी रूप ग्रहण करने के कारण यह केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहा है। विश्व के सभी देश इसके अर्थ के संदर्भ में एकमत नहीं है। यह व्यक्तियों, समूहों, समाजों, राष्ट्रों के लिये विरोधाभास से युक्त विषय है। वाल्टर लॉकर का इस विषय पर जीवनपर्यन्त शोध प्रयास इस तथ्य का परिचायक है कि इसे परिभाषित करना कितना कठिन है। जिन हिंसात्मक गतिविधियों को अमरीका और पश्चिमी संसार आतंकवाद कहता है उन्हें कट्टरपंथी मुसलमान 'जिहाद', फिलीस्तीन व कश्मीर जैसे भू–भाग को स्वतंत्र देश बनाने की तमन्ना रखने वाले 'स्वतंत्रता की लड़ाई', अमरीकी अहम् के विरोधी 'उत्पीड़न व शोषण के विरूद्ध संघर्ष' तथा तटस्थ सोच वाले 'क्रिया की प्रतिक्रिया' कहते हैं। आतंकवाद राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्त राष्ट्रों की कार्य सूचियों में शामिल अग्रणी, जटिलता से युक्त और निरन्तर परिवर्तित होती हुयी प्रक्रिया है। अनेक स्वरूपों को अपने में समाहित करते हुये यह विस्तृत समूहों व प्रेरणाओं से

जुड़ा रहता है। भावनात्मक रूप से प्रोत्साहित इसकी प्रकृति के कारण इसको परिभाषित करना कठिन है। साधारण शब्दों में, यह एक धमकी या हिंसा का प्रयोग है। जिससे उन राजनीतिक, धार्मिक, विचारधारात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके जो अन्यथा अप्राप्य है। यह कोई विचारधारा या दार्शनिक सिद्धान्त नहीं है अपितु एक तरीका, एक प्रक्रिया मात्र है जिसका प्रयोग कर कोई भी राज्य, राजनीतिक संगठन, स्वतंत्रतावादी समूह, अलगाववादी संगठन जातीय या धार्मिक उन्मादी अपने उद्देश्यों को प्रापत करना चाहते हैं। आधुनिक संदर्भ में इसका अर्थ हिंसा का ऐसा प्रयोग जो सैनिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि लक्ष्य को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करे। 'यह जीवित मानवता के प्रति एक यथार्थ धमकी उत्पन्न करता है। इसको निर्मित करने में निहित भावना यह है कि मानव जाति को शांति से वंचित कर दिया जाये यह न केवल शांति बल्कि सुरक्षा, राष्ट्रों के मध्य आपसी समझ, सामाजिक व आर्थिक विकास, प्रजातंत्र आदि के विरूद्ध सीधी प्रताड़ना है।'[1] 1975 में सर्वप्रथम आतंकवाद को सामान्य अर्थ में आतंक का एक नीति के रूप में क्रमबद्ध प्रयोग के रूप में जाना जाता

था। शाब्दिक दृष्टि से आतंकवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रुसेल्स में दण्ड विधान को समेकित करने के लिये 1931 में बुलाये गये तीसरे सम्मेलन में किया गया था। जिसके अनुसार इसका अभिप्राय, ''जीवन, भौतिक अखण्डता अथवा मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला था। बड़े पैमाने पर संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला कार्य करके जानबूझकर भय का वातावरण उत्पन्न करना है।''[2]

प्रमुख परिभाषाओं का विवेचन अग्रांकित प्रकार से है :– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, संयुकत राज्य अमरीका संघ आदि के द्वारा इसको परिभाषित करने के अनेक प्रयासों के बावजूद आज तक इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। 1936 से लेकर 1970 तक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसको परिभाषित करना टेढ़ी खीर प्रतीत होता था। इसको परिभाषित करने में 1937 के कन्वेंशन जो कि आतंकवाद पर रोक व सजा हेतु तैयार किया गया था, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र संघ के 1937 के कन्वेंशन द्वारा इसे परिभाषित किया गया जैसे कि ''आपराधिक कृत्य'' जो एक राज्य के विरूद्ध किये जायें और जिनका

उद्देश्य किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों के समूहों और सामान्य जनता में भय उत्पन्न करना हो। 1960 के दशक के अन्त में पी.एल.ओ. (Palestinian Liberation Organisation) द्वारा विमान जब्त करने की घटना उपरान्त 1970 के कन्वेंशन द्वारा जो कि गैरकानूनी ढंग से वायुयानों को जब्त करने के विरोध में तैयार किया गया था व 1971 का मांट्रियल कन्वेंशन जिसका उद्देश्य विमान यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधान तैयार करना था, विमान जब्तीकरण को आतंकवाद के कुकृत्यों में शामिल करते हुये निम्नांकित परिभाषा दी गयी है – ''गैरकानूनी रूप से शक्ति के प्रयोग अथवा धमकी या प्रपीड़न के अन्य तरीकों द्वारा विमानों को जब्त करना, उनको नियंत्रण में रखना या फिर इस प्रकार के कृत्यों का प्रयास करना।''[3] इस प्रकार इस दशक के दौरान आतंकवाद के पारंपरिक व आधुनिक स्वरूप में परिवर्तन स्पष्टतया परिलक्षित होता है। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के दौरान इजरायली खिलाड़ियों की हत्या व जापानी आतंकवाद का घिनौना कृत्य जो कि तेल अबीव में घटित हुआ, यह दोनों घटनायें बम विस्फोटों द्वारा संपादित की गयी। शीत युद्ध के दौरान

आतंकवाद बनाम स्वतंत्रता सेनानी का द्वन्द्व निरन्तर पल्लवित होता रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1996 को रिजोल्यूशन 51/210 के अनुच्छेद 2 में आतंकवाद को इस प्रकार परिभाषित किया है – गैरकानूनी व इरादतन किये गये कृत्य 1. जिससे किन्हीं व्यक्ति विशेष की मौत या गंभीर शारीरिक प्रताड़ना, 2. निजी व सरकारी संपत्ति की हानि जैसे : सार्वजनिक स्थलों, सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक इमारतों, पर्यावरणीय क्षति, 3. संपत्ति, स्थलों, सुविधाओं, व्यवस्थाओं को क्षति पहुंचाना ताकि अधिकाधिक आर्थिक हानि करते हुये अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के दूरगामी लक्ष्यों की सिद्धि हो सके। यूरोपीय संघ की परामर्शदात्री समिति द्वारा 2002 में 1937 की अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की परिभाषा में निम्नांकित तत्वों का सम्मिलन करते हुए बताया गया है कि – ''आतंकी समूहों द्वारा की गयी क्षति निश्चित रूप से आपराधिक विनाश है जो व्यापक तौर पर व्यक्तियों, संपत्तियों को हानि पहुंचाती है जिनका प्रमुख उद्देश्य गंभीर रूप से जनता को उत्पीड़ित करना है, सरकार को विवश करना है, देशों के आधारभूत राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक, सामाजिक ढांचे या अन्तर्राष्ट्रीय

संगठनों के ढांचे को विनष्ट करना है।''[4] अफ्रीकी संघ कन्वेंशन 1999 द्वारा इसको ऐसा कृत्य बताया गया है जो किसी देश के आपराधिक नियमों का उल्लंघन करता हो, देश विशेष की सांस्कृतिक विरासत को क्षति पहुंचाता हो या इसका इरादा किसी देश में विद्रोह भड़काना हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के अनुच्छेद 3/1556 में आतंकवाद को परिभाषित करते हुए इस प्रकार के कृत्यों के लिये राष्ट्र को नियंत्रण हेतु उपाय करने, अपराध हेतु सजा के प्रावधान निर्देशित किये गये हैं यदि ऐसे कृत्य जो आपराधिक हो, नागरिकों के विरूद्ध या उनको हानि पहुंचाने हेतु संपादित किये गये हो, विद्रोह भड़काते हों, सांस्कृतिक विरासत को हानि पहुंचाते हो, किसी देश के राजनीतिक, दार्शनिक, विचारधारात्मक, प्रजातिवाद, धार्मिक ढांचे को हानि पहुंचाते हो। इस परिभाषा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में न केवल नामित किया गया बल्कि राष्ट्रों को इस हेतु नियम बनाने हेतु निर्देश भी दिये गये। यूनाइटेड किंगडम ने 2000 में इसे राजनीतिक, धार्मिक, विचारधारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार पर

दबाव बनाने, जनता को प्रपीड़ित करने के रूप में चित्रित किया गया है।[5] यूनाईटेड स्टेट्स कोड के अनुसार ''पूर्व विचारित राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर हिंसा करना जिनमें गैर योद्धाओं को निशाना उपराष्ट्रवादी समूहों व गुप्त कार्यवाहियों द्वारा बनाया जाता है।''[6] भारत की दृष्टि में ''यह एक असामाजिक, असांस्कृतिक, असंवैधानिक, अनैतिक, अवांछनीय कार्यपद्धति है। जिसका उद्देश्य निरीह एवं निरपराध लोगों की हत्या करके सामान्य जनता में आतंक या दहशत फैलाकर कानूनों को धता बताते हुए अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सरकार को विवश करना है।''[7] अमरीका के अनुसार ''आतंकवाद से तात्पर्य हिंसा या धमकी से संबंधित उन सभी कार्यों से है जिसका उद्देश्य किसी राज्य या संगठन के हितों को क्षति पहुंचाना या उससे किसी प्रकार की रियायत पाना हो।''[8] अर्जेंटिना के अनुसार ''जो बमों व बंदूकों को प्रयोग में लाता है वही आतंकी कृत्य नहीं है बल्कि जो क्रिस्तानी धर्म, पश्चिमी सभ्यता के विरूद्ध विचारों का प्रसार करता है। वह भी आतंकवाद की ही श्रेणी में आता है।''[9] सीरियाई विदेश मंत्री वालिद मुअलम ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून में नागरिकों

की हत्या को भी आतंकवादी आक्रमण माना है।[10] विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों व विभिन्न राष्ट्रों के अलावा विभिन्न लेखकों द्वारा दी गयी परिभाषायें इस प्रकार हैं :–

ब्रुसहोफ्फमन तर्क देते हैं कि ''इसकी कुछ विशेषताओं को चिन्हित करना संभव नहीं है। इसमें लक्ष्यों का स्वरूप राजनीतिक होता है, हिंसा व हिंसा की धमकी साथ ही लक्ष्य की ओर मनोवैज्ञानिक प्रतिघात भी सम्मिलित रहते हें। यह एक संगइन द्वारा निर्देशित होता है जिनको निर्देश एक क्रम श्रृंखला में मिलते हैं, इसका ढांचा एक षड़यंत्रकारी या राजद्रोही होता है। उपराष्ट्रवादी समूहों व गैरराज्यीय समूहों द्वारा इसकी निरन्तर विद्यमानता रहती है।''[11] कार्सटीन बॉकस्टीट इसके मनोवैज्ञानिक व रणनीतिक पहलू की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके अनुसार ''यह राजनीतिक हिंसा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें अयौद्धेय लक्ष्यों का विनाश करते हुए आतंक व मनोवैज्ञानिक डर उत्पन्न किया जाता है। इसका उद्देश्य मध्यस्थों का दोहन करना है ताकि अधिकाधिक प्रचार के द्वारा शक्ति का विस्तार हो सके जिससे संक्षिप्त अवधि के राजनीतिक लक्ष्यों, राज्यों के

विलोपन के गतावधिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।''[12] वाल्टर लॉकर के अनुसार ''यह शक्ति का तर्क विरूद्ध प्रयोग है जिससे राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके जबकि मासूम लोक केवल निशाना बनाये जाते हैं''[13] शिमिड व जोंगमन आतंकवाद को एक उत्कंठा बताते हैं। उनके अनुसार, ''यह हिंसक गतिविधियों को प्रेरित करने का एक तरीका है जो कि गुप्त व्यक्ति समूहों, राज्यीय अभिकर्ताओं द्वारा संपादित किया जाता है जिसके धार्मिक, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। विरोध दर्शाना या हत्या करना हिंसा के परोक्ष लक्ष्य तो हो सकते हैं किन्तु मुख्य उद्देश्य नहीं। धमकी व हिंसा का प्रयोग इतने कुशल तरीके से किया जाता है कि यह संगठन, पीड़ित व्यक्तियों, मुख्य लक्ष्यों के मध्य वार्तालाप प्रक्रिया पर अवधारित किया जा सके ताकि इसको आतंक के लक्ष्य, मांगों के उद्देश्य, ध्यान आकृष्ट करने, अपने सिद्धान्तों के प्रचार की ओर मोड़ा जा सके।''[14] सरजी जागराइवास्की ने इसे शक्तिशाली के विरूद्ध कमजोर का सबसे निकृष्टतम हथियार माना है।[15] एल. अली खान ने आतंकवाद का जन्म असंतुष्ट समूहों द्वारा माना है। ये समूह दो अनिवार्य चारित्रिक गुण रखते

हैं, उनके विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। वे विश्वास करते हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का अनिवार्य साधन हिंसा है। आतंकी हिंसा में राजनीति का मात्रात्मक रूप से विद्यमान रहना उसका अन्य अपराधों से भेद करने की मुख्य वजह है।[16] जहां एक ओर रोजलिन हिगिंस के लिये यह एक ऐसा शब्द है जिसका कोई कानूनी महत्व नहीं है यह तो केवल राज्यों, व्यक्तियों के क्रियाकलापों की ओर संकेत करने का उपयुक्त रास्ता मात्र है, जिसमें अपनायी गयी पद्धति गैरकानूनी होती है।[17] वहीं दूसरी ओर डेविड रोडिन इसे शक्ति का सुविचारित, प्रमादयुक्त धृष्ट प्रयोग करते हैं जो राज्यों और गैर राज्यीय अभिकर्ताओं द्वारा विचारधारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गैर योद्धाओं के विरूद्ध किया जाता है।[18]

आतंकवाद का विस्तार

आज आतंकवाद के विश्वव्यापी रूप ग्रहण करने के कारण यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, अल्जीरिया, सऊदी अरब, मिस्त्र, मनीला, ट्यूनिश, लीबिया, लेबनान, जोर्डन, तुर्की, मैक्सिको, इजरायल,

फ्रांस, इटली, उत्तरी आयरलैंड, फिलीस्तीन, कम्पूचिया तक फैला है। आज इसका जूनूनी रूप इस्लामिक आतंकवाद के रूप में सामने आया है। किंतु पूर्ववर्ती दो शताब्दियों के आतंकवाद पर दृष्टिपात किया जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न कारणों के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। इसका ऐतिहासिक विकास यह दर्शाता है कि यह परिवर्तन का साधन या उपकरण है। इसका प्रयोग न केवल धार्मिकों बल्कि अधार्मिकों द्वारा भी किया जाता रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं है और न ही इसका प्रयोग यहूदियों, मुस्लिमों के लिये नया है। यह कम से कम 1500 वर्ष पुराना है। जहां एक ओर यहूदी जीलट समूह द्वारा इसका प्रयोग रोमन लोगों के विरूद्ध किया गया वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों द्वारा इसका प्रयोग एक–दूसरे की बाधा बनने के लिये किया गया। यहूदी लोगों का समूह जिसे ईसा पूर्व जीलट् के रूप में जाना गया जो रोमन सैनिकों व संपत्ति को विनष्ट करता था।[19] इसके शुरूआती दौर में आतंकवाद व धर्म साथ–साथ चलते थे। ईश्वर की सेवा के नाम शहीद होना, उसके शत्रुओं के विरूद्ध लड़ते हुये मरने की धारणा एक हजार वर्ष

पूर्व विद्यमान थी। उस समय शत्रु का विरोधी होना एक धार्मिक कृत्य था जो पवित्र समझा जाता था। उस समय ऐसा ही एक समूह हश–ए–शिन (1095–1291) था जो आतंक इसलिये फैलाता था ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो सके।[20] इसका आधुनिक विचार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान माना जा सकता है, जब आतंक का शासन (1793–94) बढ़ा। इस दौरान आतंकवाद सरकार द्वारा प्रायोजित था जिसका उद्देश्य विरोधियों को बाहर निकाल फैंकना तथा अपनी शक्तियों को पुष्ट करना था। रॉब्सपीयर व जेकोबियन पार्टी द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। रॉब्सपीयर ने इसे प्रभावी गुण बताया जो शासकीय उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन बना और अक्सर इसका प्रयोग विपक्ष को दबाने के लिये किया गया। इस प्रकार इस युग में आतंकवाद शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो गया।[21] 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध व बीसवीं सदी के प्रारम्भ में आतंकवाद का व्यक्तिगत स्वरूप दिखाई पड़ता है जिसमें सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणीत करते हुए मिखइल बाकुनिन (1814–1876), कार्लो पिकासने (1818–1857) द्वारा इसे विस्तारित

किया गया।[22] इस अवधि के दौरान अराजकतावादी सक्रिय रहे। इनके द्वारा जार शासकों, अन्य राजाओं, यूरोप के संभ्रांत वर्ग के लोगों की हत्या करके सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। जैसे चाहे रूस में Narodnayavolya क्रांतिकारी अराजकतावादी समूह द्वारा रूस के जार को निशाना बनाया जाना हो या फिर 13 मार्च 1881 को एलिक्जेंडर द्वितीय की हत्या करना हो इस अवधि में की गयी हत्याओं में से कुछ का विवरण इस प्रकार है :– 1894 से 1896 के मध्य फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंको कार्नोट, स्पेन के प्रधानमंत्री एंटीनियो केनोवोस डी केसेलियो, आस्ट्रेलिया हंगरी की साम्राज्ञी एलिजाबेथ बेवेरिया अराजकतावादियों द्वारा मारे गये। 1890 से 1908 के दौरान अराजकतावादियों द्वारा रूस, आस्ट्रिया, हंगरी, इटली, पुर्तगाल के अनेक शासकों जैसे इटली के अंब्रटो प्रथम जुलाई 1900 में, साम्राज्यवादी रूस के प्रधानमंत्री प्योर्टर स्टॉलीपिन 1911 में, 28 जून 1914 को आस्ट्रेलिया के आर्कड्यूक फर्डनेण्ड की हत्या कर दी गयी। अराजकतावादियों द्वारा किये गये दो प्रमुख कृत्य राष्ट्रपति एम.सी. किनले (1901) व आर्कड्यूक फर्डीनेंड (1914) की हत्या है। ये न केवल यूरोप

बल्कि संयुक्त राज्य अमरीका में भी सक्रिय रहे। 1890 से 1910 के दौरान वालस्ट्रीट में किये गये विस्फोट इनकी भयावहता को उजागर करते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में इसका प्रयोग समाज को व्यवस्थित करने व नियंत्रण हेतु किया गया। रूसी क्रांति (1917) ने शासक द्वारा प्रायोजित आतंक का विचार एक साधन के रूप में रखा ताकि शासकीय नियंत्रण को बनाये रखा जा सके। इस अवधि में आतंकवाद का प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। जैसे आयरलैंड का विद्रोह (1919–21) जिसका नेतृत्व माइकेल कॉलिन्स द्वारा आयरलैंड को ब्रिटेन से स्वतंत्र कराने हेतु किया गया। इरगुन, लेही, इजाद–दिन–अल–रसाम आदि ने आतंक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतंकवाद की अवधारणा को सरकार के प्रतिनिधियों के विरूद्ध लागू करते हुये 6 नवंबर 1944 को ब्रिटिश मंत्री लार्ड मोयने की हत्या कर दी गयी। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर तृतीय विश्व में यह एक साधन के रूप में आजादी व उपनिवेशवाद की समाप्ति की मांग करता था। 1960 की कालावधि में यह विस्तार की परिवर्तित स्थिति में प्रवेश करता है। अब इसका केंद्र बिंदू मध्यपूर्व था। मिस्त्र, सीरिया, पूर्वी यरूशलम, गाजापट्टी,

सिनाई, जोर्डन आदि देशों का आतंक फैलाने का उद्देश्य केवल इजरायल पर ध्यान केंद्रित करना था। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रारंभ 1966 में क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा आयोजित त्रिमहाद्वीपीय सम्मेलन से माना जा सकता है। शीतयुद्ध के दौरान संसार के दो खेमों पूर्व व पश्चिम में विभक्त हो जाने के फलस्वरूप आतंकवाद का एक और नया रूप राज्य प्रायोजित आतंकवाद के रूप में सामने आता है। जिसे निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दुनियां के हिस्सों में फैलाया गया। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, मध्यपूर्व, लेटिन अमरीका आदि द्वारा सामूहिक कार्य पद्धति को अपनाते हुये संगठन निर्मित किये गये। जैसे जर्मनी में दि रेड आर्मी का ब्लेक सेपटेंबर (फिलीस्तीनी समूह) के साथ गठजोड़, जापान में रेड आर्मी ब्रिगेड, ईरान में हिज बलाह, लीबिया में अबु निदाल, अलजीरिया में नेशनल लिबरेशन फ्रंट, अरमीनिया सेना (1975), तुर्की में कुर्दीस्तान मजदूर दल, पीपुल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान, मुजाहिदीन–ए–खाक आदि समूहों के अलावा माओ की चीन में क्रांति (1949), कास्त्रो की क्यूबा में क्रांति (1959) आदि भी इस अवधि की महत्वपूर्ण घटनायें रही। इसके अलावा श्रीलंका में लिट्टे, अफ्रीका में

अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की एक सैन्य शाखा Umkhonto we sizwe 1961 में स्थापित की गयी।[23] 1970 के दशक के दौरान आतंकवाद की चरम् पराकाष्ठा वायु दुर्घटनाओं के रूप में सामने आयी। 1985 में एयरइंडिया के विमान में विस्फोट 9/11 से पहले का सबसे घिनौना कृत्य था। 1960 से 1980 तक का आतंकवाद का सफर केवल किसी एक कारण को प्रदर्शित करता था। किंतु अब इसके परिवर्तित स्वरूप के कारण इसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाने लगा। जहां एक ओर ईरान में 1979 में अय तोलाह खोमीनी के उदय के साथ ही धर्म आधारित आतंकवाद की पुनः वापसी हुयी तो दूसरी ओर अमरीका के हितों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करने हेतु बम विस्फोटों, आत्मघाती हमलों, वायुयान अधिग्रहणों के रूप में सामने आया।[24] चाहे घटना न्यूयार्क की हो या फिर दिल्ली, मुंबई, इस्तांबुल की हो, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रमुख अध्येता ब्रिया क्रोजर का मानना है कि बीसवीं शताब्दी का आतंकवाद अपने स्वरूप में विश्वपरक है। इसका कोई धर्म या मजहब नहीं है, वह केवल मानवता के विरूद्ध अपराध है जिसे छिपाने के लिये धर्म के मुखौटे का इस्तेमाल

किया जाता है। यह ऐसी अमरबेल के समान है जो बिना जड़ों के भी दूसरों के सहारे जिंदा रहता है।

आतंकवाद के प्रमुख कारण

आतंकवाद का जन्म अचानक नहीं होता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियां ही इसका आधार होती हैं। इसके कारणों के संदर्भ में किया गया विश्लेषण विरोधाभास से परे है। विशेषतः सीमा पार के अध्ययन के संदर्भ में किसी ठोस तथ्य की अब तक दरकार है। विगत वर्षों में इसके कारणों का पता लगाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अनेक ऐसी परिस्थितियां सामने आयी है जिन्होंनें आतंकवाद रूपी अग्नि को सुलगाया है। किंतु फिर भी यह धनी व निर्धन, आधुनिक औद्योगिक संसार व अल्पविकसित क्षेत्रों आदि में कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। यह संरचनात्मक, तकनीकी या ढांचागत अव्यवस्थाओं के रूप में भी सामने आ सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारणों का विश्लेषण करने पर निम्नांकित तथ्य सामने आये हैं। :– राज्यों के सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों के कारण आतंकवाद को प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाता है।

द्वितीय विश्व युद्धोपरांत शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों ने अपने विरोधी खेमों के देशों में वहां के विद्रोही संगठनों अथवा बाहर के असैनिक दस्तों के द्वारा अपनी सामरिक कार्यवाहियों का संचालन करने में सहयोग किया गया था। महाशक्तियां अपनी स्वार्थपूर्ति व शक्ति ध्रुवीकरण को अपने पक्ष में करने के लिये आतंकवादी गुटों को गुप्त रूप से सहायता देती है। जैसे – निकारगुआ में कोन्ट्रा विद्रोही, फिलीपींस में नेशनल पीपुल्स आर्मी, अफगानिस्तान के मुजाहिदीन आदि। शक्ति सामर्थ्य की प्रधानता के आधार पर सितंबर 2011 के बाद संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उन सभी कमजोर राष्ट्रों को निशाना बनाया गया जहां अलकायदा व इस्लामी गुरिल्लाओं की जड़ें जमी हुयी थी जैसे अफगानिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान, सोमालिया, यमन, जोर्जिया, फिलीपींस आदि में। लेक व रोथचाइल्ड का मत है कि राज्य असमर्थता की स्थिति ही हिंसक संघर्षों की पूर्व अवस्था है।[25] शक्ति सम्पन्न राष्ट्र तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुये आतंकवादी नेटवर्कों को निष्क्रिय कर सकते हैं।

पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने अपनी पुस्तक फाइटिंग टेर्ररिज्म : हाउ डेमोक्रेसीज केन डिफीट दि इंटरनेशनल टेर्ररिस्ट नेटवर्क में दावा किया है कि यदि संप्रभूता संपन्न राष्ट्रों का सहयोग न हो तो अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।[26] विविध इस्लामिक समूहों का भारत में अधिकृत कश्मीर में अपने कृत्यों का संचालन सहायता के बिना संभव नहीं है।

वर्तमान में अन्तराष्ट्रीय परिदृश्य भूमण्डलीकरण का है। इस शब्द का प्रयोग कई तरह से हुआ है। एक अर्थ तो शाब्दिक है कि अब राष्ट्रों के बीच दूरी बेमानी हो चुकी है। कोई देश अपना नुकसान करके ही शेष विश्व से खुद को अलग रख सकता है। इसका दूसरा अर्थ इसके ठीक विपरीत निकाला जा रहा है। यह देशी हितों के स्थान पर दूसरे देशों और बहुराष्ट्रीय नियमों के हितों को ऊपर रखने वाले नीतिगत बदलाव का नाम है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि रिपोर्ट 6 सितंबर 2006 में स्पष्ट कहा है कि वैश्विक बाजार को अब तक सहभागी सामाजिक लक्ष्यों पर आधारित नियमों की अधीन नहीं किया गया

है। आज भी विकसित देशों में प्रवासियों के प्रति नकारात्मक रवैया वहां की राजनीतिक, सामाजिक सोच में गहरे बैठा है। ऐसा माना जाता है कि प्रवासी वहां के मूल निवासियों के राजनीतिक वर्चस्व में सेंध लगा देंगे या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक एकता पर हमला कर देंगे। ऐसी मान्यतायें भी है जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन नस्लवाद की राजनीति करने वालों को वे एक हथियार पकड़ा देती है। भूमण्डलीकरण के चलते राष्ट्रों व लोगों के आय स्तरों के बीच की खाई पिछले 25 वर्षों में गहराती गई है। विकासशील व विकसित देशों के इस द्वन्द्व में जीतने वाले राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिमी यूरोप, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया का नाम आता है। पिछड़ने वाले देशों में लेटिन अमरीका, अफ्रीका, पश्चिमी व दक्षिणी एशिया क्षेत्र के देश हैं। अन्तर्राष्टीय व्यापार व अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश के लिये देश के दरवाजे खोलने का अर्थ गरीब व अमीर देशों को बाघ व बकरी की तरह एक ही घाट का पानी पीने की व्यवस्था करना है। लाभ वितरण में असमानता को बढ़ावा मिलने से अमीर तो अमीर, गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। पहचान के लिये लोगों को भ्रमित

करने का काम विप्लववादी करते हैं जो सिर्फ हिंसा को बढ़ावा देते हैं।[27]

आधुनिकीकरण ने समाजों को विचारधारात्मक आतंकवाद के लिये उन्मुक्त वातावरण प्रदान किया है। समाज में व्याप्त असंगठित आध ुनिकीकरण जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करना, सामाजिक असमानतायें, पर्यावरणीय क्षति, मिश्रित बाजारू समाजों का उदय, गरीबी व अल्पविकास तृतीय विश्व में गृहयुद्धों का जन्मदाता है। 'पोलिटिकल ऑर्डर इन चैंजिंग सोसायटीज' में बताया है कि आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमरीकी देशों में तीव्र गति से फैली है। किंतु राजनीतिक संरचनाओं का विकास उस स्तर पर नहीं हुआ अतः यह अस्थिर राजनीति व हिंसा हेतु जिम्मेदार है।[28]

समान योग्यता होने पर भी असमानता की स्थिति पर टीड राबर्ट गुर ने 1970 में 'व्हाई मेन रिबेल' में व्याख्या दी है कि यह एक शब्द है जो उस चिंता को सूचित करता है जो उस भेद के कारण विकसित होती है जो

'चाहिये' व 'है' के मध्य है। संतुष्टों व असंतुष्टों के मध्य का यही अंतर आतंक की उत्पत्ति है। अरस्तू का भी मत था कि क्रांति असमानता की भावना से उत्पन्न होती है।

संचार तकनीकी क्षेत्र में प्रगति को विचारों को समाज में आतंक को बढ़ावा देने वाले कारकों में सम्मिलित किया है। जिसमें मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण व शहरीकरण शामिल है। शहर महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि वे अवसर उपलब्ध कराते हैं। जहां लक्ष्यी भीड़, संचार, श्रोता वर्ग आसानी से उपलब्ध रहते हैं। किंग्ले तर्क देते हैं कि वायु संचार एक आसान लक्ष्य है जो संपूर्ण विश्व पर गतिशीलता प्रवृत्त करने में मदद करता है। रेडियो, टेलीविजन, आधुनिक संचार उपग्रह तत्काल सूचना को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। हथियार व विस्फोटक सामग्री की तेजी से बढ़ती उपलब्धता, रिमोट आधारित विस्फोटकों को आधुनिक शहरी समाज भी असीम भेद्य लक्ष्य उपलब्ध करा देते हैं। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक खेलों के दौरान उत्पन्न आतंक का प्रचार करने में भी मीडिया

की अहम भूमिका थी। रूस में नवस्थापित रेल मार्ग व्यवस्था के बिना Narodnaya Volya समूह के सदस्य अपने कार्यों का संचालन नहीं कर सकते थे।

नवस्थापित विकसित प्रजातंत्रीय शासनों में स्वतंत्रता की धारणा, मानवाधिकारों की पृष्ठभूमि में असामाजिक तत्वों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। प्रजातंत्रीय देश जहां मुक्त भाषण की लम्बी परंपरायें रही हों उनको घरेलू व विदेशी आतंकवाद का निशाना अधिक बनाया जाता है। न केवल संयुक्त राज्य अमरीका बल्कि कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, ईटली, स्पेन, तुर्की, भारत आदि में भी यह प्रबल है।

गरीब व कमजोर राष्ट्रों की लगभग आधी जनसंख्या गरीबी में पिसती रही है। लगभग विश्व के तीस खरब लोग अपना गुजारा दो डॉलर प्रतिदिन व 730 डॉलर प्रतिवर्ष पर करने को मजबूर हैं। दक्षिणी एशिया, अफ्रीका सरीखे राष्ट्रों में नागरिकों को भोजन, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की दरकार है। जहां पर मानवीय आवश्यकतायें ज्यादा हों वहां लोक उस ओर प्रवृत्त हो जाते हैं जो उनकी मदद करते हैं।

उन गरीब देशों में कानून, पुलिस, खुफिया तंत्रों, सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमजोरी के कारण वे अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं कर सकते वहां पर सामाजिक अक्षमता, अन्याय जिनसे कि समाज व्यथित रहता है। पर अन्हें राजनीतिक दबावों से कुचल दिया है, यही सब कृत्य आतंकवादी समूहों के लिए प्राणवायु बन जाते हैं। 'इसी आधार पर विश्व के लगभग बावन देश ऐसे सामने आये हैं जो कमजोर हैं उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं :– जैसे अफ्रीका, मध्य ऐशिया, दक्षिणी एशिया, अफगानिस्तान, अंगोला, बांग्लादेश, कंबोडिया, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र, कांगो गणतंत्र, इथोपिया, गुएना, हेती, इराक, केन्या, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यूगनी, रवाण्डा, सियरा लिओन, सोमालिया, सूडान, तजाकिस्तान, तंजानिया, टोगो, युगाण्डा, उजबेकिस्तान, यमन, जिंबाब्वे आदि।'[29] सामाजिक व आर्थिक असमानता, धार्मिक विभाजन, समुदाय का निम्न स्तर आदि की चरम परिणिती भले ही हिंसक युद्धों के रूप में होती है। किंतु यह तथ्य है कि आत्मघाती दस्ते, नेटवर्कों को संचालित करते आतंकी गरीब परिवारों

से न आकर मध्यमवर्गीय परिवारों से आये हैं जिनके पास तकनीकी, मेडिकल क्षेत्र की डिग्रियां हैं। क्रूजर व मेलेकोवा का दावा है कि केवल गरीबी को हटाकर आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अन्तर्राज्यीय युद्धों में कुछ संदेह इस बात पर हो सकता है कि केवल गरीबी ही मूल तत्व है जो गृहयुद्धों को भड़काता हो। सोमालिया, सियरा लिओन, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणतंत्र जैसे देशों में पिछले सात वर्षों (1998–2004) के कालखण्ड में केवल एक से लेकर ग्यारह आतंकी घटनायें ही हुयी हैं जबकि वहां तो गृहयुद्धों का क्षेत्र विस्तृत है। वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीब भाग उपसहारीय अफ्रीका में आतंकवाद कुछ ही सीमा तक है। जबकि आतंकवाद में नागरिकों की लिप्तता विकसित देशों में ज्यादा है। यद्यपि युगाण्डा ऐसा देश है जहां अत्यधिक गरीबी ही आतंकवाद का कारण है, फिलीस्तीन इजरायली युद्ध में भी गरीबी ही प्रेरित कारण रहा है फिर भी आर्थिक विकास की बढ़ती हुयी दर के माध्यम से गरीबी पर नियंत्रण कर गृहयुद्धों को रोका जा सकता है। एक औसत देश जहां सकल घरेलू उत्पाद दर प्रति व्यक्ति 250 डॉलर हो वहां अगले

पांच वर्षों में गृहयुद्धों की संभावना पंद्रह प्रतिशत रहेगी लेकिन वह देश जहां सकल घरेलू उत्पाद दर पांच हजार डॉलर प्रति व्यक्ति हो वहां गृहयुद्धों की संभावना एक प्रतिशत ही हो जाती है। इस प्रकार तीव्र आर्थिक विकास गरीबी का समाधान कर आतंकवाद का खात्मा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

विश्व की प्रमुख आतंकवादी घटनायें

1800 से अब तक वर्ष 2013 के अप्रेल माह तक के वैश्विक परिदृश्य पर नजर डाली जाये तो आतंकवाद से अब तक लगभग 2799 घटनाओं में 47035 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं व 1,05,711 लोग घायल हुये हैं, जिन्हें अग्रांकित सारणी के माध्यम से समझा जा सकता है :–

वर्ष	कुल घटनायें	कुल मारे गये लोग	घायल
1800—1899	2	300	20
1900—1949	11	332	917
1970	10	88	90
1971	4	31	2
1972	16	103	222
1973	13	154	75
1974	20	234	818
1975	14	94	286
1976	13	194	120
1977	14	130	41
1978	10	164	195
1979	11	274	6
1980	12	142	573
1981	13	259	651
1982	15	237	881

वर्ष	कुल घटनायें	कुल मारे गये लोग	घायल
1983	18	6940	815
1984	25	194	1568
1985	28	922	755
1986	24	274	682
1987	13	291	723
1988	15	130	165
1989	30	329	1325
1990	24	429	478
1991	12	119	171
1992	16	100	726
1993	22	363	2755
1994	22	468	1637
1995	39	761	2385
1996	23	718	2274
1997	12	270	713
1998	15	3878	4128
1999	25	456	394
2000	184	695	2768

वर्ष	कुल घटनायें	कुल मारे गये लोग	घायल
2001	56	3459	1297
2002	86	1322	2428
2003	47	642	3147
2004	344	2986	17281
2005	115	449	1906
2006	71	1097	2250
2007	120	2511	4273
2008	315	3572	8456
2009	289	3097	8316
2010	106	902	3988
2011	285	3361	6205
2012	253	4251	10899
आंकड़े अप्रेल 2013 तक	70	2315	5460

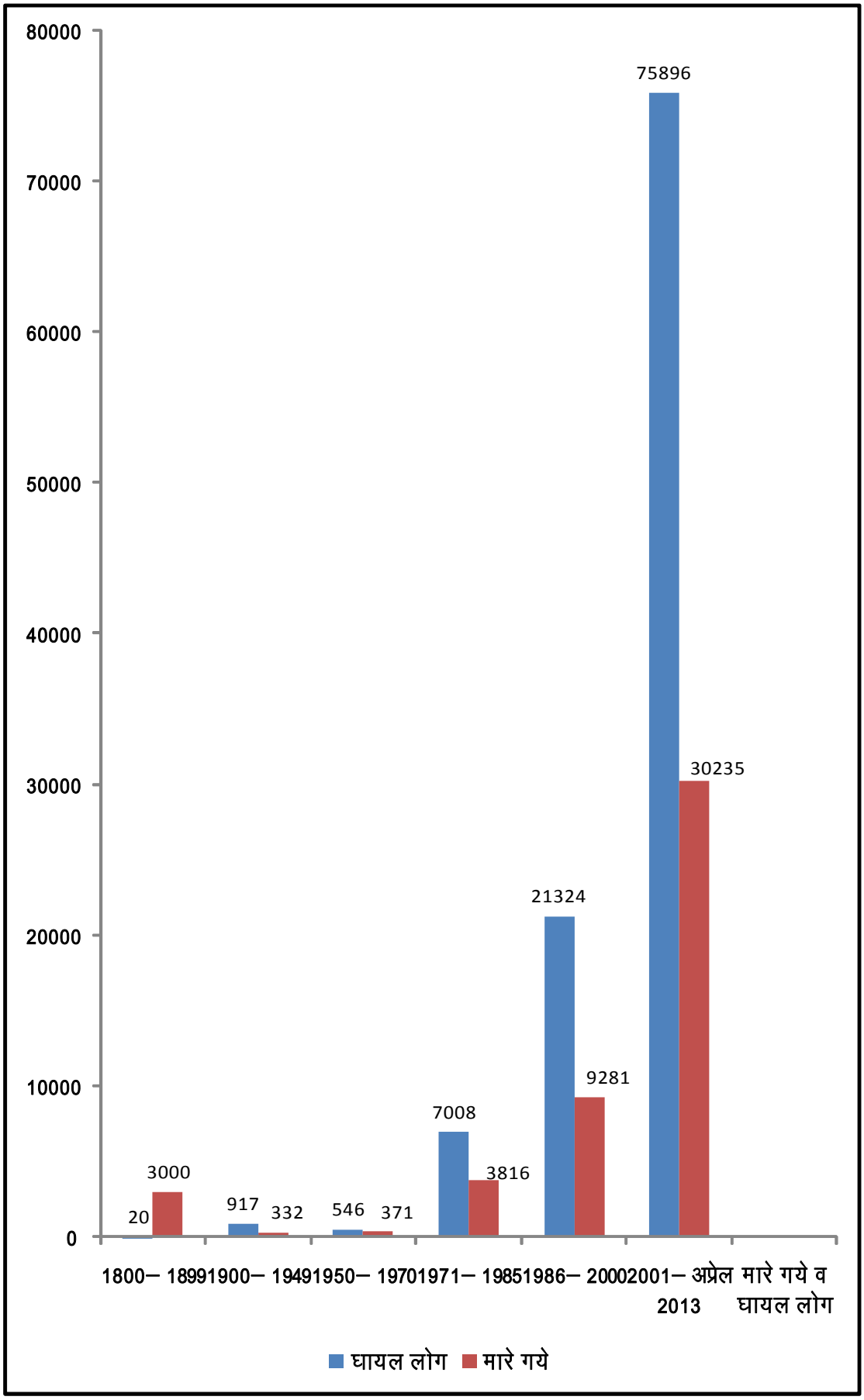
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
75896
30235
21324
9281
7008
3816
3000
20
917
332
546
371
1800– 1899
1900– 1949
1950– 1970
1971– 1985
1986– 2000
2001– 2013
अप्रेल मारे गये व घायल लोग
घायल लोग
मारे गये

विश्व की प्रमुख आतंकवादी घटनाओं का वर्णन इस प्रकार है :–

संयुक्त राज्य अमरीका में 1865 से 1877 के दौरान Kukluxkian द्वारा तीन हजार लोगों की हत्या कर दी गयी। 9 दिसंबर 1893 को फ्रांस में फ्रांसीसी अराजकतावादियों द्वारा की गयी हिंसा में बीस लोग घायल हुये। 1903 में तुर्की साम्राज्य में अराजकतावादियों द्वारा हिंसा का प्रदर्शन किया गया। 18 मई 1904 को मोरक्को में क्रोमवेल वार्ले का अपहरण किया गया। 1 दिसंबर 1910 को लॉए एंजिल्स संयुक्त राज्य अमरीका में बम विस्फोट में इक्कीस लोग मारे गये, सौ घायल हुए। 16 सितंबर 1920 को संयुक्त राज्य अमरीका वाल स्ट्रीट विस्फोट में अड़तीस लोगों की मौत हो गयी, तीन सौ घायल हुए। 13 दिसंबर 1921 को रोमानिया में सैनिकों व पुलिस अफसरों समेत सौ लोग बम विस्फोट में मारे गए। 16 अप्रेल 1925 को बुल्गारिया चर्च पर बुल्गारिया कम्युनिष्ट दल द्वारा आग लगा दी गयी जिसमें पाँच सौ लोग घायल हुए, एक सौ पचास की मौत हो गयी। 3 मार्च 1940 को स्वीडन में राजनीति से प्रेरित विस्फोटों में दो की मौत, पांच अन्य घायल हुए। 4 जुलाई 1940 को न्यूयार्क विश्व मेले में विस्फोट में दो

पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी। 2 जुलाई 1947 को रोमानिया में तीन आतंकियों द्वारा किये गये हमले में एक एयर क्रू सदस्य की मौत हुयी। 5 अगस्त 1949 को सीरिया में हुये हमले में बारह लोग मारे गये, एक दर्जन से ज्यादा घायल हुए। 7 मई 1949 को फिलीपींस में फिलीपींस एयर लाइन के विमान विस्फोट में तेरह लोगों की मौत हो गयी। 1 नवंबर 1955 को संयुक्त राज्य अमरीका में यूनाईटेड एयर लाइन विमान 629 में विस्फोट होने से चंवालीस लोग मारे गए। 5 मार्च 1960 को क्यूबा में फ्रांसीसी लड़ाकों ने सौ लोगों को मौत के घाट उतार दिया व दो सौ घायल हुए। 26 जून 1965 को दक्षिणी वियतनाम में विस्फोट में बयांलीस लोग मारे गये, अस्सी घायल हुए। 30 मई 1972 को इजरायल में जापानी रेड आर्मी ने छब्बीस लोगों को मार डाला, अठहत्तर को घायल कर दिया। 28 मई 1974 को इटली में पियाजा डेला लोजिया बम विस्फोट में आठ लोग मारे गये व नब्बे घायल घोषित किए गए। 15 दिसंबर 1976 को अर्जेंटीना में रक्षा मंत्रालय की तीसरी मंजिल पर गुरिल्ला समूह द्वारा किये

गये विस्फोट में पंद्रह लोग मारे गये व तीस घायल हुए। 11 मार्च 1978 को इजरायल में बस में सवार अड़तीस इजरायली नागरिकों की आतंकियों द्वारा हत्या, इकहत्तर को घायल कर दिया गया। 31 दिसंबर 1980 को नेरोबी, केन्या में नोरफोल्क होटल में विस्फोट में पंद्रह लोग मारे गये व पिच्यासी घायल हुए। 1 अक्टूबर 1982 को एयर इंडिया विमान 182 पर बब्बर खालसा द्वारा जंबोजेट 747 से किया गया प्रथम आक्रमण था जिसमें सभी तीन सौ उनतीस यात्रियों की मौत हो गयी। 26 फरवरी 1993 को विश्व व्यापार संगठन न्यूयार्क पर यूरिया नाइट्रेट हाइड्रोजन से किया गया हमला जिसका लक्ष्य तो भवन के दोनों टावरों को क्षतिग्रस्त करना, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देना था किंतु यह सफल नहीं हो सका। 12 मार्च 1993 को मुंबई हमला जिसमें तेरह बम विस्फोट सिलसिलेवार किये गये। ऐसा माना जाता है कि 1992 के बंबई दंगें जिनमें हिंदुओं द्वारा पांच सौ पिचहत्तर मुस्लिमों को मार गिराया था, के प्रतिउत्तर में दाऊद इब्राहिम द्वारा प्रायोजित थे। 31 जनवरी 1996 को कोलंबो में पृथकतावादियों द्वारा किया गया विस्फोट जो कि वहां की सरकार व तमिल चीतों के बीच छिड़े

युद्ध की बर्बरता को व्यक्त करता है जिसमें कम से कम सौ लोग अपनी आँखें खो चुके थे, इकरानवे लोग मारे गये व चौदह सौ घायल हुये। 11 सितंबर 2001 को न्यूयार्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर चार वाणिज्यिक जेट विमानों द्वारा किया गया हमला, अमरीकी एयरलाइंस विमान 11, युनाइटेड एयरलाइंस 175 आदि ने क्रमशः प्रातः 8:50 व 9:04 बजे दो टावरों को मिट्टी में मिला दिया, लगभग तीन हजार लोगों की जान का दुश्मन बना यह हमला आतंकवाद की भयावहता की चरम पराकाष्ठा थी। 11 मार्च 2004 को मेड्रिड रेल बम विस्फोट स्पेन में प्रातः 7:30–8:00 के दौरान स्पेन आम चुनावों से ठीक तीन दिन पहले किया गया, इसमें दो हजार पचास लोग घायल हुये व एक सौ इकरानवे मारे गये। 7 जुलाई, 2005 को प्रातः 8:50 से 9:47 के दौरान लंदन में चार इस्लामियों द्वारा आत्मघाती हमले करते हुये बावन लोगों को मार दिया गया व लगभग सात सौ घायल हुये। 11 जुलाई 2006 को मंगलवार के दिन सात बम विस्फोट श्रृंखलाबद्ध रूप से ग्यारह मिनट की अवधि में मुंबई में घटित हुये। इसमें सात सौ लोग घायल हुये व दो सौ नौ लोग मारे गये। 30

अक्टूबर 2008 को गुवाहाटी के बाजार में उल्फा, हुजी संगठनों द्वारा विस्फोट किये गये, इस कुकृत्य में सतत्तर की मृत्यु व चार सौ सत्तर घायल हुये। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी घुसपैठियों ने लगभग ग्यारह विस्फोट करते हुए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल व ओबेरॉय होटलों, नरीमन हाउस, कामा अस्पताल, मेट्रो सिनेमा, सेंट जेवियर कॉलेज, विले पार्ले आदि जगहों पर भारी उत्पात मचाते हुये लगभग एक सौ पिचयानवे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तीन सौ आठ घायल हुये। यह हमला लश्कर–ए–तैयबा द्वारा प्रायोजित था। 8 दिसंबर 2009 को मुल्तान शहर में पाकिस्तानी सुरक्षा में विस्फोट में चार सौ अड़तालीस लोग घायल हुये, नौ की मौत हो गई। 15 जुलाई 2010 को दो आत्मघाती दस्तों द्वारा शिया लोगों पर ब्लूचिस्तान में हमला इसलिए किया गया क्योंकि वे जामिया मस्जिद में मुस्लिम संत का जन्म दिवस मना रहे थे। इसमें दो सौ सत्तर लोग घायल हुये व सत्ताईस की मौत हो गई। 7 सितम्बर 2011 को बगदाद, इराक में सोलह बम धमाकों में बहत्तर लोग मारे गये, एक सौ उनहत्तर घायल हुये। 4 मार्च 2012 को कांगों की राजधानी ब्रेजविले में

लगातार हुये बम धमाकों में करीब पंद्रह लोग घायल व दो सौ की मौत हो गयी। राजधानी के पास स्थित सैनिक प्रतिष्ठान के हथियार डिपो में आग लगाने के बाद एक के बाद कई धमाकों से कांगो दहल उठा। 15 अप्रेल 2012 को अफगानिस्तान में बारह जगहों पर हमले किये गये। काबुल में संसद भवन, जर्मनी, अमरीका, रूस, ब्रिटेन के दूतावासों पर राकेट ग्रेनेड, मशीनगनों से फायर किये गये जिनमें सोलह लोग मारे गये। इसका उद्देश्य विदेशी सेनाओं की वापसी से पहले तालिबान द्वारा अपनी ताकत दिखाना था। 10 मई 2012 को दमिश्क, सीरिया में दो शक्तिशाली बम धमाकों में पचपन लोगों की मौत हो गयी, तीन सौ सत्तर से ज्यादा घायल हो गये। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद, भारत में दो बम विस्फोटों में सत्रह की मौत, एक सौ उन्नीस घायल हुए। 13 मार्च 2013 को श्रीनगर, भारत में सी.आर.पी.एफ. केंप पर हमले में पांच लोगों की मौत हुयी, दस अन्य घायल हुए। 16 अप्रेल 2013 को बंगलुरू में एक दुपहिया वाहन विस्फोट में ग्यारह पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी व पाँच अन्य घायल हुये।

संदर्भ सूची

1. के.आर. गुप्ता, ग्लोबल टेर्ररिज्म, पृष्ठ 1
2. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी एवं डॉ. एम.पी. राय, भारतीय सरकार एवं राजनीति, पृष्ठ 559
3. आर्टिकल (a), कन्वेंशन ऑफ 1970
4. ऑफिशियल जर्नल ऑफ दि यूरोपियन कम्यूनिटीज, 22.6.2002
5. यूनाइटेड किंगडम टेर्ररिस्ट एक्ट, 2000
6. शीर्षक 22, U.S.C. सेक्शन 2656 F(d)
7. प्रतियोगिता दर्पण, 12 फरवरी 2012
8. प्रतियोगिता दर्पण, 12 फरवरी 2012
9. अर्जेंटीनियन नेशनल रिऑर्गेनाइजेशन प्रेसेस डिक्टेटरशिप जो 1976 से 1983 तक चली
10. अबुकमल के शासन पर अमरीकी आक्रमण के संदर्भ में, टेर्ररिस्ट यू. एस. 28.10.2008
11. ब्रुसहोफ्फमन, इन्साइड टेर्ररिज्म, सेकण्ड एडिसन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006, पृष्ठ 41

12. कांर्सटीन बॉकस्टीट, जार्ज सी. मार्शल सेंटर ओकेशनल पेपर सीरीज (20), 2008

13. वाल्टर लॉकर, ए ऐज ऑफ टेर्ररिज्म, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी पब्लिशिंग, 2002, पृष्ठ 8

14. शिमिड व जोंगमन, एटअल पोलिटिकल टेर्ररिज्म : ए न्यू गाइड, नॉर्थ हॉलेण्ड ट्रांजेक्सन बुक्स 1988, पृष्ठ 28

15. सरजी जागराइवस्की, 365 रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन एंड ह्यूमेनिटी

16. अलीखान, ए लीगल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल टेर्ररिज्म, कनेक्टीकट ला रिव्यू 1987, वॉल्यूम 19, पृष्ठ 945

17. रोजलिन हिगिंस एवं एम, फलोरी, इंटरनेशनल ला एंड टेर्ररिज्म, 1997, पृष्ठ 28

18. शिकागो जर्नल, एथिक्स, 114, जुलाई 2004, पृष्ठ 647–649

19. ब्रुस होफ्फमन, इनसाइड टेर्ररिज्म, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1988, पृष्ठ 17

20. डेविड रेपोपोर्ड, फीयर एंड ट्रेंबलिंग : टेर्ररिज्म इन थ्री रिलिजीयस ट्रेडिशंस, अमरीकन पोलिटिकल साइंस रिव्यू, 1984, पृष्ठ 658

21. चालियन्ड गिर्राड, दि हिस्ट्री ऑफ टेर्ररिज्म : फ्रॉम एन्टीक्विटी टू अलकायदा, यूनिवर्सिटी ऑफ केलिफोर्निया प्रेस, 2007, पृष्ठ संख्या 68

22. चालियन्ड गिर्राड, दि हिस्ट्री ऑफ टेर्ररिज्म : फ्रॉम एन्टीक्विटी टू अलकायदा, 2007, पृष्ठ संख्या 116

23. (a) स्टोरा बेंजामिन, अल्जीरिया, 1830 – 2000 : ए शॉर्ट हिस्ट्री, कोरनेल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004, पृष्ठ 36 (b) तुर्कीश कुर्द : सम बेक दि स्टेट, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, 2007–07–06

24. (a) जमाइल धर, हज बुल्लाहाज ट्रांसफोरमेशन, एशिया टाइम्स, 2006–07–20

(b) फ्रंट लाइन टारगेट अमरीका : टेर्ररिस्ट अटेक्स ऑन अमरीकंस, 1979–1988

25. डेविड ए. लेक एवं डोनाल्ड रोथचाइल्ड, कन्टेनिंग फीयर : दि ओरिजंस एण्ड मेनेजमेंट ऑफ एथनिक कांफ्लिक्ट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, 1996, पृष्ठ 431–479

26. बेंजामिन नेतान्याहू, फाइटिंग, टेर्ररिज्म : हाउ डेमोक्रेसीज केन डिफीट दि इंटरनेशनल टेर्ररिस्ट नेटवर्क, पृष्ठ 13

27. ए सर्वे ऑफ थ्योरीज एण्ड हाइपोथीसिस ऑन द कॉजेज ऑफ टेर्ररिज्म, एफएफआई रिपोर्ट 02769, पृष्ठ 4

28. सैम्युअल पी अटिंग्टन, पोलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसायटीज, पृष्ठ 47

29. सुजान ई. राईस, ग्लोबल पावर्टी : वीक स्टेट्स एण्ड इनसिक्योरिटी, पृष्ठ 5, 6

तृतीय

अध्याय

भारतीय संदर्भ में आतंकवाद के कारण, विभिन्न राज्यों में उत्पन्न आतंकवाद, नक्सलवादी आतंकवाद व भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभाव

भारत में आतंकवाद के उदय के अनेक प्रत्यक्ष कारण विद्यमान हैं जिनकी सरलता से पहचान की जा सकती है। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें हमारे पड़ौसियों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही चुनौतियां दी जा रही हैं। न केवल बाहरी अपितु आतंरिक चुनौतियां भी कम नहीं रही हैं। कभी यह पृथक खालिस्तान तो कभी माओवाद और अब यह अपने नये रूप इस्लाम के रूप में सामने आया है। चाहे दंगे कलकत्ता (1946), भागलपुर (1989), हैदराबाद (1990), दिल्ली (1984), अयोध्या (1992), गुजरात (2002), के रहे हो या फिर कोई बाहरी व्यक्तियों द्वारा किये गये हमले जो बंबई, जयपुर, बंगलौर अहमदाबाद में घटित हुये, इन सबमें भारत में आतंकवाद का व्यापक विस्तार उजागर होता है। इसके प्रमुख कारणों को अग्रांकित रूप में रेखांकित किया जा सकता है :– भौगोलिक दृष्टि से हम पाकिस्तान से घिरे हुये हैं। पाकिस्तान अपनी स्थापना के समय से ही भारत के विरूद्ध आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा

है। इसकी सीमायें जम्मू कश्मीर व पंजाब से मिली हुयी हें। भारत की सामरिक, आर्थिक शक्ति को रोकने हेतु चीन, पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर रहा है। दक्षिण में श्रीलंका से चुनौतियां मिल रही हैं। बांग्लादेश म्यांमार से, नेपाल बिहार से मिला हुआ है। उत्तरपूर्वी हिस्से से चीन अरूणाचल प्रदेश में दावा जता रहा है। उत्तरपूर्व के राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अवैध आव्रजन एवं विदेशों से आतंकियों की सैन्य, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सहायता से आतंकी हिंसा को प्रश्रय मिलता है। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस. आई. ने कहरवादी तत्वों का समर्थन कर पूर्वोत्तर में आतंकवादी तत्वों को प्रेरित किया है।[1]

भूमण्डलीकरण नयी विश्व व्यवस्था से उत्पन्न उत्पाद की तरह है। आधुनिकीकरण का विकास, संचार के साधनों में आयी क्रांति, उत्पादन का वैश्विक ढांचा, व्यापार तकनीक ने तीव्र व क्रांतिकारी परिवर्तन विश्व व्यवस्था में किये हें। इसी व्यवस्था ने राज्य प्रायोजित व समूहों द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है क्योंकि उन्हें जिंदा रखने के लिये विदेशी सहायता निरंतर उपलब्ध होती रहती है। भारतीय उपमहाद्वीप लंबे समय

से इस्लामी समूहों जैसे लश्कर ए तैयबा, हरकत उल मुजाहिद्दीन, जैश ए मोहम्मद, अल बदर मुजाहिद्दीन जैसे विदेशी संगठनों की दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इंदौर, बंगलौर, हैदराबाद, पटना, पुणे, नागपुर में सक्रियता में प्रमुख हाथ विदेशी राष्ट्रों का रहा है।[2]

भारतीय संदर्भ में आतंकवाद की उत्पत्ति के संदर्भ में हम आर्थिक कारकों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। स्वाधीनता पश्चात् औद्योगिकीकरण, विकास जैसे आधुनिक प्रभावों ने नवीन तनावों को जन्म दिया है। यह एक कटु तथ्य है कि विगत पांच दशकों में आर्थिक विकास के लाभ सर्वसाधारण तक नहीं पहुंच पाये हैं। देश की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रस्त रहा है। अपनी आर्थिक परेशानियों के कारणों को समझने में असमर्थ, बढ़ती आर्थिक असुरक्षा की चिंताओं से त्रस्त वर्ग इन्हीं असामाजिक तत्वों का शिकार बन जाता है। मध्यप्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश में तेलंगाना, बिहार में छोटा नागपुर का पठार ऐसे ही उदाहरण है जहां ग्रामीण बेरोजगारी, भूमि सुधारों की कमी, जमींदारों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है यही अन्याय जब

विचारधारात्मक आतंकी समूहों के सम्पर्क में आता है तो इनसे ही माओवाद जैसे नाम सामने आते हैं। पूर्वोत्तर में प्राकृतिक संसाधनों एवं जैव विविधता की प्रचुरता के बावजूद बुनियादी ढांचे का अभाव रहा है। यहां उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्य आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति से गुजर रहे हैं। यहां विकसित एवं स्थापित उद्योगों की गमी है। यहां देश की जनसंख्या के मात्र चार प्रतिशत का निवास है किंतु उन्हें केंद्रीय सहायता के कुल अंश का बीस प्रतिशत प्राप्त होता है। इस प्रकार नक्सली हिंसा, पृथकतावादी उपद्रवों आदि के मूल में आर्थिक असंतुलन के प्रश्न निहित है।

राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के माह में हमारे राजनीतिक दलों की तुष्टीकरण की नीति का सर्वोत्तम उदाहरण असम व त्रिपुरा में दिखाई पड़ता है। यह हमारी सरकार की कमजोरी रही कि वे अवैध शरणार्थियों को बाहर नहीं कर पाई चाहे वह अवैध आव्रजन बांग्लादेश के मुस्लिमों का रहा हो या फिर पाकिस्तानी शरणार्थियों का। 1947 में भारत विभाजन के उपरान्त पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थी, 1950 के बंगाल के सांप्रदायिक

दंगों, 1964 में पूर्वी पाकिस्तान के सांप्रदायिक दंगों, 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान असम में शरणार्थियों के बसने का क्रम बना रहा किंतु शरणार्थियों की बड़ी संख्या का संकट 1971 में भारत पाक युद्ध एवं बांग्लादेश के उदय के दौरान हुआ जब नब्बे लाख बंगाली शरणार्थी भारत आये।[3] स्थानीय राजनीतिक दलों द्वारा इन शरणार्थियों को अपने वोट बैंक के रूप में देखा गया। पंजाब में 1995 से पूर्व एवं जम्मू कश्मीर में 1989 के दौरान धर्म आतंकवाद के एक कारक के तौर पर उभरा। पंजाब में कुछ सिक्ख समर्थक खालिस्तान की मांग को लेकर आतंक फैलाते रहे। वहीं जम्मू कश्मीर में कुछ उद्देश्यों को लेकर भी यही स्थिति सामने आयी है। एक ओर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कश्मीर को स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता है वहीं दूसरी ओर हिजबुल मुजाहिदीन उसे पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहता है। अनेक धार्मिक संगठनों जैसे स्टूडेण्ट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, अलकायदा, तालिबान आदि भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुये हैं। भारत में पृथक समूह चेतना से ग्रसित मुसलमानों तथा

संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवाद ने देश के दो प्रमुख संप्रदायों के मध्य वैमनस्य को उपजाया है। एक ओर अल्पसंख्यकों विशेषतः मुस्लिम संप्रदाय का एक बड़ा भाग राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया वहीं दूसरी ओर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थकों ने देश के बहुलतावादी स्वरूप को अस्वीकार कर दिया।

भारत में भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक बनावट की भिन्नता के कारण इस क्षेत्र में सामाजिक संस्कृति के निर्माण में सहायक तत्वों की कमी रही है। पूर्वोत्तर में लगभग दो सौ अनुसूचित जनजातियों एवं कबीलों का निवास है जिनकी पृथक–पृथक बोलियां हैं। प्राकृतिक विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध भूभाग में समान संस्कृति का विकास नहीं हो पाया है। ब्रिटिश शासन के दौरान ईसाई मिशनरियों ने धर्मान्तरण को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार के सामाजिक ढांचे में विखण्डन व आतंक की अग्नि पनपना आसान था। केन्द्र की अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण भी असंतोष की स्थितियों ने जन्म लिया है। तेरहवें संविधान संशोधन द्वारा नागालैण्ड को पृथक राज्य, 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को पूर्ण

राज्य, 1986 में मिजोरम को राज्य के दर्जे के उपरान्त आज भी उल्फा, बोडोलैण्ड या गोरखालैण्ड की मांग निरन्तर बढ़ती स्थानीय महत्वाकांक्षाओं का ही प्रतिफल है।[4]

विभिन्न राज्यों में उत्पन्न आतंकवाद

वर्तमान समय में भारत में आतंकवाद की जो गतिविधियां जारी हैं, उनके केंद्र में जम्मू एवं कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान अपनी कुदृष्टि लगाये हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पंजाब एवं पूर्वोत्तर के राज्य आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। विभिन्न राज्यों में हुयी आतंकी हिंसा को अग्रांकित सारणी प्रकट करती है :–

सारणी संख्या – 1

विभिन्न राज्यों में आतंकवादी हिंसा में मारे गये लोग

राज्य	वर्ष	मारे गये लोग			
		आतंकवादी	नागरिक	सुरक्षा बल	कुल
कश्मीर	1988–अप्रेल 2013 तक	7504	4233	2057	13794
पंजाब	1981–अप्रेल 2013 तक	8098	11783	1750	21631
असम	1992–अप्रेल 2013 तक	2850	4018	809	7677
नागालैण्ड	1992–अप्रेल 2013 तक	1384	766	246	2396
त्रिपुरा	1992–अप्रेल 2013 तक	520	2509	455	3484

विभिन्न राज्यों में आतंकवादी हिंसा में मारे गये लोग

वर्ष	मारे गये लोग
1988–अप्रेल 2013 तक	13794
1981–अप्रेल 2013 तक	21631
1992–अप्रेल 2013 तक	7677
1992–अप्रेल 2013 तक	2396
1992–अप्रेल 2013 तक	3484

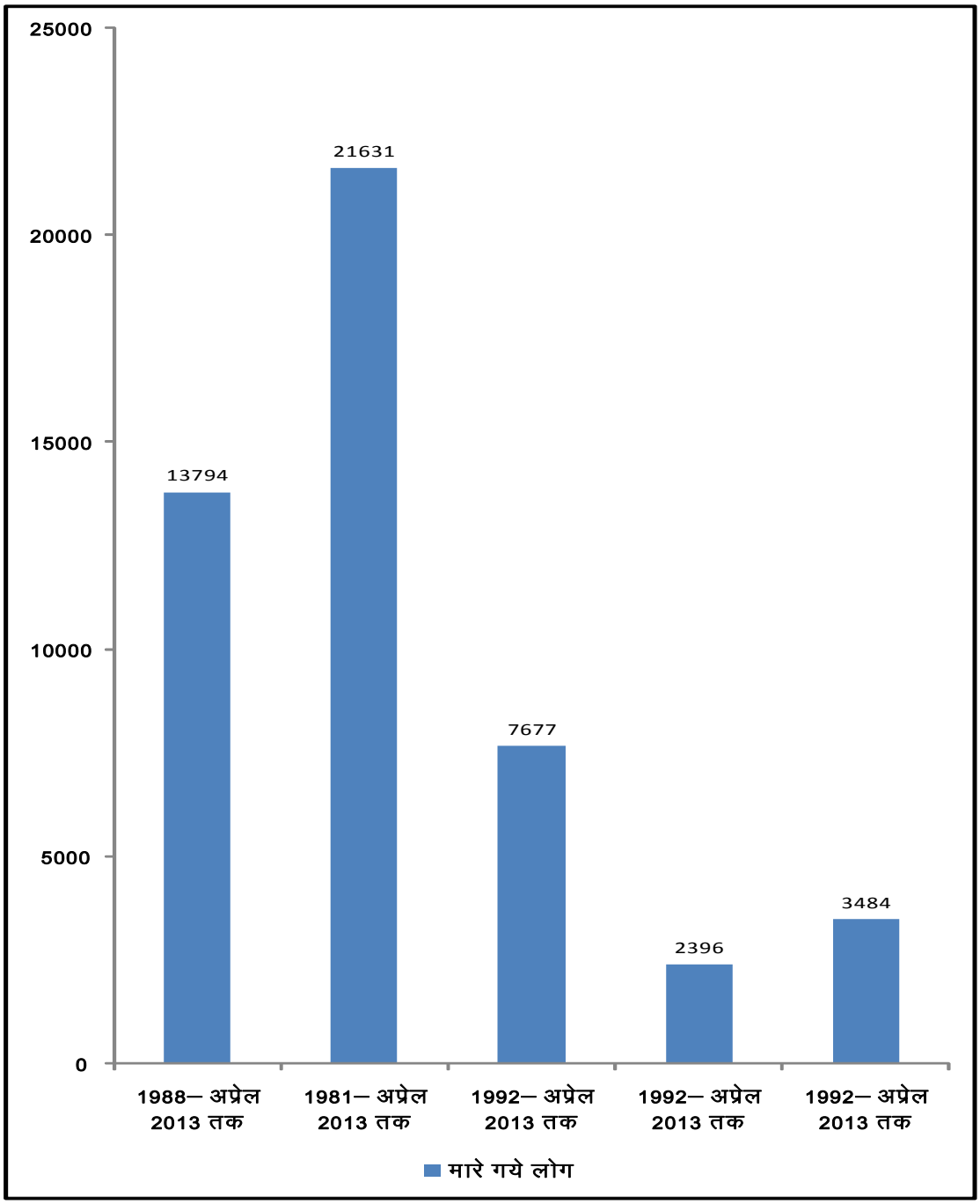

जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवाद

स्वतंत्रता पश्चात् देशी रियासतों के विलीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान जम्मू कश्मीर रियासत के शासकों द्वारा जब तक निर्णय लिया जाता, तब तक पाकिस्तान के कुछ कबायलियों ने आक्रमण कर इसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय हो गया, किंतु पाकिस्तान अपना दावा जताता रहा। इसको लेकर भारत व पाकिस्तान के मध्य तीन सशस्त्र युद्ध हो चुके हैं। पाकिस्तान इनमें पराजित होने के कारण अप्रत्यक्ष युद्ध का सहारा ले रहा है। इसके द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में चलाये जा रहे प्रशिक्षित केम्पों में तैयार आतंकवादी विषम भौगोलिक अवस्थिती का लाभ उठाकर कश्मीर में अवैध प्रवेश से श्रीनगर, कूपवाड़ा, पुंछ, डोड़ा, बड़गाम, अनन्तनाग, जम्मू आदि क्षेत्रों में खूनी संघर्ष जारी रखे हुये हैं। ये संगठन जम्मू–कश्मीर का पाकिस्तान में विलय चाहते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे का कश्मीरियों के स्वाधीनता संघर्ष एवं कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन के रूप में अन्तर्राष्ट्रीयकरण किया है। अस्सी एवं नब्बे के दशक में पाकिस्तान ने

कश्मीर में सीमा पार के आतंकवाद की नीति को निरन्तर योजनाबद्ध षड़यन्त्र के माध्यम से बनाये रखा है। जम्मू–कश्मीर में सक्रिय उग्रवादी संगठन लश्कर–ए–तैयबा, जैश–ए–मोहम्मद, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट, कश्मीर लिबरेशन आर्मी, हिजबुल मुजाहिद्दीन एवं जमाते तुल्ला आदि हैं। इन आतंकवादी संगठनों का प्रमुख लक्ष्य निर्दोष लोगों की हत्या, सुरक्षा बलों पर छापामार हमले, धार्मिक स्थलों पर विस्फोट, सार्वजनिक संपत्ति की हानि तथा कानून व्यवस्था को ठप कर सरकार एवं जनमानस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है।[5] सरकार द्वारा कश्मीर में सामान्य कानून व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण स्थिति बनाये रखने के लिए प्रयास किये गये हैं। चरमपंथी गुटों के साथ कश्मीर के मुद्दे पर संवैधानिक दायरे में बातचीत, कश्मीर में चुनावों द्वारा सरकार के गठन, नागरिकों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा बलों की तैनाती तथा उग्रवादी संगठनों के विरूद्ध समय–समय पर कार्यवाही द्वारा आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण का प्रयास किया है। वस्तुतः एक नये एवं खुशहाल कश्मीर के लिये जनता एवं सरकार के स्तर पर ईमानदारी पूर्ण सुदृढ़ प्रयासों की आवश्यकता है।

सारणी संख्या – 2

कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में मारे गये लोग

वर्ष	मारे गये लोग			
	आतंकवादी	नागरिक	सुरक्षा बल	कुल
1988	1	29	1	31
1989	0	79	13	92
1990	183	862	132	1177
1991	614	594	185	1393
1992	873	859	177	1909
1993	1328	1023	216	2567
1994	1651	1012	236	2899
1995	1338	1161	297	2796
1996	1194	1333	376	2903
1997	1177	840	355	2372
1998	1045	877	339	2261
1999	1184	790	555	2529
2000	1908	842	638	3388
2001	1610	931	515	3056
2002	1714	839	469	3022
2003	1546	658	338	2542
2004	951	534	325	1810
2005	1000	521	218	1739
2006	599	349	168	1116
2007	492	164	121	777
2008	382	69	90	541
2009	242	55	78	375
2010	270	36	69	375
2011	119	34	30	183
2012	3	4	0	7
अप्रेल 2013 तक	2	0	5	7

कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में मारे गये लोग

वर्ष	मारे गये लोग
1988–1992	4602
1993–1997	13537
1998–2002	14256
2003–2007	7984
2008–अप्रेल 2013 तक	1488

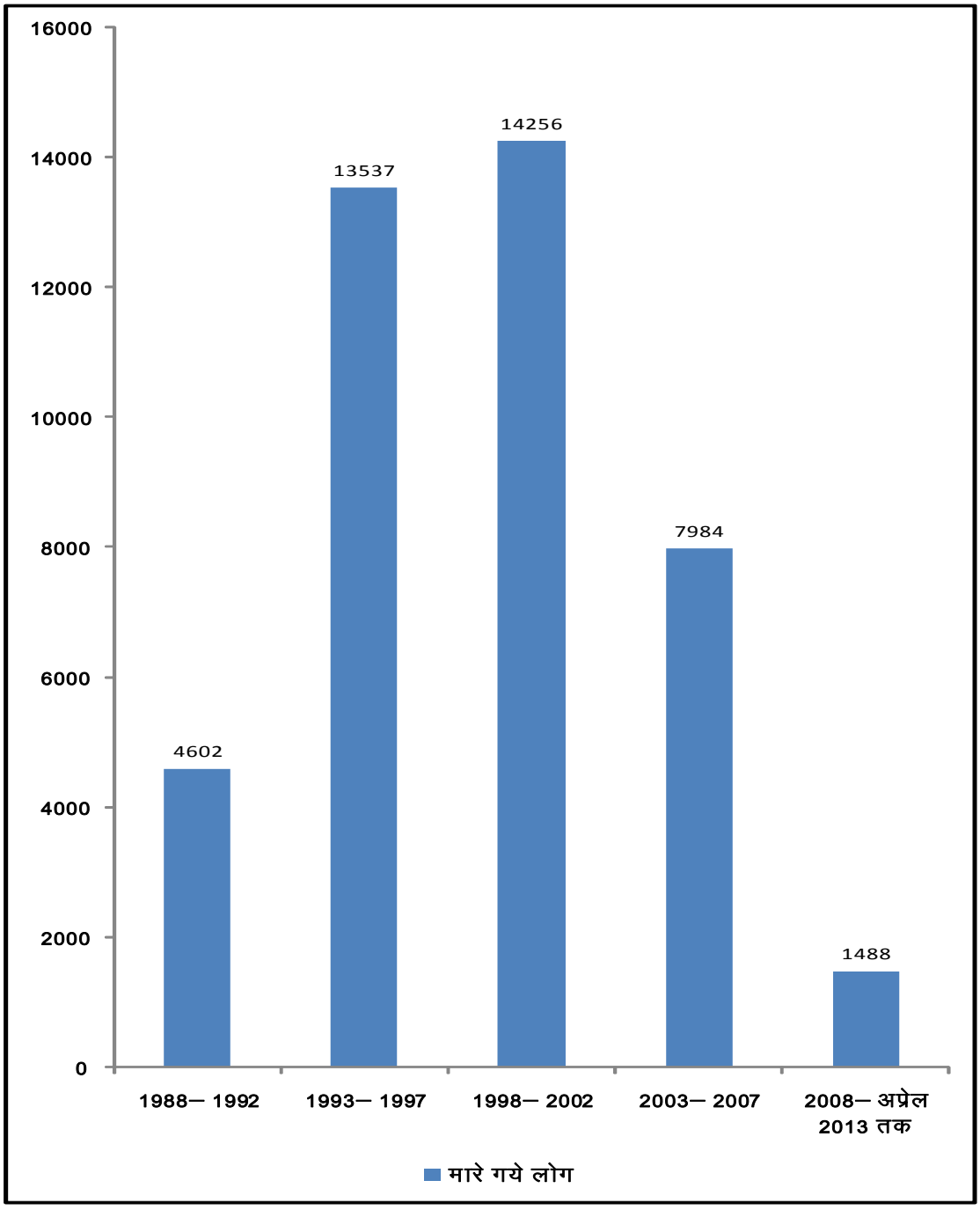

पंजाब में आतंकवाद

स्वतंत्रता के पश्चात् भाषा के आधार पर पंजाबी तथा हिन्दी भाषी अलग राज्यों की मांग उठायी गई। 1960–64 के समय पंजाबी भाषा के आधार पर पृथक राज्य की मांग ने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। नवंबर 1966 में पंजाब एवं हरियाणा इन दो राज्यों की स्थापना कर चण्डीगढ़ को इन दोनों की राजधानी बनाया गया। किंतु सरकार एवं सिक्ख समुदाय के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले संगठनों के मध्य मतभेद बने रहे हैं। 1980 में पृथक खालिस्तान की मांग को लेकर जनरेल सिंह भिण्डरवाला के नेतृत्व में कतिपय सिक्ख संगठनों ने आतंकवादी गतिविधियों का संचालन किया। जून 1982 में आपरेशन ब्ल्यू स्टार के द्वारा सैनिक कार्यवाही से सिक्खों के पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मन्दिर परिसर को आतंकवादियों के नियंत्रण से मुक्त कराया गया। किंतु धार्मिक स्थल पर सैन्य कार्यवाही का सिक्ख राजनीतिक नेतृत्व द्वारा विरोध किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या करने के बाद दिल्ली सहित देश के अनेक स्थानों पर हुए हिन्दू–सिक्ख

दंगों में जान माल की क्षति हुयी। 80 के दशक में पंजाब समस्या सुलझाने के निरंतर प्रयास किये जाते रहे। 90 के दशक में पंजाब में निर्वाचनों के माध्यम से गठित सरकार द्वारा पुनः राजनीतिक स्थायित्व कायम करने का प्रयास किया गया है। पंजाब के उग्रवादी संगठनों जैसे :– ऑल इण्डिया सिक्ख स्टूडेण्ट्स फेडरेशन, बब्बर खालसा, दल खालसा आदि को देश के बाहर से समर्थन प्राप्त होता रहा है। पाकिस्तान, अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में इन आतंकवादी संगठनों के नेताओं की उपस्थिति, आतंकवादी संगठनों को शस्त्र एवं अर्थ की उक्त देशों द्वारा सहायता इसका प्रमाण है।[6]

पूर्वोत्तर में आतंकवाद

1947 के देश के विभाजन के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र काफी संवेदनशील रहा है। स्वतंत्रता उपरान्त एक असम के सात टुकड़े करने के बाद भी क्षेत्रीय जातीय कबीलों को संतुष्ट करने, इसे देश की मुख्य धारा में लाने का सपना आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित सात

राज्य असम, नागालैण्ड, अरूणाचलप्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, एवं त्रिपुरा को पूर्वोत्तर भारत के रूप में जाना जाता है। यहां अलग अलग पहचान एवं भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले तीन सौ पचास से अधिक जातीय समूह हैं। जिनमें से कई की कुल आबादी पांच हजार से भी अधिक नहीं है। इन राज्यों की नन्यान्वें प्रतिशत सीमा रेखा भूटान, चीन, तिब्बत, म्यांमार एवं बंग्लादेश से मिलती है। इनमें से कम से कम पांच राज्यों में अलग राज्य या देश की मांग को लेकर सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। सर्वप्रथम आजाद हिन्द फौज के एक पदाधिकारी ए.जेड. फिजो ने 'नागा नेशनल काउंसिल' बनाकर आतंकवाद का बीजारोपण किया जो अब अनेक शाखाओं में फैल चुका है। यहां की प्रत्येक जाति अपनी पहचान और अस्मिता के लिये संघर्षरत है। पहले चीन और म्यांमार अब बंग्लादेश के मार्फत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. हिंसक आंदोलनों को बढ़ाने में लगी हुई है। इनमें आतंकवाद की स्थिति अग्रांकित है :–

असम

उत्तरपूर्व का प्रवेश द्वार माना जाने वाला असम राज्य, भारत की

मुख्य भूमि से अठाईस किमी. चौड़ी एवं एक संकीर्ण पट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। दो पड़ौसी देशों बंग्लादेश व भूटान के साथ भी इसकी लंबी सीमा है। यहां की जनसंख्या मंगोलियन, इंडो मयांमरीज, इंडो ईरानियन तथा आर्यन प्रजातियों का वृहत अन्तःमिश्रण है। इसी कारण इसे लघु भारत भी कहा जाता है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड प्रमुख आतंकवादी गुट है। भारतीय संघ से अलग एक स्वाधीन असम का सपना जगाने वाले संगठन 'उल्फा' का जन्म 1979 में हुआ। इसके अलावा कोकराझार, बारपेटा, नलबाड़ी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ के आधे जिलों को मिलाकर बोडो सुरक्षा दल ने पृथक बोडो राज्य की मांग की। 1980 में नेपाल से आये गोरखा लोगों ने सुभाष घीसिंग के नेतृत्व में पृथक गोरखालैण्ड की मांग आदि से जाहिर होता है कि नृजातीय पहचान के इच्छुक उक्त गुटों ने असम में हिंसक गतिविधियों का संचालन किया है। इन सबमें प्रमुख भूमिका आई.एस.आई. की रही है जो यहां के निवासियों को प्रशिक्षित कर उन्हें हथियार उपलब्ध करवा रही है। यहां पर उल्फा एवं अन्य आतंकवादी गुटों द्वारा चाय बागानों के मालिकों,

व्यवसायियो, सुरक्षा बलों तथा गैर असमी लोगों के विरूद्ध यह हिंसक संघर्ष जारी है।[7]

नागालैण्ड

नागालैण्ड में उग्रवादी हिंसा ने केवल इसे ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर पूर्व को भी आतंकित किया है। वर्तमान नागा समस्या का बीज स्वतंत्रता के पूर्व ही पड़ गया था जब अप्रैल 1946 में गठिन 'नागा नेशनल कौन्सिल' के नेता अगामी जापू फिजो ने 14 अगस्त 1947 को नागालैण्ड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उद्घोषित कर विवाद का विष बीज बो दिया था। भारत सरकार द्वारा नागा नेशनल कौंसिल की इस उद्घोषणा को अस्वीकार कर 9 जुलाई 1948 को फिजो एवं उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। नागा नेशनल कौंसिल द्वारा मई 1951 में जनमत संग्रह करते हुये स्वतंत्र नागालैण्ड का दावा किया गया। 1956 में नागा फेडरल गवर्नमेंट एवं नागा फेडरल आर्मी का गठन किया गया। 1957 में नागालैण्ड को असम के एक भाग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया

गया। दिसंबर 1963 में इसे पूर्ण राज्य के दर्जे उपरान्त भी नागा आतंकवादी इसके वर्तमान स्वरूप से संतुष्ट नहीं हैं। इनके तत्कालीन व दीर्घ कालीन दो लक्ष्य हैं :– तत्कालीन लक्ष्य – मणिपुर, असम और अरूणाचलप्रदेश के नागा आबादी वाले क्षेत्र को नागालैण्ड में शामिल कर वृहत्तर नागालैण्ड का सृजन करना। दीर्घकालीन लक्ष्य – स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नागालैण्ड की स्थापना।[8]

त्रिपुरा

यह अंग्रेजों के संरक्षण में स्वतंत्र राज्य था, जिसका 1949 में भारतीय संघ में विलय हुआ था। 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तीन ओर से यह राज्य बंग्लादेश से घिरा है। यहां बंगाली शरणार्थियों के आने से स्थानीय आदिवासियों में कुण्ठा पैदा हुई तथा हिंसक आन्दोलन की ओर प्रवृत हुए। त्रिपुरा में आतंकवाद की जड़ में पादरियों की भूमिका भी रही है। यहां के आदिवासियों का पादरियों द्वारा धर्मान्तरण की वजह से ईसाई आदिवासी बंगालियों एवं गैर ईसाइयों के

मध्य कटुता एवं संघर्ष उत्पन्न हुआ है। त्रिपुरा में मुख्य रूप से 'ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स' एवं 'नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा' का बोलबाला है।

मणिपुर

मणिपुर में दो जनजातियों नागा एवं कुकी के मध्य हिंसक संघर्ष एवं पारस्परिक कटुता ने आतंक की स्थिति उत्पन्न कर दी है। यहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण छः आतंकवादी संगठन हैं। जिन्हें बाहरी समर्थन प्राप्त है। इन संगठनों पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट, पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक, कांगलीपाक कम्युनिष्ट पार्टी, कांगली याओल काम्बा लूप, मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रन्ट इनके हिंसक संघर्ष की गतिविधियों से इस क्षेत्र में अस्थिरता एवं अव्यवस्था व्याप्त हो गयी है। मणिपुर में इन संगठनों द्वारा भारतीय संघ क्षेत्र से पृथक होकर आजादी की मांग करना राष्ट्रीय अखण्डता के लिये चिंताजनक पहलू है।

नक्सलवादी आतंकवाद

यह मूल रूप से मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त पर आधारित

है। इसके तहत शोषित, उपेक्षित एवं दलित वर्ग अपनी संघर्षशक्ति से पूंजीपतियों, जमींदारों, साहूकारों एवं शासकों को शिकार बनाते हैं और अपना अधिकार प्राप्त करने में जो बाधा पहुंचाता है, उसे समाप्त कर देना चाहिये, तभी सर्वहारा शासन तंत्र की स्थापना हो सकेगी, ऐसी उनकी धारणा है। यद्यपि इसका वास्तविक उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना है। किंतु अकारण हिंसा, अपराध एवं उग्रवाद अपनाने के कारण यह हमारे समाज के लिये एक बड़ी चुनौती एवं सुरक्षा की दृष्टि से एक सामयिक समस्या के रूप में उभरा है। इसका प्रारंभ पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी के एक संभाग से हुआ, जिसमें नक्सलवादी, पंसीदेवा एवं खरीबाड़ी जैसे तीन उपक्षेत्र थे, इनमें संथाल, आरांव तथा राजवंशी जैसी जनजातियों को लोग रहते थे। साठ के दशक में नक्सलवादी गांव में भूस्वामियों के विरूद्ध भूमिहीन किसानों एवं बेरोजगार युवकों ने अपना संघर्ष अभियान आरंभ किया। इनको नेतृत्व प्रदान करने वाले मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के स्थानीय नेता चारू मजूमदार, कानू सान्याल, लंगल संथाल थे। इस आंदोलन के नेतृत्व कर्ता सामाजिक,

आर्थिक न्याय आधारित व्यवस्था की स्थापना के लिये भारत के साम्यवादी दल के सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणित करने के लिये इस आंदोलन को प्रारम्भ किया गया। चीन के साम्यवादी दल से प्रभावित इस आंदोलन के प्रवर्तकों ने पश्चिमी बंगाल में कानू सान्याल, आन्द्रप्रदेश में बी. सत्यनारायण, केरल में कुन्नीकल के नेतृत्व में विचारधारा का प्रसाद किया। भूमिहीन मजदूरों का भूमिपतियों के विरूद्ध प्रारंभ हुआ यह संघर्ष शीघ्र ही हिंसक रूप ले चुका था। अपने मूल स्थान पश्चिमी बंगाल में पनपने के स्थान पर नक्सलवाद का विस्तार जंगल एवं घाटी की बहुतायत वाले स्थानों जैसे आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा क्षेत्रों में तीव्रता से हुआ।

नक्सली हिंसा में मौतें

राज्य	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
आंध्रप्रदेश	45	46	18	24	9	13	11
बिहार	67	73	72	97	62	44	69
छत्तीसगढ़	369	242	290	343	204	109	110
झारखण्ड	157	207	208	157	182	162	150
मध्यप्रदेश	2	—	—	1	—	—	—
महाराष्ट्र	25	22	93	45	54	41	19
उड़ीसा	17	101	67	79	53	45	35
उत्तरप्रदेश	3	—	2	1	—	—	—
पं. बंगाल	6	26	158	258	41	—	—

2007–अप्रेल 2013 के दौरान नक्सली हिंसा में हुयी मौतें

राज्य	मारे गये लोग
आंध्रप्रदेश	166
बिहार	484
छत्तीसगढ़	1667
झारखंड	1223
मध्यप्रदेश	3
महाराष्ट्र	299
उड़ीसा	397
उ0प्रदेश	6
पश्चिम बंगाल	489

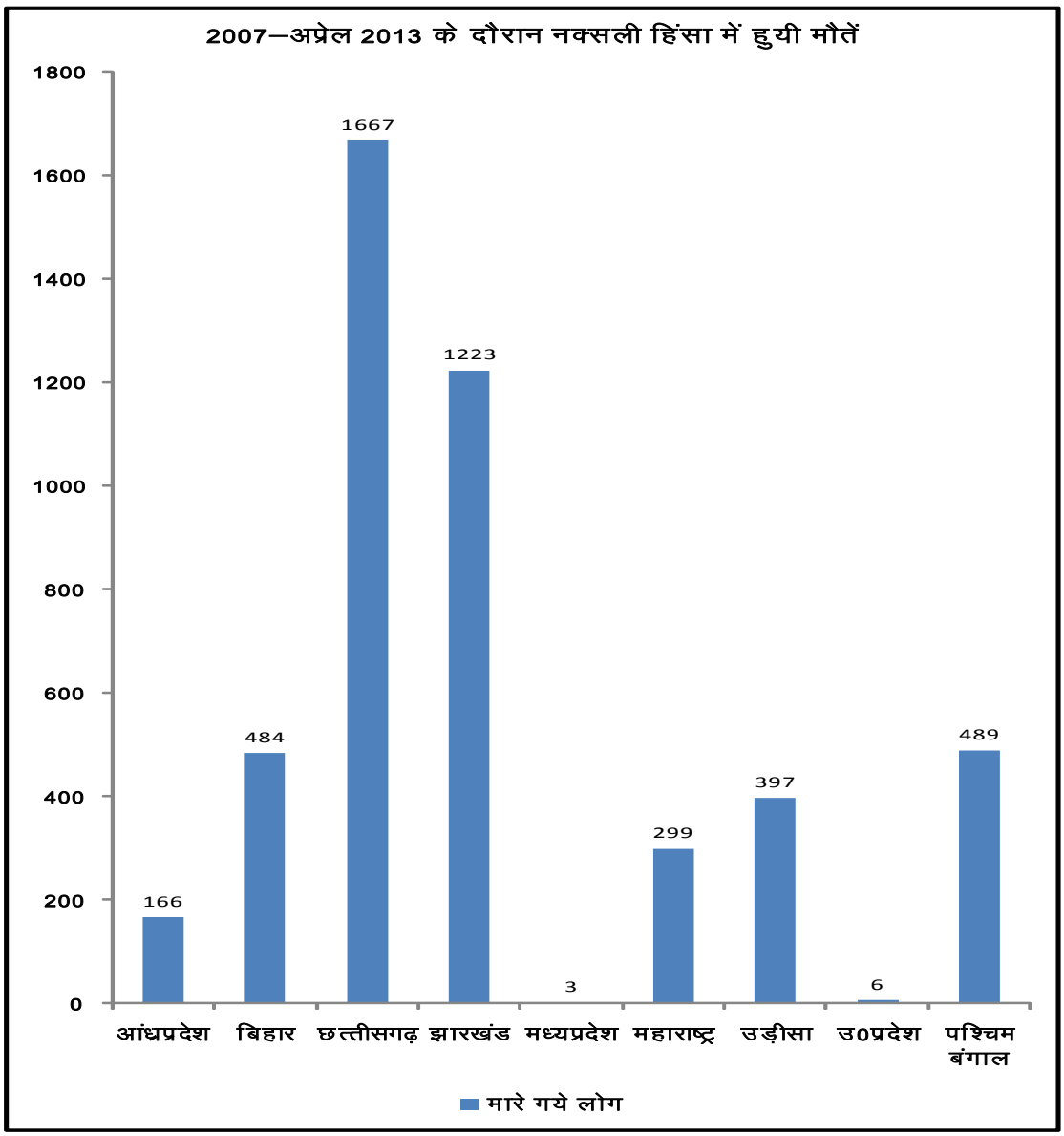

नक्सलवादी नाम से प्रचलित कम्युनिष्ट क्रान्तिकारियों की यह धारा स्पष्ट तौर पर दो प्रवृत्तियों के मध्य विभक्त है – एक विशेष रूप से आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र बिहार एवं उड़ीसा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सक्रिय पीपुल्स वार ग्रुप नक्सलवाद की अराजकतावादी धारा है, दूसरी प्रवृत्ति जो संसदीय व गैर संसदीय संघर्ष को अपना प्रस्थान बिंदु मानती है, उसे भारत की कम्युनिष्ट पार्टी लिबरेशन यानि भाकपा माले लिबरेशन कहा जाता है। आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु के नक्सली नेता कोंडापल्ली सीतारमैया तथा कोदंड रमन के द्वारा पीपुल्स वार ग्रुप का गठन किया गया। लंबी अवधि से हथयार बंद एवं बारूदी सुरंगों में दक्षता प्राप्त कर चुका यह संगठन सरकार के साथ संघर्ष के कारण चर्चित रहा है। पीपुल्स वार ग्रुप की ही तरह बिहार का एक अन्य नक्सलवादी गुट माओवादी कम्युनिष्ट केंद्र चर्चित रहा है। बिहार का एक अन्य नक्सलवादी संगठन सी.पी.आई.(एम.) लिबरेशन इस राज्य की बड़ी आंदोलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है।[9] नक्सलवादी हिंसा की समस्या तीन दशक से भी अधिक समय से चली आ रही है। वर्तमान में देश के दो सौ

तेईस जिले इससे ग्रसित हैं। इसके पनपने का प्रमुख कारण समाज में व्याप्त वर्गभेद के साथ गरीबी व बेरोजगारी भी है। मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार 41.6 प्रतिशत लोग यहां $1.25 प्रतिदिन पर जीवनयापन करने को मजबूर हैं। नक्सलवाद की मूल जड़ भूमि सुधार कार्यक्रमों पर तेजी से अमल नहीं होना भी है। समाज का सामाजिक व आर्थिक ढांचा भी इस समस्या को बढ़ा रहा है। क्योंकि यह मूलतः समाज के उस वर्ग के ही असंतोष का परिणाम है जिन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो रही है। आज के ग्रामीण युवावर्ग को भी शहरी क्षेत्र में मिल रही सुविधाओं से खुद को अलग रख पाना संभव नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि नक्सलवादी इलाकों में सरकार की पहुंच असफल साबित हो रही है। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उनको नहीं मिलता जिनको आवश्यकता है। सरकार द्वारा इस तरफ प्रभावी तरीकों को काम में लेने में संसाधनों की कमी भी खलती है। राजनीतिक दबाव भी सरकारी योजनाओं को पूरा करने में एक मुख्य बाधा के तौर पर उभरा है। अतः यह आवश्यक है कि देश के जन, गण, मन, शासक व

शासित संस्थायें इस दिशा में ईमानदारी से कार्य करें, साथ ही भूमि सुधार कार्यक्रमों पर भी तेजी से अमल हो।

इसके भारत पर प्रभाव

भारत में आतंकवाद के दो स्वरूप नजर आते हैं एक ओर बाहरी व दूसरी ओर भीतरी आतंकवाद। नक्सलवाद भी भीतरी आतंकवाद का ही एक रूप है। राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाते क्षेत्रीय आंदोलनों, बढ़ती जनाकांक्षा आदि तत्वों से जब आंतरिक सुरक्षा व्यय में भारी वृद्धि हो जाती है तो आर्थिक विकास व सामाजिक सेवाओं के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति देश के एक बड़े हिस्से को सुलभ नहीं हो पाती है। इसी कारण आज भी अनेक समुदाय विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये हैं। इसके कारण निर्दोष लोगों का जीवन जब नष्ट होने लगता है तो इससे देश के बहुसांस्कृतिक ढांचे में मौजूद सौहार्द की भी क्षति होती है। न केवल राष्ट्र की एकता व अखण्डता को ही चुनौती मिलती है बल्कि राष्ट्र निर्माण की अवधारणा भी कमजोर होती है। भारत जैसे देश में जहां अनेक वर्गों, भाषाओं, धर्मों को

मानने वाले लोगों का निवास है वहां ऐसे तनावों से आपसी भाईचारा ही खंडित होता है। लोगों के बीच मनोवैज्ञानिक संघर्ष बढ़ रहे हैं। केंद्र राज्य संबंधों में सहयोग व सामंजस्य में ही कमी नहीं आयी है बल्कि क्षेत्रीय समस्याओं का भी इजाफा हुआ है। भूख, उत्पीड़न, दहशत के माहौल में असंतोष व अराजकता बढ़ती जा रही है। इसके नियंत्रण हेतु बहुस्तरीय, बहुआयामी प्रयास व उनके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु आवश्यक ईमानदारी का हमारी सरकार के पास अभाव होने से नक्सलवादियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। नक्सलवादियों द्वारा अपने संघर्ष को जारी रखने हेतु हथियारों की जरूरत होती है। उनकी पूर्ति हेतु वे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में इतनी वन संपदा व खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं कि उनका दशांश भी उनके भले के लिए प्रयुक्त हो जाये तो उनका और देश, दोनों का उद्धार हो जाये। लेकिन वे तो हिंसक संघर्षों हेतु राष्ट्रीय प्रगति को ही रोक रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आतंकवाद से मुक्ति भारत जैसे बहुसमुदाय वाले देश के लिए एक आवश्यकता एवं अपरिहार्यता है।

संदर्भ सूची

1. सुरेश मैयर, द रूट कॉजेज ऑफ टेर्ररिज्म इन इंडिया, 13 जुलाई 2011
2. डॉ. संजीव कुमार शर्मा, कम्युनिकेशन मीडिया ग्लोबलाइजेशन एंड टेर्ररिज्म इन इंडिया, 2006, पृष्ठ संख्या 273–281
3. विपिन चंद्र एवं अन्य, आजादी के बाद का भारत, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 442
4. डॉ. रूपा मंगलानी, भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2009, पृष्ठ संख्या 522, 523
5. जोगिन्दर सिंह, आतंकवाद का बदलता स्वरूप, 13 सितंबर 2003, पृष्ठ संख्या 8
6. कमला भसीन एवं अन्य, अमन की तलाश में इंसानियत की आवाजें, बुक्स फॉर चेंज, नई दिल्ली, 2001, पृष्ठ संख्या 9
7. टेर्ररिज्म : इंडियाज अनएंडिंग वार, 4 अप्रेल 2003
8. लेर्नाट बेन्ड फेल्ड, नक्सलिज्म : द माओईस्ट चेंज टू द इंडियन स्टेट, जुलाई 2010, पृष्ठ संख्या 6, 7, 8
9. रजत कुजुर, नक्सल मूवमेंट इन इंडिया, सितम्बर 2008, पृष्ठ संख्या 2, 3

चतुर्थ

अध्याय

आतंकवाद के नियंत्रण व समाप्ति एवं देश की आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने हेतु सुझाव

भले ही भारत इक्कीसवीं सदी में प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, किंतु आंतरिक व बाहरी दोनों तरह के आतंकवाद को झेल रहा है। मौजूदा दौर में हम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और लश्कर द्वारा समर्थित घरेलू आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। चाहे पाकिस्तानी आतंकी समूह हो या घरेलू आतंकी गुट वे हमारी आतंकरोधी तंत्र की खामियों का लाभ उठा रहे हैं। अभी बहुत से मोर्चे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है।

आतंकवाद पर नियंत्रण हेतु सुझावों पर दृष्टिपात करें तो सर्वप्रथम हमें सभी देशों के साथ सहयोग के ही सूत्र तलाशने चाहिए। क्योंकि विदेश नीति संबंधी मसलों पर दूरगामी दृष्टि और राष्ट्रीय लाभ हानि की दीर्घकालिक समझ के साथ ही रूख तय हो सकता है। तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में गर्जन तर्जन युक्त वक्तव्य राजनीति का हिस्सा तो हो सकते हैं किन्तु सुविचारित विदेश नीति का नहीं। प्रश्न यहां संप्रभू राष्ट्र के भीतर

अन्यों के हस्तक्षेप का है। किसी भी देश के साथ सीमा मुद्दे के समग्र संबंधों को प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता है। बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाया जा सकता है।

भारत में बाहरी आतंकवाद पर नियंत्रण हेतु अच्छे आर्थिक सन्य संबंध ही बेहतर विकल्प हो सकते हैं। भारत के लगभग सभी पड़ौसियों से सीमा विवाद हैं। लेकिन इन पर नियंत्रण के लिए तात्कालिक आवश्यकता यह हो कि दो देशों के बीच क्षेत्रीय दावों पर चर्चा व विचार विमर्श हो। हमारा ध्यान समस्या पर ही केंद्रित हो। क्योंकि इन्हीं बढ़ते तनावों से कट्टरपंथीयों को ताकत मिलती है। आतंकी गुट व कट्टरपंथी तो चाहते हैं कि तनाव व संवादहीनता बनी रहे किन्तु प्रत्येक देश का उदारवादी व प्रगतिशील तबका सद्भाव का ही इच्छुक होता है।

आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आतंकवाद ऐसा मुद्दा है जिसमें अल्पदृष्टि और तात्कालिक हितों के आधार पर तय रूख लंबे समय में भारत को भारी पड़ सकता है। भारत के इस ओर अमरीका, रूस, इजरायल, फ्रांस के साथ किए गए करार निश्चित तौर पर लाभदायी हो

सकते हैं। फिर भी हमें अपने पड़ौसी देशों पर नजदीकी से निगाह रखनी होगी।[1] चीन जैसी महाशक्ति का हम सैन्य मोर्चे पर मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए अच्छे संबंध ही बेहतर विकल्प हो सकते हैं। क्योंकि चीन द्वारा सिक्किम व अरूणाचल प्रदेश में जो सुविधायें विकसित की गई हैं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। चीन के नवनियुक्त राष्ट्रपति द्वारा पेश किए गए पांच सूत्री फार्मूले को क्रियान्वित करने की पहल की जानी चाहिए। एक–दूसरे की ताकत का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि मैत्री सलाह मशविरा जारी रखें तो निष्पक्ष व स्वीकार्य हल पर पहुंचा जा सकता है और आतंकवाद से निपटने हेतु इससे सहयोग लिया जा सकता है।[2] पाकिस्तान के संदर्भ में यह सही है कि वह हमारे विरूद्ध बहुआयामी युद्ध छेड़े हुए है। लेकिन आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान की कमजोर इच्छा शक्ति के बावजूद संबंधों को सामान्य बनाने के लिए बातचीत के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। दोनों परमाणु सम्पन्न पड़ौसियों के बातचीत को शुरू करने और बरकरार रखने का सीधा लाभ यह भी हो सकता है कि इससे

पाकिस्तान की कट्टरपंथी ताकतों को कमजोर करने का अवसर बढ़ता है।[3] श्रीलंका के संदर्भ में भी संतुलित रवैया ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस ओर सार्क देशों से सहयोग के सूत्र इस चुनौती से निपटने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हमारी सार्क देशों से समान रियायतें प्राप्त करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए बल्कि हमें उनको पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को यहां विकसित किया जा सके। हमें उनको विश्वास में लेना होगा ताकि उनकी सरजमीं में से आतंकी गतिविधियां संचालित न हो सके। हमारे देश में वास्तविक सुधार आर्थिक दृष्टि से सशक्त होने पर ही हो सकते हैं। इन सुधारों हेतु हमें पड़ौसियों से विश्वास बहाली के साथ–साथ व्यापार को संभालना चाहिए ताकि समय आने पर वे हमारी मदद कर सकें। आतंकवाद के खिलाफ संसार भर में रूस द्वारा खोले गए मोर्चे से सभी देश सीख ले सकते हैं। विश्व के सभी देशों की एकजुटता ही इससे निपटने में सहायक हो सकती है। रूस की भारत के साथ आतंकवाद के विरूद्ध की गई साझेदारी अमरीका–रूस के मध्य आतंकवाद के मामले में संधि निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है।

ऐसी पहल सभी देशों द्वारा की जा सकती है।

न केवल सीमाओं की चौकसी बढ़ानी चाहिए बल्कि सेनाओं का भी आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। भारत की थल सीमा बांग्लादेश (4339 कि.मी.), भूटान (605 कि.मी.), चीन (4056 कि.मी.), म्यांमार (1425 कि.मी.), नेपाल (1690 कि.मी.), पाकिस्तान के साथ (3244 कि.मी.) लम्बी है। हमारी तटीय रेखा 7516 कि.मी. लम्बी है। नौ समुद्र तटीय राज्य, तेरह बड़े व एक सौ सत्तयासी छोटे बंदरगाह हैं। हमारी जल व थल सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि बाहरी आतंकवादी यहां प्रवेश न कर पाये। समुद्र तटीय सुरक्षा हेतु प्रमुख पहलू यह है कि सार्क, आसियान जैसे संगठन आपस में आतंकवाद से संबंधित सभी सूचनाओं का आदान–प्रदान करे। भारत में राष्ट्रीय पहचान हेतु एक ही आधार कार्ड आवश्यक घोषित हो। मछुआरे भी सरकार के आंख व कान बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाये। उनके सहयोग के लिए उन्हें इनाम दिया जाए। समुद्र प्रहरी बल का मजबूती से संचालन हो, जनता की भागीदारी बढ़ाने के भी प्रयास किए

जा सकते हें। इसके लिए समुद्री इलाकों में टोलफ्री नंबरों की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में नए सीजीएचक्यू (Costal Guard Head Quarter) का गठन, समुद्र तटीय सुरक्षा की चौकसी वाले राडार स्थापित करने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी की जाये। यह प्रयास महज कागजी खानापूर्ति न बने। विशिष्ट कार्यों हेतु नये उपग्रहों की भी स्थापना की जाये जिनसे निरन्तर सहयोग प्राप्त हो सके। भारतीय नौ सेना, तटीय सुरक्षा बलों व भारत सरकार में सामंजस्य बना रहना चाहिए साथ ही पड़ौसी देशों व संगठनों से निरन्तर सहयोग के सूत्र तलाशे जाये। इसके लिए हमें रक्षा बजट को और बढ़ाना होगा। देश पश्चिमी, उत्तरी सीमाओं व समुद्र क्षेत्र में लगातार खतरों का सामना कर रहा है। लगभग तेरह लाख सैनिकों के साथ हमारी सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। वित्तीय वर्ष 2013 में हमारे सालाना रक्षा बजट में 4.5 फीसदी बढ़ोतरी की गयी है। 2012 में 1,93,407 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे जो 2013 में बढ़ाकर 2,03,672 करोड़ रूपये कर दिये गए हैं। 'जबकि पिछले साल

गृहमंत्रालय के अनुसार दो हजार पांच सौ आतंकी पाकिस्तानी सीमा से भारत में घुसने की फिराक में थे।'[4] हमारे दो विरोधियों चीन व पाकिस्तान का सामना करने के लिए केवल 8670 करोड़ रूपये ही सेना के नए हथियार व उपकरण खरीदने हेतु आवंटित किये गये हैं। मौजूदा समय में भारत दुनिया भर में हथियार आयात करने वाला सबसे बड़ा देश है। अब जाकर हमारे यहां हथियारों की स्वदेशीकरण प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। अतः हमें स्वदेशी दक्षता पैदा करनी चाहिए। फायटर एयर क्राफ्ट, मिग्ज, एसयू मिराज या आई एल 76 पूरी तरह से आयातित है या लाइसेंस के तहत खरीदे गए हैं। नौ सेना फ्रांसीसी व रूसी तकनीक पर ही निर्भर है। डीआरडीओ (Defence Research and Development Organisation) जैसे संस्थान भी स्वदेशी निर्माण की तरफ बढ़ने में पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं। वैसे स्वदेशी प्रक्रिया का हम वास्तविक आकलन करे तो पर्याप्त बजट के अभाव में यह भविष्य में हमारी रक्षा जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहेगी इसलिए सेना के आधुनिकीकरण हेतु व रक्षा जरूरतों के लिए हमें बजट को बढ़ाना होगा।[5] रक्षा योजना में तेजी लाने

के लिए रक्षा मंत्री को एक कार्यबल स्थापित करना चाहिए जो हथियार खरीद की जटिल प्रक्रिया में थोड़ी नरमी ला सके। साथ ही कारगिल समीक्षा समिति की रक्षा सुधार संबंधी सिफारिशों को माना जाये। 'सीमा सुरक्षा का प्रबंधन गृहमंत्रालय के पास ही होना चाहिए। अभी तक अलग–अलग क्षेत्र की कमान केन्द्र के भिन्न–भिन्न मंत्रालयों के पास है। इससे वास्तविक सहयोग बना नहीं रह सकता है। यदि एकल बिन्दु से नियंत्रण का सिद्धान्त अपना लिया जाये तो सभी प्रक्रियायें प्रभावी तौर पर व्यवस्थित हो सकती है। भारतीय सेना के सभी छः भागों जैसे एल.ए.सी. (Line of actual control), एल.ओ.सी.(Line of control), ए.जी.पी.एल. (Actual ground position line) एल.ए.सी. के सभी पांच संभागों पूर्वी सीमा पर म्यांमार सभी का नियंत्रण भारतीय सेना को ही सौंपा जाना चाहिए। भारतीय सीमा पर सेटेलाइटों के माध्यम से चौकसी की जानी चाहिए।[6] लेकिन इन सभी महंगे उपकरणों से सेना का आधुनिकीकरण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हमारी खुफिया एजेंसियों के

मध्य सहयोग व समन्वय के सूत्र फिर से तलाशे जा सकते हैं। एजेंसियां एक–दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए ताकि किसी भी वक्त साथ–साथ काम कर सकें चाहे खतरा आतंकवादी हमले का हो या फिर कोई दूसरा। आतंकवाद का मुकाबला करने वाली हमारी एजेंसियां चिर परिचित आतंकी समूहों के बारे में सूचनायें जुटाने में तो सक्षम हैं लेकिन कुछ गुमनाम समूह जो कि निरूद्देश्य ही आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं। उन पर नजर रखने में असफल रही हैं। घरेलू आतंकी समूहों की जांच करने के उपरान्त भी मुंबई, पुणे, हैदराबाद में हुयी आतंकी वारदातों को हमारी खुफिया और आतंकवाद रोधी एजेंसियां न तो रोक पाई और न ही उनका पता लगा पाई। अब भी हमें खुफिया सूचनाओं की प्रणाली को और पुख्ता करने की जरूरत है। इस हेतु कानून लागू करने वाली संस्थाओं व खुफिया विभागों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए।[7] 'वर्ष 2001 में एम.ए.सी. (Multi agency center) की स्थापना और 31 दिसंबर 2008 को एस.एम.ए.सी. (Subsidiary multi agency centre) की प्रत्येक

राज्य राजधानी में स्थापना से अब कार्य अधिक कुशलता से हो रहा है जो कि एक सराहनीय कदम है।'[8] देश की आतंकवाद से आंतरिक सुरक्षा के लिए सभी उपयों के नियंत्रण व समन्वय के लिए एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी हो जो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हो। एन.सी.टी.सी. (National counter terrorism centre) के मसले पर 20 मार्च 2013 को सरकार बहुमत से जीत गई है। इसको गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून 1967 की धारा 43 (ए) के तहत गिरफ्तारी व तलाशी का अधिकार होगा। अतिरिक्त निदेशक स्तर का अधिकारी निकाय का प्रमुख होगा। इसमें तीन प्रभाग होंगे। हर प्रभाग का प्रमुख खुफिया विभाग के संयुक्त निर्देशक स्तर का अधिकारी होगा। ये प्रभाग खुफिया जानकारी एकत्र करने, उन्हें वितरित करने, विश्लेषण और परिचालन से जुड़े होंगे। मुंबई आतंकी हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गयी थी। एन.सी.टी.सी. को एन.एस.जी. (National Security Guard) की सेवायें लेने का अधिकार होगा। इसे आतंकवाद के खिलाफ कार्य करने की पूरी छूट

मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी यह पूरे प्रमाणों के साथ कार्य करने को बाध्य हो। यह एक ऐसी संस्था हो जो आतंकवाद से जुड़ी सूचनाओं पर सुनियोजितपूर्ण ढंग से जांच पड़ताल करे।[9] आतंकवाद रोधी उपायों के मामलों में परंपरागत ढंग से सोचना सही नजरिया नहीं है।

सभी राज्यों की सरकार को पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु कदम उठाये जाने चाहिए। सभी राज्यों के डीजीपी का एक अलग से आतंकवाद रोधी समूह बनाया जाए जो दूसरे राज्यों को तुरन्त सूचना दे सके। अभी तक यह कार्य ग्रहमंत्रालय के पास है। सभी राज्यों के पुलिस थानों में आतंकवाद रोधी शाखा की स्थापना हो जो आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने का ही कार्य करे। 22 सितंबर 2006 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये पुलिस सुधारों के दूरगामी निर्देशों का पालन किया जाए। शहरों में सी.सी. टी.वीं कैमरे लगाना, पुलिस को नवीन हथियारों की आपूर्ति, केन्द्र व राज्यों के खुफिया विभागों के बीच समन्वय हेतु अधिकारी की नियुक्ति की जाए। मौजूदा पुलिस प्रणाली पर लोगों का भय कम किया जाए।

आतंकवाद के बारे में विश्वसनीय जानकारियां जुटाने के लिए लोगों को भी दक्ष बनाया जाना चाहिए। जनता व पुलिस के मध्य बेहतर समन्वय होना चाहिए। आतंकवादी जनता व पुलिस के बीच तालमेल की कमी का फायदा उठाते हैं। आतंकवाद रोधी अभियान केवल तभी कामयाब हो सकते हैं जब कानून का पालन करने वाले नागरिक पुलिस के आंख व कान बने। पुलिस का मुखबिर होना निंदासूचक न माना जाये। पुलिस के सामने आने वाली मुश्किलों का जमीनी स्तर पर ही सुधार होना चाहिए नहीं तो शीर्ष स्तर पर भी संस्थायें गठित करने से लाभ नहीं होगा। पुलिस के काम में आने वाले उपकरणों के स्थान पर आधुनिक उपकरण काम में लिए जाने चाहिए। राज्यों की सरकार के पास न तो कोई ठोस नीति है और न ही संसाधन जिससे कि वे पुलिस के स्तर में सुधार कर सके। जब केंद्र व राज्यों में विरोधी गठबंधन हो तब स्थिति और भी गंभीर बन जाती है। वित्त आयोग द्वारा राज्यों को अधिकाधिक सहायता दी जानी चाहिए।[10] साथ ही सूचनाओं के संकलन हेतु सीसीटीएनएस (Crime and Criminal

Tracking Network System) आज के तकनीकी युग की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने देशभर में सीसीटीएनएस मई 2013 तक लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही देश भर के थाने इंटरनेट से जुड़ने के बाद राज्य स्तर पर एक डाटा सेंटर बनाया जाए। इसमें प्रवर्तन निदेशालय व खुफिया विभाग अपनी जानकारियों का आदान प्रदान करें।[11] सभी थाने पुलिस मुख्यालय से चौबीस घंटे ऑनलाइन जुड़े रहें। इस चुनौती से निपटने हेतु रात्रि में दूसबीननुमा उपकरण प्रयुक्त किये जायें। दूरबीननुमा यह उपकरण इस तरह से बनाया गया है कि आसानी से स्वतः चालित उपकरणों से जोड़े जा सकते हैं। इनकी मदद से गहरे अंधेरे में भी दो सौ से तीन सौ मीटर की दूरी तक स्पष्ट देखा जा सकता है।[12]

आतंकवाद जैसे विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहां प्रश्न ऐसी परिस्थितियों से जूझने के लिए सबको विश्वास में लेने का है। ऐसे विषय पर सर्वानुमति बनाना आवश्यक हो। केंद्र बनाम राज्य के टकराव में बदल देने की बजाय इस पर समग्रता से विचार किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार को सभी राज्यों की सरकार व विपक्ष की राय लेनी चाहिए व उनकी शिकायतों का निवारण होना चाहिए। लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राजनीतिक लाभ पाने की कोशिशें आतंकवाद से लड़ाई पर भारी न पड़ जाए। ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों का केंद्र की आई.बी. (Intelligence Bureau) के तहत एनसीटीसी के गठन के विरोध से प्रतीत होता है कि आतंकवाद जैसे विषय पर टकराव होना ठीक नहीं है।[13]

देश में हानिकारक रसायनों के भंडारण व विक्रय पर कड़ी रोक लगायी जानी चाहिए। हैदराबाद विस्फोट में बाजार में जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसित डिवाइसेज लगाया गया था उसमें उर्वरक आधारित अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था जो हमारे देश में आसानी से मुहैया हो जाता है। यहाँ इसे लेकर कड़े प्रतिबंध अभी तक नहीं लगाए गए हैं। इसी शिथिलता के कारण आतंकी समूहों ने बार–बार अमांनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है।[14] आतंकवाद रोधी कानूनी को कठोरता से लागू

किया जाए। भारत में आतंकवाद रोधी कानूनों में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून 1967, टाडा (3 सितंबर 1987–1995), मकोका (24 अप्रेल 1999), पोटा (28 मार्च 2002), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून 2004, 2008, 2011, 2012 में लागू किए गए हैं। काले धन का आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। मनी लांडरिंग निरोधक (संशोधन) विधेयक 2011 की कालेधन के दुरूपयोग पर रोक लगाने के प्रयास में तेजी लाई जानी चाहिए। वर्ष 2002 में बनाए गए इस कानून में 2005 व 2009 में भी संशोधन हो चुके हैं। पुराने कानूनों को और अधिक कठोर कानूनों से बदला जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरकार में बदलाव की पर्याप्त इच्छा शक्ति दिखाई दे।[15] न्याय के संदर्भ में इसका समय से होना और सभी के साथ समान रूप से होना अनिवार्य माना जाता है। न केवल आतंक फैलाने वालों को बल्कि उनकी मदद करने वालों को भी कठोर सजा के प्रावधान हो।

मुंबई में माफिया समूहों को खत्म किया जाए। यद्यपि लंबे समय से इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी आतंकवाद रोधी दस्तों को और

अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए। स्वस्थ नागरिकों को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण का प्रावधान होना चाहिए। देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में आत्मरक्षा के तौर पर यह आवश्यक हो गया है। राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण गैर सरकारी विधेयक 2013 को मंजूरी दी जा चुकी है।[16]

भारत में माओवादी व नक्सली हिंसा की जड़ें शोषण में छिपी हुई है। उन पर होने वाले अत्याचारों ने उन्हें बंदूक थामने को मजबूर किया है। यहां अमीरी गरीबी की खाई शर्मनाक है। छत्तीस करोड़ लोग गरीबी की श्रेणी में आते हैं। भारत की सबसे बड़ी संपदा इसके एक अरब से ज्यादा लोग हैं। इन सबको पेट भरने के लिहाज से यहां पर्याप्त अन्न पैदा होता है। फिर भी प्रचुरता के बीच भूख का विरोधाभास बना हुआ है। जिसमें लोग हथियार उठाने को मजबूर हो जाते हैं।[17] लेकिन माओवादी व नक्सलवादी लड़ाके हथियारों को थामने के बजाय आदिवासियों के प्रामाणिक प्रवक्ता बन जाये तो केंद्र व राज्य सरकारों को हिलाकर रख सकते हैं। अब नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी उनकी

समस्त लोक कल्याणकारी मांगें माननी पड़ेगी लेकिन उन्हें यह भी बता देना चाहिये कि इसके बावजूद हिंसा जारी रही तो उसे रोकने के कड़े उपाया करेंगे।[18] जंगलों में नक्सलियों को खोजने के लिए 'नेत्र' जैसे अन्य उपकरण भी विकसित किये जायें। यह ऐसा यंत्र है जो दिन या रात में पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकता है। इसके द्वारा भेजी गई तस्वीरें कम्प्यूटर पर देखी जा सकती हैं। मानव रहित हवाई तकनीक पर आधारित 'नेत्र' को झारखण्ड के सीआरपीएफ बेड़े में शामिल कर लिया गया है।[19]

यह सत्य है कि भारत की सरकार अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया में सैंकड़ों निर्दोष नागरिकों की बलि नहीं चढ़ा सकती लेकिन वह भारत को अराजक राज्य भी बनने नहीं दे सकती है। अतः आतंकवाद से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि सरकार, राजनीतिक दल, सरकारी एजेंसियां नियत काम पर ध्यान लगायें।

संदर्भ सूची

1. कुलदीप नैयर, चीन की पड़ौस में हठधर्मी, दैनिक नवज्योति, 15 सितंबर 2010, पृष्ठ : शेष विशेष

2. भारत से रिश्ते सुधारेगा चीन, राजस्थान पत्रिका, 20 मार्च 2013, पृष्ठ 15

3. पाकिस्तान के साथ संवाद, दैनिक नवज्योति, 10 फरवरी 2011, पृष्ठ : शेष विशेष

4. राजस्थान पत्रिका, 26 फरवरी 2012, पृष्ठ 19

5. अफसर करीम, खतरों से घिरी हमारी सुरक्षा, राजस्थान पत्रिका, 23 मार्च 2013, पृष्ठ 15

6. गुरमीत कनवाल, इंडियन बोर्डर सिक्योरिटी पूअर मेनेजमेंट इन एवीडेंस, 2007, पृष्ठ 55

7. अफसर करीम, कैसे खत्म होगा ये सिलसिला, राजस्थान पत्रिका, 20 मार्च 2013, पृष्ठ 15

8. वी.पी. मलिक, इंटरनल सिक्योरिटी मेनेजमेंट : चेलेंजेज एंड पॉलिसी ऑपशन्स

9. राजस्थान पत्रिका, 26 फरवरी 2012, पृष्ठ 19

10. मधुकिश्वर, पुलिस सुधारों की चुनौती, दैनिक भास्कर, 3 अक्टूबर 2011, पृष्ठ 6

11. दैनिक भास्कर, 2 अप्रेल 2013, पृष्ठ 2

12. दैनिक भास्कर, 2 अप्रेल 2013, पृष्ठ 9

13. आतंकवाद बनाम सियासत, दैनिक भास्कर, 20 फरवरी 2012, पृष्ठ 6

14. अफसर करीम, कैसे खत्म होगा ये सिलसिला, राजस्थान पत्रिका, 20 मार्च 2013, पृष्ठ 15

15. जोगिन्दर सिंह, मुल्क की हिफाजत के लिए कठोर कानून जरूरी, दैनिक भास्कर, 8 जनवरी 2012, रसरंग, पृष्ठ 1

16. दैनिक भास्कर, 15 अप्रेल 2013, पृष्ठ 1

17. हर्षमंदर, विपुलता के बीच भूख की यह लाचारी, दैनिक भास्कर, 27 अक्टूबर 2012, पृष्ठ 6

18. वेद प्रताप वैदिक, माओवादी हिंसा की चुनौती, दैनिक भास्कर, 2 मई 2012, पृष्ठ 6

19. दैनिक भास्कर, 8 अप्रेल 2012, पृष्ठ 7

पंचम

अध्याय

आतंकवाद की समाप्ति हेतु गांधीय विकल्पों का आकलन

भारत में आतंकवाद की समाप्ति हेतु दो ही विकल्प नजर आते हैं। जहां एक ओर हिंसा का विकल्प अनिवार्य रूप से द्वेष, युद्ध विनाश की ओर ले जा रहा है वहीं दूसरी ओर अहिसक मार्ग प्रेम, शांति और सबके कल्याण की ओर ले जाने वाला है। इस अहिंसक मार्ग के चुनाव का लक्ष्य शांति का संदेश पेश करना है उस संसार के सामने जो आतंकवाद रूपी अग्नि से छिन्न–भिन्न हो रहा है।

यह सवाल कि क्या गांधीय विकल्प आतंकवाद को रोकने में सफल हो सकते हैं? इसके प्रतिउत्तर में यह कहा जा सकता है कि आतंक रूपी तमाम कार्यवाहियां चाहे वे किसी भी माध्यम से की जाये, उनके विरूद्ध लड़ाई बुनियादी रूप से एक नैतिक लड़ाई ही हो सकती है। वह कानून व व्यवस्था मात्र की ही समस्या नहीं होती। एक बार यदि नैतिक शक्ति को ही जाग्रत कर दिया जाये तो यह समस्या धीरे–धीरे हल की जा सकती है। मानवीय मूल्यों को अपनाते हुये आतंकवाद की समाप्ति का यह अहिंसक तरीका कितना कारगर सिद्ध हो पाता है इसका अध्ययन गांधीय

विकल्पों के संदर्भ में आकलन व विश्लेषण के माध्यम से कर सकते हैं। सर्वप्रथम अहिंसा पर नजर डालें तो क्या विरोध का गांधीवादी अहिंसक तरीका काम करता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग के प्रो. स्टीवन पिंकर की पुस्तक 'द बेटर एंजेल्स ऑफ आवर नेचर' मानव के इतिहास में कम होती हिंसा को रेखोंकित करती है। पिंकर ने इसकी पुष्टि करने में पेस्लियान यूनिवर्सिटी के जैकेलिन स्टीवंस के नए अध्ययन का हवाला दिया है। जिसमें हिंसक व अहिंसक आंदोलनों की श्रृंखला पर नजर डाली गयी, केवल पच्चीस प्रतिशत हिंसक व पिचहत्तर प्रतिशत अहिंसक संघर्ष कामयाब हो रहे हैं।'[1] इस संबंध में ऑक्सफोर्ड शोध समूह की संस्थापक सेला एल्वर्धी ने आतंकवाद रूपी हिंसा को अहिंसा से खत्म करने के तरीकों की खोज की है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका खुद में बदलाव लाने का है।[2]

एकमात्र वस्तु जो हमें पशु से भिन्न करती है वह है अहिंसा। इसकी साधना से बैरभाव निकल जाता है। बैरभाव के जाने से काम, क्रोध आदि वृत्तियों का निरोध होता है। इससे शरीर निरोगी बनता है। मन में शांति व आनंद का अनुभव होता है। सही व गलत में भेद करने की ताकत आती

है। जब भी हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है जो एक बार टोकता जरूर है। हमारे अन्तः करण में आग्रह का भाव जागता है। दया, उदारता का भाव एक बार शरीर के रग रग में बहता जरूर है। यदि हम भीतर की सत्ता से जुड़े रहें तो बाहर की सत्तायें हमसे गलत काम नहीं करवायेंगी। यह जीवन के सही बोध के अभाव से जन्म लेता है। इस समस्या को सेना, पुलिस, कानून की मदद से रोकना पूरी तरह से संभव नहीं है। हमें मानव जाति को जीवन के सही उद्देश्य का बोध कराना होगा। उनके दिलो–दिमाग का शुद्धिकरण जरूरी है। एक बुनियादी जीवन मूल्य के रूप में अहिंसा पर आग्रह एक जरूरी निर्णय है। हिंसा के स्रोत्र हमारी जीवन व्यवस्था में ही बिखरे हुये हैं। यदि व्यक्तियों के आपसी संबंधों में ही अहिंसा नहीं है तो हिंसा के मार्ग से छुटकारा नहीं मिल सकता है। व्यक्ति को अहिंसा की शिक्षा तो देनी ही चाहिये, घर से लेकर विद्यालय, महाविद्यालय तक और विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भी, लेकिन यह शिक्षा तभी फलीभूत हो सकेगी जब व्यवस्था को भी अहिंसा प्रधान बनाया जाये। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब तक धरती पर अन्याय है तब तक आतंक रहेगा। इसका प्रयोग या तो अन्याय

आरोपित करने के लिये किया जायेगा या फिर अन्याय का प्रतिकार करने के लिये। लेकिन ''भारत पर आक्रमण करने वाले लुटेरों, चोरों, राष्ट्रों से निपटने के लिये हिंसा का सहारा लेना ही उचित है। लेकिन इसमें अच्छी तरह कामयाब होने के लिये हमें अपने पर संयम रखना सीखना चाहिये।[3] दुनिया केवल तर्क के सहारे नहीं चलती जीवन में थोड़ी बहुत हिंसा तो है ही। अतः हमें न्यूनतम हिंसा के रास्ते को अपनाना है।[4]

सत्याग्रह ही अहिंसा की कुंजी है। यह वह माध्यम है जिसके बल पर शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी लड़ सकता है। हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि विरोधी को प्रेमपूर्वक समझाकर उसके दिलोदिमाग पर असर डालकर उसका ह्रदय परिवर्तन कियाजाये। यदि हम स्वयं को अपने विरोधी की स्थिति में रखकर उसके दृष्टिकोण को समझे तो संसार के अधिकांश दुःख और गलतफहमियां मिट सकती हैं। इसका उद्देश्य विरोध का अंत करना है न कि विरोधी का। मूल बात यह है कि हम सत्य पर अडिग हो, साधन शुद्धि पर हमारा भरोसा हो। सत्याग्रह होना चाहिये

समाज को बेहतर बनाने के लिये, स्वयं अपने भीतर के कलुषों को मिटाने के लिये।[5] सत्याग्रह की यह नीति आतंकवाद को रोकने में भी प्रभावी है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है मध्यप्रदेश के पूर्व आत्मसमर्पित दस्यु डाकू बी.के. पंचम सिंह चौहान। उन्हीं के शब्दों में, ''इंसान को परिस्थितियां गलत राह की ओर ले जाती हैं। व्यक्ति अपने को भूलकर गलत मार्ग पर चल पड़ता है लेकिन सही संगत और सीख उसे ईश्वर की राह पर वापस मोड़ सकती है। जब वाल्मिकी जैसे दस्यु के कुछ साधुओं की प्रेरणा से महाकवि और संत बनने के उदाहरण पहले से मौजूद है तो फिर असंभव कुछ नहीं। अब एक ही मकसद है, कोई मेरे जैसे राह न भटके। मिशन के रूप में मैं लोगों को चरित्रवान एवं पवित्र बनने के लिये प्रेरित कर रहा हूं।'' इन्होंने अपने चौदह साल के दस्यु जीवन में सौ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 1972 में उन पर दो करोड़ का इनाम घोषित था। जय प्रकाश द्वारा अपील करने पर फांसी की सजा माफ हुयी। इसी दौरान प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाईयों बहनों ने सरकार से अनुमति लेकर पांच सौ पचास डाकुओं को तीन वर्ष तक खुली जेल में

आध्यात्मिक अभ्यास कराया। यहीं पर इनका ह्रदय परिवर्तन हुआ और जब चौथी कक्षा पास दस्यु की जुबान से श्रीमद् भागवतगीता के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या ठीक उसी प्रवाह में होती है जैसे किसी विद्वान कथावाचक के श्रीमुख से।[6]

जिंदगी संवारने की एक ऐसी ही कोशिश मणिपुर की युवा लेखिका बीना लक्ष्मी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र` दस्तावेज 'ट्रेफिकिंग इन स्मॉल आर्म्स एंड सेंसेटिव टेक्नोलॉजीज' के प्रकाशन के बाद उठा उनका पहला कदम जिसने यह समझाया कि छोटे हथियार ही स्थानीय अशांति का मुख्य स्रोत बने हुये हैं। बंदूक जैसे छोटे हथियार जो तस्करी व कालाबाजारी की सहायता से युवाओं के हाथों में आ रहे हैं, उन पर रोक लगाकर लोगों की आतंकी कृत्यों में लिप्तता पर रोक लगायी जा सकती है। उनका प्रमुख लक्ष्य है कि लोग किसी भी कीमत पर हथियारों की तस्करी या खरीद फरोख्त के रोजगार में शामिल न हो।[7]

25 जनवरी 2012 को अठारह सौ पचपन उग्रवादियों ने तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम के सामने गुवाहाटी में समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिये समर्पण कर दिया। इन संगठनों के साथ सरकार ने युद्ध विराम संधि

की थी। हमारी पहल यह होनी चाहिये कि सबको सपने देखने का अधिकार है। उनके दुःखों में हम उनके सहभागी बने।

सर्वोदय का अर्थ है आदर्श समाज व्यवस्था। सबका उदय, सबका उत्कर्ष। बिना किसी भेदभाव के सबके विकास की कामना। इसमें राजा रंक, हिंदू मुसलमान, छूत अछूत, संत पानी सबके लिये स्थान है। इसकी नीति है समन्वय। दुनियाँ में शांति तब तक नहीं बनी रह सकती जब तक साठ प्रतिशत गरीब लोगों की जरूरत विश्व की आय के सिर्फ छः प्रतिशत से पूरी होती हो। पूर्ण से पूर्ण संसार में भी असमानताओं से नहीं बचा जा सकता है। दुनियां में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वह चीज नहीं है हालांकि वे उसे चाहते हैं। अगर भूखे और अभावग्रस्त लोगों को हम कहीं उसी चीज के साथ मिल जाये तो वे न केवल हमारे साथ उसे बांट लेना चाहेंगे बल्कि उसे हमसे छीन लेना चाहेंगे। वे लोग अगर उस वस्तु को चाहते हैं और छीन लेने पर उतारू है तो इसलिए नहीं कि उनके मन में हमारे प्रति कोई द्वेष है बल्कि इसलिए कि उनकी जरूरत हमारी जरूरत से बड़ी है। इसमें दोष कहीं न कहीं बुनियाद में ही है। यहां प्रश्न राज्य

का नहीं स्वयं का है, किसी वर्ग या समुदाय के स्वयं का नहीं बल्कि सर्व के 'स्व' का है। जिसमें जब देश के बारे में बात की जाये तो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी ओझल न हो पाये। सबको समान महत्व मिले।[8] सर्वधर्मसमभाव अर्थात् सभी धर्मों को समान मानकर उनमें जो भी अच्छी बातें हैं वे ग्रहण कर ली जाये। भारत में जन्मे लोग चाहे वे किसी भी धर्म, संप्रदाय के क्यों न हो, राष्ट्रीयता के आधार पर भारतीय हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत में धर्म से उत्पन्न आतंक को समाप्त करने के लिये यह कोशिश की जाये कि यहां की सामान्य जनता का जीवन स्तर उन्नत हो, रोजगार के साधन स्थायी एवं परिपूर्ण हो। किंतु यह ध्यान रखा जाये कि सभी कानूनों से बढ़कर प्रेम का कानून है जिसमें संघर्ष का कोई स्थान नहीं है। क्रूरता का जवाब क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक एवं बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है।

'वृक्ष का अंकुर जिस प्रकार झुक जाता है, वृक्ष भी उसी प्रकार झुक जाता है। ठीक इसी प्रकार शिक्षा जिधर मानव मन को मोड़ती है मानव उधर ही मुड़ जाता है।[9] इस दृष्टि से शिक्षा शास्त्र वस्तुतः व्यक्तित्व निर्माण

का ही विज्ञान है। जिससे मानव व्यक्तित्व के अन्तर्निहित आध्यात्मिक, बौद्धिक, भौतिक सभी गुणों का विकास हो सके। शिक्षा का उद्देश्य साक्षर होना नहीं बल्कि आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति का जरिया होना चाहिए। बालक को किसी एक न एक व्यवसाय में इतनी दक्षता प्रदान करा दी जाये कि वह आत्मनिर्भर हो सके। शिक्षा जब तक व्यावहारिक नहीं होगी तब तक अधूरी रहेगी। उद्योग को शिक्षण का एक साधन नहीं बल्कि उसका अविभाज्य अंग स्वीकार किया जाये तो देश में बढ़ रही बेकारी की समस्या का समाधान हो सकता है।[10]

कोठारी आयोग के अनुसार भी हम चाहे कला और काव्य की सुषमाओं का ज्ञान प्रापत करना चाहे या विज्ञान के आश्चर्यजनक आविष्कारों को समझना चाहें या फिर किसी कला कौशल में पूर्ण दक्षता ही प्राप्त करना क्यों न चाहें हमें कर्म केंद्रित करना होगा।[11]

पाकिस्तान नाभिकीय वैज्ञानिक परवेज हुद्रभाय के अनुसार वहां तालीम के जरिये ही बच्चों को आतंक की ओर धकेला जा रहा है। ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बंदूक, एच फॉर हिजाब, जे फॉर जिहाद, टी फॉर

टकराओ, के एच फॉर खंजर जैसे कट्टरपंथी और भारत विरोधी विचार उनके दिमाग में भरकर आतंकवाद की जड़ें मजबूत की जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम मतभेद, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मंसूबों, शहादत तथा जिहाद पर व्याख्यान उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है।[12] इसलिए शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश हो। क्योंकि शिक्षा का अर्थ बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुंमुखी विकास करना हो। 'प्रेम ज्ञान के ग्रंथ को खोलने से नहीं बल्कि ह्रदय ग्रंथि को खोलने से होता है।'

स्वराज्य में स्व व राज्य दो शब्दों का योग है जिसका अर्थ है अपने ऊपर शासन करना। इसमें सरकार एक हास्यास्पद चीज बन जायेगी अगर जीवन की हर छोटी बात के नियमन के लिये लोग उसकी ओर देखने लगेंगे। इसमें हर गांव का नियमन व्यक्ति स्वयं करे। जिसमें अपनी जरूरतों के लिए पड़ौसी पर भी निर्भरता न हो, अधिक से अधिक व्यक्ति स्वावलंबन के आधार पर कार्य करे, सभी आत्मनिर्भर हो, लेकिन बहुतेरी जरूरतों के लिये परस्पर सहयोग से कार्य करे। ऐसी ग्राम स्वराज्य की

कल्पना भारत के गांवों में स्पष्टतया परिलक्षित होती है। दिल्ली में त्रिलोकपुरी व मयूरविहार में चल रही मोहल्ला सभा, आंध्रप्रदेश के वारंगल जिले की मचापुर ग्राम पंचायत का गंगादेवी पल्ली गांव, राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील का गोपालपुरा गांव, महाराष्ट्र के गढ़ चिरोली का मेढ़ा गांव (धनोड़ा तहसील), झुंझुनू के निकट बख्तावरपुरा, टोंक जिले का सोड़ा गाँव, चेन्नई का कुटुंबक्कम गांव, आदि ऐसे उदाहरण हैं जहां ग्रामवासियों ने जिंदगी बदलने के लिये आतंक की ओर मुड़ने के बजाय ऐसे कदम उठाये जिन्होंने यहां की तस्वीर ही बदल दी। यहां के लोगों द्वारा शिक्षा, कायिक श्रम, जनभागीदारी के माध्यम से ऐसे प्रयास हुये हैं जिसमें जनता में न तो किसी प्रकार का शोषण है और न ही बेरोजगारी की समस्या। यहां सभी की आत्मनिर्भरता इन्हें अपराधी कृत्यों की ओर मुड़ने का मौका नहीं देती है।

ऐसा ही प्रयास आंध्रप्रदेश में 1936 में जन्मे डॉ. गुट्टा मुनिरत्नम ने ग्रामसेवा को अपना मिशन बनाते हुये किया है। गांव में रहने वाले ग्रामीण समाज, गरीबों की विभिन्न समस्याओं का निदान गांधीवादी तरीकों से

करना शुरू किया। इसके लिए राष्ट्रीय सेवा समिति नामक संस्था स्थापित की। स्वदेशी व ग्राम स्वराज्य के सिद्धान्त को अमल में लाते हुये लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना कर ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना उनका मकसद रहा। वह अनेक समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर भी काम करते रहे हैं।[13] शांति सेना भी इस बदलाव में सहायक सिद्ध हो सकती है। यदि प्रयास स्थानीय स्तर से, अपने घर, मोहल्ले, गांव से ही शुरूआत की जाये। अलखनंदा सिंह जैसे शख्स की पहचान एक नक्सली के रूप में होती थी। आज से वे नंदा महोदय के नाम से जाने जाते हैं। बिहार के गया जिले के नक्सली प्रभावित क्षेत्र बाराचट्टी के डुमरी और आसपास के क्षेत्र में नंदा गरीब बच्चों को कई सालों से निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। वे इन बच्चों की जरूरत का सामान सप्ताह में एक बार गांव में घूमकर चंदा इकट्ठा करके लाते हैं। जहानाबाद का यह युवक कभी नक्सलियों के दस्ते का महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करता था। गरीबों को अधिकार दिलाने की भावना से नंदा ने माओवादियों का हाथ थामा लेकिन जल्द ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गये। जेल में महात्मा गांधी, मदर टेरेसा

को पढ़कर उन्हें लगा कि गरीबों का भला बंदूक से कभी नहीं हो सकता। जेल से निकलते ही गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। आज उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ता जुड़ चुके हें जो तन मन से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। इस क्षेत्र में तीन विद्यालय चल रहे हैं जिनमें चार सौ से ज्यादा छात्र निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं। इस कार्य की सफलता में इन स्थानीय कार्यकर्ताओं का ही योगदान है जिन्होंने शुरूआत स्थानीय स्तर से की है।[14]

ट्रस्टीशिप उन सिद्धान्तों में से है जिन पर सर्वाधिक विरोधाभास है। यह सिद्धान्त आध्यात्मिकता का प्रतीक है जिसका आधार अपरिग्रह वृत्ति है। यह संचय की मनोवृत्ति को ही बदलने का सिद्धान्त है जो स्वैच्छिक आधारों पर साधनों के समाज में न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना चाहता है। यह इस बात पर आधारित है कि जिसके पास धन है, वह उसे अपना समझकर फिजूलखर्च न करे, थाती समझकर रखे और जनकल्याण में खर्च करे। आर्थिक समानता की जड़ में धनिक का ट्रस्टीपन निहित है। वर्तमान में बदली हुयी परिस्थितियों में इसका व्यापक स्तर पर सफल

प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि सबके सोचने का तरीका जमनालाल बजाज और बिलगेट्स जैसा नहीं हो सकता है। स्वयं गांधी के शब्दों में, ''ट्रस्टीशिप तो एक कल्पना मात्र है व्यवहार में उसका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन यदि लोग इस पर विचार करे और उसे आचरण में उतारने की कोशिश भी करते रहे तो मनुष्य जाति के जीवन की नियामक शक्ति के रूप में प्रेम आज जितना प्रभावशाली दिखाई देता है उससे कहीं अधिक दिखाई पड़ेगा। पूर्ण ट्रस्टीशिप तो युक्लिड की बिंदु की व्याख्या की एक कल्पना ही है और उतनी ही अप्राप्य भी है। लेकिन यदि उसके लिये कोशिश की जाये तो दुनियां में समानता की स्थापना की दिशा में हम दूसरे किसी उपाय से ज्यादा दूर तक जा सकेंगे।[15] लेकिन धनिक ही नहीं श्रमिक भी स्वयं को अपने श्रम का ट्रस्टी माने। गरीब आदमी भी अपनी रोटी कमाता है तो उस रोटी पर नहीं वरन् भूख पर उसका अधिकार है। यदि कोई पड़ौसी भूखा है तो उसे रोटी बांटकर खाना चाहिए, यही ट्रस्टीशिप का आदर्श है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई न कोई शक्ति न हो। जितनी शक्तियां है उन सबका

मनुष्य केवल ट्रस्टी बने। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा समझेगा तब समाज में सर्वोदय की व्यवस्था होगी। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके का गांव है पिठौरिया। यहां रहने वालों का प्रमुख पेशा खेती है लेकिन छत्तीस साल से गांव वाले दसवीं तक का एक विद्यालय चला रहे हैं। 1977 के दौरान अच्छे विद्यालय की कमी को समझते हुये उसका हल खुद ही ढूंढा। किसान कमेटी बनाई। पांच एकड़ जमीन, खेती की कमाई का एक हिस्सा तथा पढ़े लिखे युवकों की सेवा से यह विद्यालय शुरू हुआ। वर्तमान में यहां एक सौ अठानवे छात्र व तीन सौ सतानवे छात्रायें हैं। इन्हें शिक्षा के साथ–साथ खेती भी सिखाई जाती है। प्रत्येक किसान गुप्त रूप से नगदी देने के अतिरिक्त एक रूपये में एक टोकरी किसान कमेटी को बेचता है। तीन से पांच हजार टोकरियां हाट में बेची जाती है। जिनसे लगभग बारह से बीस हजार रूपए विद्यालय को मिलते हैं।[16]

यह बदलाव स्थानीय स्तर की मेहनत का ही नतीजा है। यदि जमीनी स्तर पर ही सुधार नहीं होंगे तो शीर्ष स्तर पर गठित संस्थायें भी बेहतर प्रबंधन नहीं कर पायेंगी। यह पहल नागरिकों को ही करनी है।

संदर्भ सूची

1. सही है गांधी का रास्ता, राजस्थान पत्रिका, 2 जनवरी 2012, पृष्ठ 21
2. अहिंसा के लिए गुस्से पर काबू करना जरूरी, दैनिक भास्कर, 11 दिसंबर 2012, पृष्ठ 6
3. महात्मा गांधी, यंग इंडिया, 29 मई 1924, पृष्ठ 176
4. महात्मा गांधी, हरिजन, 28 सितंबर 1934, पृष्ठ 259
5. पुनीत शुक्ला, गांधी विचार आज भी प्रासंगिक हैं, 2 अक्टूबर 2008
6. दस्यु अब बता रहे हैं गीता के रहस्य, दैनिक भास्कर, 5 सितंबर 2011, पृष्ठ 2
7. संगीन के साये में जिंदगी संवारने की कोशिश, राजस्थान पत्रिका, 22 जनवरी 2012, पृष्ठ 1
8. महात्मा गांधी, सर्वोदय
9. डॉ. रामजी सिंह, गांधी दर्शन मीमांसा, पृष्ठ 253
10. महात्मा गांधी, हरिजन, 11 सितंबर 1937
11. राधा कृष्णन कमीशन रिपोर्ट, भाग 1, पृष्ठ 42

12. पाक के स्कूलों में ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बंदूक, दैनिक भास्कर, 25 जून 2012, पृष्ठ 1

13. गांधी के रास्ते पर ....., राजस्थान पत्रिका, 5 फरवरी 2012

14. बंदूक छोड़कर थामी निःशुल्क शिक्षा की राह, राजस्थान पत्रिका, 4 मार्च 2012, पृष्ठ 1

15. स्टडीज इन गांधीज्म, पृष्ठ 201

16. किसानों का जुनून : खेती की कमाई स्कूल में लगा देते हैं, दैनिक भास्कर, 24 फरवरी 2013

निष्कर्ष एवं आत्मकथन

आतंकवाद कभी जिहाद, स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में सामने आता है तो कभी इसे उत्पीड़न व शोषण के विरूद्ध संघर्ष कह दिया जाता है लेकिन यह तो शुद्ध उन्माद है। भारतीय मनोविज्ञान में जिसे बौद्धिक सन्निपात कहते हैं यह उसकी पराकाष्ठा है। इसके संगठन व तरीके अलग होते हैं लेकिन इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक लोगों को हताहत कर समाज में दहशत फैलाना होता है। यह एक ऐसी प्रमुख समस्या है जिसके विरूद्ध लड़ाई निरंतर है। समय–समय पर इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का कोई ठोस व उत्तरदायी एक प्रमुख कारक अब तक सामने नहीं आया है। देश, काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां ही इसकी आधारभूमि होती हैं। कहीं पर यह संरचनात्मक तकनीकी ढांचागत अव्यवस्थाओं के रूप में भी सामने आया है। राज्यों के हित, भूमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण के स्तर तक राजनीतिक संरचनाओं का विकास न हो पाना, असमानता की स्थिति, सामाजिक अन्याय आदि इसके अनेक कारक सामने आये हैं। इसके लिए किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

वैश्विक संदर्भ में गरीबी को भी मुख्य कारक नहीं माना जा सकता है क्योंकि आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोग तकनीकी क्षेत्र में माहिर होते हैं। वे अधिकांश गरीब परिवारों से नहीं आते हैं। उनके पास तकनीकी क्षेत्र की डिग्रियां होती हैं। फिर गरीबी को तो ऐसे कारक के रूप में गिन सकते हैं जिसे आर्थिक विकास की दर को बढ़ाकर रोका जा सकता है। अतः वैश्विक संदर्भ में यह कोई महत्वपूर्ण कारक नहीं कहा जा सकता है। भारत बाहरी व घरेलू दोनों तरह के आतंकवाद का शिकार रहा है। हमारे यहाँ इसके प्रमुख कारक धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैं तो बाहरी तौर पर हमारी सीमायें, आधुनिकीकरण का विकास, व्यापार व तकनीकी परिवर्तन इसके जिम्मेदार कारक हैं। हमारे यहां धर्म इसके प्रमुख कारण के रूप में उभरा है। निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा धार्मिक कट्टरता को अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। संसाधनों का असमान वितरण, अवसरों का सबके लिए उपलब्ध न हो पाना, गरीबी यहाँ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कर देने के लिए पर्याप्त है। मानसिक रूप से कमजोर लोगों को प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाना यहां नई बात नहीं है। इसी तरह नक्सल समस्या

केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। नक्सलियों का प्रमुख तर्क यही है कि उन पर होने वाले अत्याचारों ने बंदूक थामने पर मजबूर किया है। उत्तर पूर्वी इलाकों में सरकार बुनियादी विकवास को नजरअंदार करती रही है। वंचित लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनमें गरीबी, भूख की समस्या है। यहां शहरीकरण की गति अत्यंत धीमी है। हमारे जैसे विकासशील देश में लोगों को शहरों में अति उत्पादकता वाले औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़े बगैर बड़े पैमाने पर गरीबी हटाने में हम सफल नहीं हो सकते हैं हम आज भी जीवन प्रत्याशा, मानव विकास जैसे सूचकांक में पिछड़े हुए हैं। इसे सुधारने के प्रयास भले ही जारी हों लेकिन आतंकवाद जैसे मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह बनाना कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बना है। हमारे यहां शहरी और औद्योगिक वृद्धि दर सरकारी नीतियों के कारण अवरूद्ध है। ये नीतियां आधारभूत ढांचे को अपंग बनाती हैं, युवाओं के कौशल विकास की अनदेखी करती हैं। ग्रामीण इलाकों के लोगों को झूठी उम्मीदों का सहारा देने के लिए तोहफे बांटना, योजनायें शुरू करना, ग्रामीणों को आगे और ऊपर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय वहीं ठहरे रहने का प्रलोभन देना है। इस प्रकार यहां सामाजिक अलगाव व

विषमता बढ़ी है। यही विषमता व अन्याय झुंझलाहट व क्रोध पैदा करती है। जब यही झुंझलाहट एक प्रकार के मानसिक रोग में परिवर्तित हो जाती है तो हर बात का समाधान हिंसा व बल प्रयोग से ही कर लेना स्वाभाविक लगता है। इसी कमजोरी का लाभ उठाकर असामाजिक, अवांछित तत्वों द्वारा लोगों को इस ओर धकेला जा रहा है। इस प्रकार घरेलू आतंकवाद में अहम कारक अन्याय व शोषण की प्रवृत्ति ही है। भारत की गणना दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश के तौर पर हुयी है। हमारी पुरानी कानूनी व्यवस्था भी इससे लोहा लेने की कोशिश में बाधायें खड़ी करती है। हम बाहरी मोर्चे पर पड़ौसियों से भी घिरे हुए हैं। भारत में खतरा अभी टला नहीं है। विगत समय में यदि बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं हुयी है तो इसकी वजह हमारे पड़ौसियों की अंदरूनी हालत हैं। भारत की सुरक्षा को बाहर व भीतर दोनों ओर से ही गंभीर खतरा है। इसके लिए भ्रष्ट व अयोग्य नेता, उग्र वामपंथी विचारधारा, विदेशी संगठन व एजेंसियों भी जिम्मेदार हैं। भारतीय राजसत्ता के लिए यह पेचीदा प्रश्न हो सकता है कि वे इससे सैन्य शक्ति से निपटे या विकास की शक्ति से। लेकिन इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्र की विकास की रणनीति में कहीं न कहीं बुनियादी खोट है।

घरेलू या आन्तरिक आतंकवाद को मिटाए बिना हम बाहरी आतंकवाद का खात्मा नहीं कर सकते। हमारा लक्ष्य सिर्फ बुनियादी ढांचे और पहले से ही विकसित लोगों का और विकास नहीं बल्कि मानव विकास होना चाहिए। यदि एक बार गरीबी हटाओं के मुद्दे को ठोस आंकड़ों के रूप में उठायें तो शायद जाति, मजहब, प्रांत की दीवारें ढह जाएं और एक अखिल भारतीय लहर उठ जाये, क्रोध की नहीं आशा की लहर। ऐसी विकास की रणनीति जो समतामूलक हो। साथ ही हम धर्म के सही मायने समझें। यह कट्टरता का नाम नहीं बल्कि श्रेष्ठताओं का समुच्चय होता है। इसका अर्थ विवेकहीन, तर्कहीन मान्यताओं का कट्टरता के साथ अनुसरण करना नहीं है। एक समाज के तौर पर हम सबके लिए यह आत्ममंथन का विषय है। कि हमारा आपसी भरोसा इतरा कमजोर क्यों है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष के लोगों में निराधार अफवाहों से अफरा–तफरी मच जाती है। ऐसे में दीर्घकालिक समाधान विभिन्न समुदायों में ऐसा संवाद बनाना ही हो सकता है जिससे कोई देश के किसी भी हिस्से में खुद को अलग–थलग महसूस न करे। हमारे उदार, सर्वसमावेशी, आधुनिक भारत के लिए उत्पन्न इस चुनौती को रोकने हेतु राजनीतिक नेतृत्व, केंद्र व राज्यों की सरकार की

एजेंसियों के बीच समन्वय होना चाहिए। आतंकी हमलों और उनके बाद हालात को संभालने को लेकर हमेशा तैयार रहने का अभ्यास ज्यादा जरूरी होता है। लगातार उपजे इस दैत्य के विरूद्ध हम ऐसी परिपक्वता हासिल नहीं कर पाये हैं और न ही न्यूनतम क्षति के साथ संभालने की क्षमता हम प्राप्त कर पाये हैं। इस हेतु प्रशासन के साथ–साथ जन जागृति को सच्ची भागीदारी में बदलने की आवश्यकता है। जनता भी अपना उत्तरदायित्व समझे तो हमारे देश के हित में होगा। वर्तमान में हम आतंकवाद की समाप्ति के लगभग सभी हिंसक उपायों को प्रयोग में ला चुके हें। यह हिंसा का विकल्प अनिवार्य रूप से हमें द्वेष, विनाश की ओर ले जाता है। एक ओर रक्षा बजट, अनुसंधानों में बढ़ती प्रवृत्ति, वहीं दूसरी ओर अहिंसक गांधीय उपाय मौजूदा बुनियादी व्यवस्था पर ध्यान लगाए हुए हैं। यह समाज को बेहतर बनाने का मार्ग है। गांधीय उपायों के प्रचार के कार्य की शुरूआत परिवार, गली मोहल्लों से ही हो सकती है।आतंकवाद का मानवीयता के आधार पर संवाद स्थापित करने से भी रास्ता निकल सकता है। पांच सौ बावन चंबल दस्युओं, अठारह सौ पचपन उग्रवादियों का केंद्र सरकार के

समक्ष समर्पण, भारत के अनेक गांवों में चल रहे आत्मनिर्भरता के प्रयास, शिक्षा के प्रयास जिनमें जनता की भी भागीदारी है, इस तथ्य के परिचायक हैं कि लोग हिंसा के बजाय बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं, शांति चाहते हैं और यह शांति उन्हें अहिंसक मार्ग के चुनाव से ही मिल सकती है। यद्यपि इसकी सार्थकता तब ही है जब संपूर्ण जनता इसे अपनाये।

षष्टम

अध्याय

संदर्भ सूची

1. अहमद परवेज — अलकायदा मिशन कश्मीर, 2009
2. आल्टरमेन जे.बी. — हाउ टेर्ररिज्म एंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, वाशिंगटन डीसी, 1999
3. अल्जेब ओमर व अल्जेब जीहान — इंटरनेशनल ला डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू टेर्ररिज्म, केवेन्डिश, न्यूयार्क, 2007
4. आनंद वी — डिलिंग विद नक्सलिज्म, वर्ल्ड फोकस, 2006
5. अंडरसनसीन व स्टीफेन स्लोअन — हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ टेर्ररिज्म, विजन, बुक्स, नई दिल्ली, 2002
6. आरनोल्ड डेविड — गांधी, लोंगमन, 2001
7. आर्ट आर.जे. व रिचर्डसन एल — डेमोक्रेसी एंड काउंटर टेर्रिरिज्म : लेशन फ्रोम दि पास्ट वाशिंगटन डीसी, 2006
8. अटरल स्कॉट — दि मोरल लॉजिक एंड ग्रोथ ऑफ सुसाइड टेर्ररिज्म, 2006

9. बारबर बेंजामिन आर — जिहाद वर्सेज एमसी वर्ल्ड टेर्ररिज्म चेलेंज टू डेमोक्रेसी, कोवगी बुक्स, लंदन, 2003

10. बसरूर राजेश — न्युक्लियर इंडिया ऐट दि क्रॉस रोड्स आर्म्स कंट्रोल, 2003

11. बेदी राहुल — माओइस्ट इन्सरजेंसी स्प्रीड्स इन इंडियो, 2006

12. बेल जे.बोअर — ओल्ड ट्रेंडस एंड फ्यूचर रियलिटीज, 1985

13. बेनडेक ई.पी. — दि साइट्रिक आस्पेक्ट्स ऑफ टेर्ररिज्म, वाशिंगटन, 1980

14. बनर्जी दिपांकर — साउथ एशिया एंड दि वार ऑफ टेर्ररिज्म, नई दिल्ली, 2003

15. बनर्जी सुमंत्रा — इंडिया सिमरिंग रेवोल्यूशन दि नक्सलाईट अपराईजिंग, दिल्ली, 1984

16. बेंजामिन स्टोरा — अल्जीरिया 1830–2000 ए शॉर्ट हिस्ट्री, कोरनेल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004

17. बेसिडनी चेरिफ एम. इंटरनेशनल टेर्ररिज्म एंड पॉलिटिकल क्राइम्स, 1975

18. भसीन कमला अमन की तलाश में इंसानियत की आवाजें नई दिल्ली, 2001

19. भाटिया बेला एनाटोमी ऑफ ए मासएकरे दि नक्सलाईट मूवमेंट इन सेन्ट्रल बिहार, 2000

20. भूषण के व काटमाल जीअटेक ऑन पार्लियामेंट, एपीएच पब्लिकेशन, 2002

21. बिकस्टर जे. व इकर्ट सू काउण्टरिंग दि फायनेंस ऑफ टेर्ररिज्म, रूटलज, लंदन, 2008

22. बियान्ज एन्द्रे एनफोरसिंग इंटरनेशनल ला नॉर्म्स अगेंस्ट टेर्ररिज्म, हेस्ट पब्लिकेशन, 2004

23. बिजोरगो टी रूट कॉजेज ऑफ टेर्ररिज्म : मिथ्स रियलिटीज एंड वे फारवर्ड, रूटलज, लंदन, 2005

24. ब्लेग डोनाल्ड — दि ज्योमेट्री ऑफ टेर्ररिज्म, 2004

25. ब्लोमबर्ग, ब्रोक एस. — इकोनोमिक कंडीशंस एंड टेर्ररिज्म, 2004

ग्रेगरीडी व वीराप्ना अकीला

26. बोलिंजर एल. — टेर्ररिज्म कंडक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ ए साइकोलोजिकल प्रोसेस, प्लीनम, न्यूयार्क, 1985

27. बान्ड्यूरेंट जॉन वी. — कन्क्वेस्ट ऑफ वायलेंस : दि गांधीयन फिलोसोफी ऑफ कांफ्लिक्ट, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1988

28. बूथ केन व दूनेटिम — वर्ल्डस इन कोलिजन : टेरर एंड दि फ्यूचर ऑफ ग्लोबल, मेकमिलन, न्यूयार्क, 2002

29. बोरम रेंडी — साइकोलॉजी ऑफ टेर्ररिज्म, साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004

30. बोस सुमंत्रा — कश्मीर रूट्स ऑफ कोन्फिलिक्ट पाटज टू पीस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2003

31.	ब्रेशर माइकल व विल्केनफील्ड जान्थपन	ए स्टडी ऑफ क्राइसिस, मिशिगन यूनिवर्सिटी प्रेस
32.	ब्रियांजर लिया	ग्लोबलाइजेशन एंड दी फ्यूचर ऑफ टेर्ररिज्म पेटनर्स एंड प्रिडिक्शंस, रूटलज, लंदन, 2005
33.	बर्टन जॉन डब्ल्यू	वायलेंस एक्सप्लेन्ड, मेन्चेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, 1997
34.	चेमरन गेविन	मल्टीट्रेक माइक्रो प्रोलिफरेशन : लेशन्स फ्रॉम आम शिंरिक्यो एंड अलकायदा, 1999
35.	चंद्र बी.	इंडिया सीन्स इंडिपेंडेंस, पेगुइन बुक्स, नई दिल्ली, 2000
36.	चंद्र रमेश	ग्लोबल टेर्ररिज्म : फोरेन पॉलिस इन दि न्यू मिलेनियम, कल्पज प्रकाशन, 2003
37.	चंद्र विपिन व अन्य	आजादी के बाद का भारत, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

38. चौधरी शंकरदीप — आई एस आई मूव टू यूनाईट इन दि नॉर्थ ईस्ट, 2002

39. चौहान एस. शारदा — दी अल्कायदा थ्रिट, 2003

40. चुवा एमी — वर्ल्ड ऑन फायर : हाउ एक्सपोरटिंगफ्री मार्केट डेमीक्रेसी बीड्स एथिनिक हेट्रेडएंड ग्लोबक इन्स्टेबिलिटी, एंकर बुक्स, न्यूयार्क, 2003

41. चलार्क रिचर्ड ए. — अगेंस्ट ऑफ एनीमीज, फ्री प्रेस, न्यूयार्क, 2004

42. चोल सेट, रिक व टान वेन्दे करडे — दी इवोल्यूशन ऑफ टेर्ररिज्म इन 2005 : ए स्टेटिकल एक्सेसमेंट, बेल्जियम यूनिवर्सिटी प्रेस, बेल्जियम

43. चोहेन स्टीफेन — अमेरिकाज रोल इन एशिया अमेरिकन व्यू, सेनफ्रांसिस्को, 2004

44. चोबंस सिंडी सी. — टेर्ररिज्म इन 21 सेंचूरी, प्रेन्टिस हाल न्यूजर्सी, 1997

45. चूपर एच एच ए — वाट ईज ए टेर्ररिस्ट : ए साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, 1977

46. चोड्समेन एंथनी — फोरजिंग ए ट्रांसलांटिक स्ट्रेटजी फोर टेर्ररिज्म एंड असाईमेट्रिक वारफेयर, वाशिंगटन डीसी, 2002

47. चोरेडो रेमंड आर. — ए क्रिटिक ऑफ दी मेंटल डिसआर्डर पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल टेर्ररिज्म, 1981

48. च्रेनशा मारथा — टेर्ररिज्म इन कंटेस्ट, पेन्सिलविनिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1995

49. च्रोनिन इशाक — कन्फ्रन्टिंग फीयर : ए हिस्ट्री ऑफ टेर्ररिज्म, थंडर्स माउथ प्रेस, न्यूयार्क, 2002

50. डरेन्ड्रोफ राफ — क्लास एंड क्लास कान्फिलिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसायटी, स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1969

51. डाल्टन डेनिस — महात्मा गाँधी : नोनवायलेंट पावर एक्शन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012

52. डांग सत्यपाल — टेर्रिरिज्म इन पंजाब, ज्ञान पब्लिकेशन, हाउस, नई दिल्ली, 2000

53. डेनियल बेंजामिन व सिमोन स्टीवेन — दि नेक्स्ट अटेक : दि फेलरऑफ दि वार ओन टेरर एंड दि स्ट्रेटजी ऑफ दि वार ओन टेरर एंड दि स्ट्रेटजी फोर गेटिंग इट राइट, टाइम्स बुक, न्यूयार्क, 2005

54. दास निरंजन — टेर्ररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी वर्ल्ड, कलिंग पब्लिकेशन, दिल्ली, 2003

55. दास रतन — गांधीयन 21 सेंचुरी, सरूप एंड संस, नई दिल्ली, 2002

56. दत्ता पी.के. — लेंड रिफार्मेस एडमिनिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल दया पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 1980

57. देसाई जतिन — इंडिया एंड यूएस ऑन टेर्ररिज्म, कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000

58. धर मलोए कृष्णा — ओपन सीक्रेट्स : इंडियाज इंटेलीजेंस अनवील्ड, मानस पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005

59. डिल्लो गुरदसन सिंह — ट्रूथ अबाउट पंजाब, साउथ एशिया बुक्स, 1996

60. डिशमेन क्रिश — टेर्ररिज्म क्राइम एंड ट्रांसफोरमेशन, 2001

61. दीक्षित ज्योति चंद्रनाथ — इंडियाज फोरेन पॉलिसी एंड इट्स नेबर्स, ज्ञान बुक्स, 2001

62. दुबे अभय कुमार — क्रांति का आत्म संघर्ष : नक्सलवादी आंदोलन का बदलता चेहरा, समकालीन प्रकाशन, पटना

63. एस्पोसिटो जॉन एल. — अनहोलीवार : टेरर इन दि नेम ऑफ इस्लाम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002

64. फीयन जेम्स व लेटिन डेविड डी. — एथनीसिटी : इनसरजेंसी एंड सिविल वार, 2003

65. फेन्जीलबर, पेब्लो, लीडरमेन डेनियल व लायजा नार्मन — इन्इक्वेलिटी एंड वायलेंस क्राइम, 2002

66. फर्ग्युसन चार्ल्स डी.पोटर विलियम सी.,एमीसेंड्स स्पेक्टर, लियोनार्ड एस. व व्हेलिंग फ्रेड एल. — दि फोर फेसेज ऑफ न्युक्लियर टेर्ररिज्म रूटलज, न्यूयार्क, 2005

67. फ्रीडमेन लारेंस जेलिक व योनाह एलिक्जेंडर — पर्सपेक्टिव्ज ऑन टेर्ररिज्म, हिन्दुस्तान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 1985

68. गांधी मोहनदास कर्मचन्द — हरिजन

69. गांधी मोहनदास कर्मचन्द — यंग इंडिया

70. गिराल्ड चालियंड — दि हिस्ट्री टेर्ररिज्म : फ्रॉम एन्टीक्विटी टू अलकायदा, केलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007

71. गिराल्ड स्नाइडर, केथरीन बारबरी व निल्स पीटर — ग्लोबलाइजेशन एंड आर्म्ड कान्फिलिक्ट, लनहनरोमेन लिटनफील्ड, 2003

72. घोस एस.के. टेर्ररिज्म वर्ल्ड अंडर सीज, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1995

73. गोपाल कृष्णन ए. इवोल्यूशन ऑफ दि इंडियन न्युक्लियर पावर प्रोग्राम, 2002

74. गोस्वामी नम्रता अ व आउट ऑफ नागा फेक्शनल वायलेंस, 2008

75. ग्रीथी कॉर्नर एसेज ऑन ह्यूमन राइट्स एन्ड टेर्ररिज्म कंपेरेटिव ऐप्रोचेज टू सिविल लिबर्टीज इन एशिया, केमरन, लंदन, 2008

76. गरेवाल गुरूदेव दि सर्चिंग, आई : ऐन एन्साइडर लुक्स ऐट दि पंजाब क्राइसिस, रूपा एंड कंपनी नई दिल्ली, 2006

77. गुहा विश्वजीत कांफ्लिक्ट एंड वायलेंस इन इंडियन सोसायटी, कमुश्का पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1998

78. गुणरत्न रोहन — ग्लोबल नेटवर्क ऑफ टेरर, रोली बुक्स इंडिया, नई दिल्ली, 2002

79. गुप्ता के.आर. — इंटरनेशनल टेर्ररिज्म, एटलांटिक पब्लिकेशन, 2002

80. गुप्ता आर. — ए कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन दि कॉजेज ऑफ टेर्ररिज्म, 1998

81. गुरी नंदीन — न्यू फेस ऑफ टेर्ररिज्म, आई जी ओरजी एंड कंपनी, लंदन, 2002

82. गुर टी.आर. — वाई मेन रिबेल, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूजर्सी, 1970

83. हार्डीमन डेविड — गांधी इन हिज टाईम एंड अवर्स : दि ग्लोबल लीगेसी ऑफ हिज आइडियाज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2003

84. हरमन क्रिस्टोफर सी. — टेर्ररिज्म टूडे, फ्रेंकास पब्लिशर्स, लंदन, 2000

85. हार्वर्ड वीना रानी — गांधी : द महात्मा इवोलविंग नेरेटिव्ज एंड नेटिव डिसकार्स इन गांधी स्टडीज, 2006

86. हीज पीटर — नेशनलिज्म टेर्ररिज्म कम्यूनलिज्म, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000

87. हेडरसन हेरी — ग्लोबल टेर्ररिज्म, जेको पब्लिकेशन, मुंबई, 2003

88. हिंगिस रोजलिन — इंटरनेशनल ला एंड टेर्ररिज्म, 1997

89. होफमेन ब्रुस — दि माइंड ऑफ दि टेर्ररिस्ट पर्सपेक्टिव फ्रॉम सोशल साइकोलोजी, साइशियाट्रिक एन्लस, 1999

90. होफमेन ब्रुस — इन्साइड टेर्ररिज्म, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000

91. होमर डिक्शन थामस — दि राईज ऑफ काम्प्लेक्स टेर्ररिज्म, 2002

92. हबी बुल्लाह वजहत — माइ कश्मीर : कांफ्लिक्ट एंड दि प्रोसपेक्ट्स ऑफ एन्ड्यूरिंग पीस, वंगार्ड बुक्स, 2009

93. हडसन आर. दि सोशयोलोजी एंड साइकोलोजी ऑफ टेर्ररिज्म हू बिकम्स ए टेर्ररिस्ट एंड वाई

94. हटिंग्टन सैमुअल पी. दि क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन्स एंड ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, सिमोन एंड श्यूसटर, 1996

95. हुसैन तकीर यू एस पाकिस्तान एंगेजमेंट : दि वार ऑन टेर्ररिज्म एंड बेयंड वाशिंगटन डीसी, 2005

96. हुसैन वशबीर मणिपूरर्स रिबेल्स : चाइल्डस प्ले, 2008

97. हुसैन कबीर इन्सरजेंसी इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट क्रॉस बॉर्डर लिंक्स एंड स्ट्रेटजिक एलायन्सेज, फॉल्ट लाइन पब्लिकेशन, 2010

98. जागराइवस्की सरजी रिफ्लेक्शन्स ऑन ह्यूमन एंड ह्यूमेनिटी

99. जैन शारदा पॉलिटक्स ऑफ टेर्ररिज्म इन इंडिया केस ऑफ पंजाब, दीप एंड दीप, नई दिल्ली, 1995

100. जयशंकर कार्तिक — कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एंटी टेर्ररिस्ट लॉज, आर्थर, नई दिल्ली, 2002

101. झा प्रेमशंकर — दि जिनीसिस ऑफ टेरर, 2003

102. जोशी मनोज — दि लोस्ट रिबेलियन, पेंगुइन बुक्स, 1999

103. जग मोहन — शेपिंग इंडियाज न्यू डेस्टिनी, अलाइड पब्लिशर्स, 2009

104. जग मोहन — माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, अलाइड पब्लिशर्स, 2006

105. जुरगेन्समेशर मार्क — टेरर इन दि माइंड ऑफ गॉड दि ग्लोबल राईज ऑफ रिलिजियस वायलेंस केलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001

106. केमरन गोविन — न्युक्लियर टेर्ररिज्म, मोतीबाग प्लेस पटियाला, 1999

107. कनवाल गुरमीत — इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी पूअर मेनेजमेंट इन एवीडेंस, 2007

108. करीम अफसर — काउन्टर टेर्ररिज्म : दि पाकिस्तान फेक्टर, लांसर इन्टरनेशनल, नई दिल्ली, 1991

109. कटारिया आर.पी. व खुर्शीद नकवी — लॉज ऑन प्रिवेंशन ऑफ टेर्ररिज्म एंड अनलाफुल एक्टीविटिज, ओरियंट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 2003

110. किग्ले चार्ल्स डब्लयू — इंटरनेशनल टेर्ररिज्म : केरेक्टरिस्टिक्स कोजेज कंट्रोल, सेंट मार्टिन, प्रेस न्यूयार्क, 1990

111. केटिल वोलडन व डेन स्मिथ — कोजेज ऑफ कांफिलिक्ट इन दि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, 1997

112. खान अली — ए लीगल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल टेर्ररिज्म, 1987

113. खान जलिल अहमद व सुधीर एस — डाइंग टेर्ररिस्ट, मानस पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003

114. खुर्शीद नकवी — बेयंड टेर्ररिज्म न्यू होप फोर कश्मीर, यूएसजी पब्लिकेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, 1994

115. किमेल माइकल एस. — ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स कंटेन्ट्स : दि जेन्डर्ड मोरल एंड पॉलिटिकल इकॉनोमी ऑफ टेर्ररिज्म, 2003

116. कूली जोन के. — अनहोलीवार : अफगानिस्तान अमरीका एंड इंटरनेशनल, परग्यून्न, दिल्ली

117. क्रोनस्टेल्ड एलन के.व वॉगन ब्रुस — टेर्ररिज्म इन साउथ एशिया वाशिंगटन डीसी, 2004

118. क्रूजर ए. व मेलेकोवा जे. — एजूकेशन पावर्टी एंड टेर्ररिज्म, ईज देहर ए कोजल कनेक्शन, 2003

119. कुमार आनंद — एक्सटरनल इंफ्लूऐन्सेज ऑन दि नार्थ ईस्ट इन्सरजेंसी

120. कुमार आनन्द — भूटान्ज ओफेंसिव अंगेस्ट दि टेर्ररिस्ट, 2003

121. कुमार अशोक — टेर्ररिज्म एंड ह्यूमन राईट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओम पब्लिकेशन, 2007

122. खुशनर एच. डब्ल्यू. एसेंसियल रीडिंग्स ओन पोलिटिकल टेर्ररिज्म : एनालिसेज ऑफ प्रोब्लम्स एंड प्रोसपेक्ट्स फोर दि 21 सेंचूरी, 2002

123. लाहिरी के प्रतीप भारत में सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद

124. लेसरलेन व अर्स काउंटरिंग दि न्यू टेरर, एंड पब्लिकेशन, 2008

125. लेवी ए. माइकल ऑन न्युक्लियर टेर्ररिज्म, 2007

126. लॉकर वाल्टर दि न्यु टेर्ररिज्म, ऑक्सफोर्ड यूनिविर्सिटी प्रेस, 1999

127. लॉकर वाल्टर ओरिजन्स ऑफ टेर्ररिज्म, दि वुडरो विल्सन सेंटर प्रेस, 1998

128. लॉकर वाल्टर दि ऐज ऑफ टेर्ररिज्म, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002

129. लोरई हिमांशु — ग्लोबल पावर्टी टेर्ररिज्म एंड पीस, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005

130. मेकिनले जान — ग्लोबलाइजेशन एंड इन्सरजेंसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002

131. मलिक ओमर — इनफ ऑफ दि डिफिनेशन ऑफ टेर्ररिज्म, बुकिंग प्रेस, 2001

132. मलिक एस व गौड़ एस. एन. — एन्साइक्लोपीडिया ऑफ टेर्ररिज्म ला पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, 1993

133. मलिक एस.के. — दि क्यूरेनिक कंसेप्ट ऑफ वार, वाजिडेलिस, लाहौर, 1979

134. मलिक वी.पी. — इंटरनल सिक्योरिटी मेनेजमेंट चेलेंजेज एंड पॉलिसी ऑपशन्स

135. मंगलानी डॉ. रूपा — भारतीय शासन व राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2009

136. मारगेट हरमन — हेंड बुक ऑफ पोलिटिकल साइकोलोजी, सेनफ्रांसिस्को, 1985

137. मारवाह वेद — अनसिविल वार्स पेथेलोजी ऑफ टेर्ररिज्म इन इंडिया, नई दिल्ली, 2007

138. मैयर सुरेश — दि रूट कोजेज ऑफ टेर्ररिज्म इन इंडिया

139. मीड वाल्टर रसेल — पावर टेरर पीस एंड वार : अमेरिकाज ग्रांड स्ट्रेटजी इन ए वर्ल्ड एट रिस्क, अल्फ्रेड नोफ, न्यूयार्क, 2004

140. मेहता आर.एस. — इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टेर्ररिज्म ला, पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली, 2007

141. मर्बल पीटर एच. — पोलिटिकल वायलेंस एंड टेरर : मोटिव्ज एंड मोटिवेशन, केलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1986

142. मर्टन रोबर्ट के. — सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, दि फ्री प्रेस, न्यूयार्क, 1968

143. माइकल जे.नोजेम — गांधी एंड किंग : दि पावर ऑफनोनवायलेंट रेजिस्टेंस, प्रियगर वेस्टपोर्ट, 2004

144. मिलर डायना — टेर्ररिज्म : आर वी रेडी, नोवा साइंस पब्लिशर्स, 2002

145. मिल्स सी. राइट — दि कोजेज ऑफ वर्ल्ड वार थ्री, सेकर एंड वारबर्ग, लंदन, 1959

146. मिश्रा गोविन्द — एंड अमेरिका अटेक्ड : मास्टर ऑफ टेर्ररिज्म इन 21 सेंचुरी, 2002

147. मिश्रा आर.पी. व केंडीकनग्रोड — गांधीयन अल्टरनेटिव, कंसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली 2005

148. मिश्रा त्रिनाथ — बेरल ऑफ दि गन : दि माओइस्ट चेलेंज एंड इंडियन डेमोक्रेसी, श्रीधन बुक कंपनी, नई दिल्ली

149. मूरी लुईस — रिस्क एंड दि वार ओन टेरर, रोटलेस, लंदन, 2008

150. मुखर्जी अप्रतिम — आक्रोश, 1998

151. मुखर्जी कल्याण व सिंह राजेन्द्र — नक्सलिज्म इन दि प्लेन्स ऑफ बिहार, राधा कृष्णा पब्लिकेशन, 1980

152. मुशरिफ एस.एम. — हू किल्ड करकरे : दि रियल फेस ऑफ टेर्ररिज्म इन इंडिया, फेरोज मीडिया पब्लिशिंग, 2009

153. नेकोस ब्रीगीटे — मास मिडियाटेड टेर्ररिज्म : दि सेंट्रल रोल ऑफ दि मीडिया इन टेर्ररिज्म एंड काउन्टर टेर्ररिज्म, मेरीलेंड रोमन एंड लिटल फील्ड, 2002

154. नाग सजल — फंडिंग दि स्ट्रगल : पोलिटिकल इकोनोमी ऑफ इंमरजेंसी, मानस पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008

155. नेपोलिओनी लोरेटो — मॉडर्न जिहाद : ट्रेसिंग दि डॉलर्स बिहाइंड दि टेरर नेटवर्क, प्लूटो प्रेस, लंदन, 2003

156. नेतान्याहू बेंजामिन — फाइटिंग टेर्ररिज्म, फेनर स्टोज एंड जेरोक्स पब्लिशर्स, 2001

157. ओटोकेन जेनिफर — काउंटर इंसरजेंसी अगेंस्ट नक्सलाइट्स इन इंडिया, रूटलज प्रकाशन, 2009

158. ओलिविरियो, एनामेरी व पेट लांडरडेल — दि स्टेट ऑफ टेरर, न्यूयार्क यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1998

159. परेल एंथनी — फ्रीडम एंड सेल्फ रूल, लेक्जिगटन बुक, 2000

160. परेल एंथनी — गांधीज फिलोसोफी एंड दि क्वेस्ट फोर हारमनी, केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006

161. पाटिल वी.टी. — न्यू फेस ऑफ टेर्ररिज्म, लांसर पब्लिकेशन, दिल्ली, 2008

162. फिलीपोंज सुधरी — ओपरेशन राइटियान माइट : ह्यूमन राइट्स एंड आर्म्ड फोर्सेज, आर्थर, नई दिल्ली, 2004

163. पिलर पाल आर. टेर्ररिज्म एंड यू एस फोरेन पोलिसी, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन प्रेस, वाशिंगटन डीसी, 2001

164. पोस्ट जे. नोट्स ओन ए साइकोडाइनेमिक थ्योरी ऑफ टेर्ररिस्ट बिहेवियर, 1985

165. पूनियानी राम टेर्ररिज्म : फेक्ट्स वर्सेज मिथ्स, फरोज मीडिया पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2007

166. रहमान मिर्जा जुल्फीकार इंसरजेंसीज स्पिलट्स टेरर, 2009

167. राय अरूंधती गांधी बट विद गंस, 2010

168. राज चेंगपा वेपंस ऑफ पीस, हार्पर कालिंस, नई दिल्ली, 2000

169. रमन पी.वी. माओइस्ट अटेक ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, 2009

170. राना मोहम्मद आमिर गेट वे टू टेर्ररिज्म, मिलेनियम, लंदन, 2003

171. राउक अरविंद नक्सली आतंकवाद, ईस्ट वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास, 1996

172. रेपोपार्ट डेविड सी. असाइनेशन एंड टेर्ररिज्म, टोरंटो, 1971

173. रेपोपार्ट डेविड सी व एलिक्जेंडर वाई. दि रेसनलाइजेशन ऑफ टेर्ररिज्म, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ऑफ अमरीका, 1982

174. राशि अहमद जिहाद, ओरियंट लोंगमन, हैदराबाद, 2004

175. रेड्डी एल.आर. बायो टेर्ररिज्म, एपीएच पब्लिशिंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली, 2002

176. रिच वाल्टर ओरिजंस ऑफ टेर्ररिज्म : साइकोलोजी, आइडियोलोजी स्टेट ऑफ माइंड, वुडरो विल्सन सेंट्रल प्रेस, वाशिंगटनडीसी, 1990

177. राईस सूजान ई. ग्लोबल पावर्टी : वीक स्टेट्ज एंड इंसिक्योरिटी

178. रोजेमबर्ग ए.एच.टी.ओ. टेरर फोर्स एंड वर्ल्ड, पाथक्रोम मॉर्डनिटी, एडवर्ड एल्गर, यू.के., 1994

179. रोस जे.आई. स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ अपोजिशनल पोलिटिकल टेर्ररिज्म टूवार्डस ए कोजल मॉडल, 1993

180. रूबेंस्टीन रिचर्ड ई. अल्केमिस्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन : टेर्रिरिज्म इन दि मोडर्न वर्ल्ड, बेसिक, न्यूयार्क, 1987

181. सबरवाल ओ.पी. किलिंग इंसटिक्स, रूपा एंड कंपनी, नई दिल्ली, 2000

182. सेगमेन एम. अंडरस्टेंडिंग टेरर नेटवर्क फिलाडेल्फिया, 2004

183. सेकिया जयदीप दि आई.एस.आई. रिचेज ईस्ट : एनाटोमी ऑफ ए कंसपायरेसी, रूटलज, 2002

184. सेकिया प्रदीप नोर्थ ईस्ट इंडिया ऐज ए फेक्टर इन इंडियाज डिप्लोमेटिक एंगेगमेंट विद म्यांमार : ईसूज एंड चेलेंजेज, नई दिल्ली, 2009

185. सेलिवस्की वोल्फगेंग डी. दि लेटेस्ट थ्योरी रिकागनाइज्ड बाई सोशयोलोजिकल, 1980

186. सेमिउद्दीन आबिदा — दि पंजाब क्राइसिस : चेलेंज एंड रेस्पोंस, मित्तल पब्लिकेशन, दिल्ली, 1985

187. सत्पाठी जी.सी. — बायोलोजिकल वेपंस एंड टेर्ररिज्म, कल्पज पब्लिकशन, दिल्ली, 2004

188. सक्सेना एन.एस. — टेर्ररिज्म : हिस्ट्री एंड फेस इन दि वर्ल्ड एंड इन इंडिया, बभिनय, नई दिल्ली, 1985

189. सहगल बी.पी. — ग्लोबल टेर्ररिज्म : सोशियो पोलिटिक एंड लीगल डायमेंशन, दीप एंड दीप, नई दिल्ली, 1995

190. सेनगुप्ता दीपांकर व सिंह सुधीर कुमार — इंसरजेंसी इन नोर्थ ईस्ट इंडिया : दि रोल ऑफ बांग्लादेश, आथर्स प्रेस, नई दिल्ली, 2004

191. सेन, एम. — दि नक्सलिस्ट्स एंड नक्सलिज्म, 1971

192. सेन शंकर — टेर्ररिज्म एंड ड्रग्स, एस.सी. सरकार, कलकत्ता, 1994

193. शाह जी.पी. — न्यू टेर्ररिज्म : इस्लामिस्ट इंटरनेशनल एपीएच पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005

194. शारदा डी.पी. काउंटिंग टेर्ररिज्म, लांसर इंटरनेशनल, नई दिल्ली, 1992

195. शर्मा डी.पी. न्यू टेर्ररिज्म : इस्लामिस्ट इंटरनेशनल, 2005

196. शर्मा, डॉ0 सजीव कुमार कम्युनिकेशन मीडिया ग्लोबलाइजेशन एंड टेर्ररिज्म इन इंडिया, 2006

197. शर्मा करूणा 9/11 ओन फायर, 2003

198. सिल्के ए. टेर्ररिस्ट्स विक्टिमस एंड सोसायटी : साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिव्ज ओन टेर्ररिज्म एंड इट्स कोसीक्वेंसेज, जोनविले एंड संस लिमिटेड, इंग्लेंड, 2003

199. सिमोन जेफरी डी. टेर्ररिस्ट ट्रेप, इंडिरून यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001

200. सिंह, अजीत वर्ल्ड टेर्ररिज्म टुडे, बुक एन्कलेव, जयपुर, 2002

201. सिंह डॉ., रामजी गांधी दर्शन मीमांसा

202. सिंह गुरमीत — हिस्ट्री ऑफ सिख स्ट्रगल्स, साउथ एशिया बुक्स, नई दिल्ली, 1989

203. सिंह जोगिंदर — आतंकवाद का बदलता स्वरूप

204. सिंह महावीर — इंटरनेशनल टेर्ररिज्म एंड रिलिजियस एक्सट्रीक्स, मकायाज, नई दिल्ली, 2002

205. सिंह नरेन्द्र — प्राइवेट आर्मीज इन बिहार, वाणी पब्लिकेशन, 2010

206. सिंह प्रकाश — दि नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया, रूपा एंड कंपनी, 1996

207. सिंह प्रकाश — कोहिमा टू कश्मीर, रूपा एंड कंपनी, नई दिल्ली, 2001

208. सिंह रामनरेश प्रसाद — आई.एस.आई. का आतंक

209. सिंह सुधीर कुमार — टेर्ररिज्म ए ग्लोबल फिनोमिना, आथर्स प्रेस, दिल्ली, 2000

210. सिंह सूरत व सिंह हेमराज — ला रिलेटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेर्ररिज्म, यूनिवर्सल ला पब्लिकेशन

211. सिंह सुरंद — फाइटिंग दि न्यू एविल वार ऑफ टेर्ररिज्म, त्रिकुटा रेडियंट पब्लिकेशन, जम्मू

212. सिंह उज्जवल कुमार — स्टेट डेमोक्रेसी एंड एंटी टेरर लोज इन इंडिया, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2007

213. सिवाक मंजरिका — कांफिलिक्ट्स एंड पीस प्रोसेस, मनोहर प्रकाशन, 2006

214. स्मिथ जेम्स एम. व स्मिथ विलियम सी. — दि टेर्ररिज्म थ्रेट एंड यू एस गवर्नमेंट रेस्पोंसेज ओपरेशनल एंड ओर्गेनाइजेशनल फेक्टर्स, कोलाराडो, 2001

215. स्मिथ पोल जे. — टेर्ररिज्म एंड वायलेंस इन साउथ एशिया, पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली, 2005

216. स्मूकर फिलिप — अलकायदाज ग्रेट एस्केप, मानस पब्लिकेश, नई दिल्ली, 2005

217. सोनल आशीष — टेर्ररिज्म एंड इंसरजेंसी इन इंडिया, लांसर इंटरनेशनल, नई दिल्ली, 1994

218. श्रीवास्तव देवयानी — टेर्ररिज्म एंड आर्म्ड वायलेंस इन इंडिया, 2009

219. स्टर्ड जेसिका कालिंस — टेरर इन दि नेम ऑफ गोड, हार्पर न्यूयार्क, 2003

220. स्टर्न जेसिका — दि अलीमेट टेर्ररिस्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999

221. स्टोंब टालबोट व चंदा नयन — दि ऐज ऑफ टेरर : अमरीका एंड वर्ल्ड ऑफ्टर सेप्टेंबर 11, बेसिक बुक्स, 2001

222. सुब्रमण्यम राजू — टेर्ररिज्म इन साउथ एशिया : व्यूज फ्रोम इंडिया, 2004

223. सुब्रमण्यम राजू व पोंकलन एस.आई.कीथा — मेरीटाइम कोपरेशन बिटविन इंडिया एंड श्रीलंका, मनोहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2008

224. सुरोनेनी इंद्रा — गांधीयन डोक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, साउथ एशिया बुक्स, नई दिल्ली, 1991

225. टेलिस ऐशले जे. ए न्यू यू.एस. पोलिसी ओन दि सबकोंटिनेंट, वाशिंगटन डीसी, 2005

226. त्रिवेदी डॉ. आर.एन.व राय डॉ. एम.पी. भारतीय सरकार व राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

227. टर्नर स्टेंसफील्ड टेर्ररिज्म एंड डेमोक्रेसी, बोस्टन

228. उर्मिलेश बिहार का सच, प्रकाशन संस्थान, दिल्ली, 1998

229. वेद प्रकाश टेर्ररिज्म इन इंडियाज नोर्थ ईस्ट : ए गेदरिंग स्टोर्म, कल्पज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008

230. वीनर मायरन पोलिटिक्स ऑफ स्केरसिटी, 1968

231. वर्गीज बी.जी. इंडियाज नोर्थ ईस्ट रिसरजेंट, कोणार्क पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2002

232. विशाल थापर एमो फायर्स नोट क्वाईट एक्सीडेंटल, 2001

233. व्यास वेद टेर्ररिज्म इन नदर्न इंडिया : जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, 2008

234. वालपर्ट स्टेनली — इंडिया एंड पाकिस्तान : कंटीन्यूड कांफ्लिक्ट एंड कोपरेशन, केलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2010

235. वीटकर डी. — टेर्ररिस्ट्स एंड टेर्ररिज्म इन दि कंटेंपरेरी वर्ल्ड, रूटलज टेलर व फ्रांसिस ग्रुप, लंदन व न्यूयार्क, 2004

236. विर्वका माइकल — दि मेकिंग ऑफ टेर्ररिज्म, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, शिकागो, 1993

237. विलकिंसन पी. — टेर्ररिज्म एंड दि लिबरल स्टेट, न्यूयार्क, यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1986

238. विलकिंसन पी. — टेर्ररिज्म वर्सेज डेमोक्रेसी : दि लिबरल स्टेट रेस्पोंस, फ्रेंकास, लंदन, 2001

239. जाक्सा जोहानी व महाबुल बी.के. — ट्राईब्स एंड नक्सलिज्म, सोशल एक्शन, 2010

240. योनाह एलिक्जेंडर — कोमबेटिंग टेर्ररिज्म : स्ट्रेटनिज ऑफ टेन कंट्रीज, मनन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003

241. योनाह एलिक्जेंडर यूनाइटेड किंगडम्स लीगल रेस्पोंसेज टू टेर्ररिज्म, केवेंडिश पब्लिकेशन, लंदन, 2003

शोध पत्रिकायें व संदर्भ पत्रिकायें

1. ओडिश रिव्यू

2. अमरीकन पोलिटिकल साइंस रिव्यू

3. दैनिक भास्कर

4. दैनिक नवज्योति

5. फ्रंटलाइन

6. हिंदु

7. हिंदुस्तान टाइम्स

8. इंडिया टुडे

9. लीगल मेडिकल क्वार्टली

10. आउटलुक

11. आउटलुक इंडिया

12. पोलिटिकल क्वार्टली

13. प्रतियोगिता दर्पण

14. प्रतियोगिता साहित्य

15. प्रतियोगिता दृष्टि

16. राजस्थान पत्रिका

17. सहारा समय

18. थर्ड वर्ल्ड क्वार्टली

19. टाइम्स ऑफ इंडिया

20. वाशिंगटन क्वार्टली

21. वाशिंगटन पोस्ट